HVS/Lib/12
2-8-96

# हरियाणा विधान सभा

की

# कार्यवाही

23 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

## विषय सूची

वीरवार, 23 मार्च, 1995


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि | (12)1 |
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (12)1 |
| ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनायें | (12)26 |
| ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— | |
| थर्मल पावर प्लांट पानीपत के गन्दे पानी तथा राख के कारण प्रदूषण से बीमारियां फैलने सम्बन्धी | (12)28 |
| वक्तव्य— | |
| वन मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी | (12)28 |
| समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना— | |
| (i) लोक-लेखा समिति | (12)35 |
| (ii) आश्वासन समिति | (12)36 |
| (iii) अनुसूचित जातियों तथा जनजाति कल्याण समिति | (12)36 |
| (iv) प्राक्कलन समिति | (12)36 |
| वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान | (12)36 |


मूल्य :

| | |
|---|---|
| वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (11)97 |
| सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन | (11)114 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (11)118 |
| सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन (पुनरारम्भ) | (11)118 |
| वाक आउट | (11)119 |
| सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन (पुनरारम्भ) | (11)120 |
| वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (11)120 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (11)126 |
| वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (11)126 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (11)129 |
| वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (11)129 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (11)131 |
| वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (11)131 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (11)131 |
| वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (11)131 |

# हरियाणा विधान सभा

बीरवार 23 मार्च, 1995 ]

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की ।

---

## शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members now the Chief Minister will move a resolution.

**मुख्य मंत्री** (चौ० भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सारा देश ऐसे तीन महान सपूतों, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मना रहा है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आज ही के दिन 23 मार्च, 1931 को लाहौर सैन्ट्रल जेल में हंसते-हंसते फांसी के फन्दे को चूमा था ।

इन तीनों महान् देश-भक्तों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने वीरतापूर्ण कार्यों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिलाकर रख दी थी ।

अंग्रेज सरकार इन युवा देश-भक्तों एवं क्रांतिकारियों से इतना अधिक खौफ खाती थी कि जन-आक्रोश के डर से, उसने भारत माता के इन तीनों महान सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निश्चित तिथि से पूर्व ही, चुप-चाप 23 मार्च, 1931 की शाम को फांसी दे दी । ऐसा करके अंग्रेज सरकार ने न केवल अपनी कायरता का परिचय दिया, बल्कि देश के लाखों नर-नारियों को इन महान युवा देश-भक्तों के अंतिम दर्शनों से भी वंचित कर दिया था ।

इन क्रांतिकारी देश-भक्तों तथा अन्य लाखों देश-प्रेमी सपूतों की कुर्बानियों का ही यह नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सुख की सांस ले रहे हैं ।

यह सदन भारत माता के इन तीनों महान सपूतों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और उन सारे शहीदों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहूति दी, को आज शहीदी दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।

[चौधरी भजन लाल]

देश प्रेम के लिए इन महान सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान की कहानी हमें हमेशा राष्ट्र-प्रेम तथा देश के नव-निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी । इसी संकल्प के साथ हम एक बार फिर इन महान सपूतों को याद करते हुए नतमस्तक होकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आमरेबल मैम्बर्ज, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए शहादत दी है । उस वक्त एक नरम दल था और एक गरम दल था । गरम दल में लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल आदि नेता थे जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे इसके अलावा हमारे कुछ नौजवान भी जैसे चन्द्र शेखर आजाद वगैरह ने भी अपनी शहादत दी । ये लोग अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देना चाहते थे ताकि उनके कानों तक यह आवाज जाए कि देश में अंग्रेज जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है और वे देश के हितों के खिलाफ चल रहे हैं । इस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी । वे बहुत ही बहादुर थे और उनमें किसी भी किस्म का डर नहीं था, वे देश प्रेम से ओत प्रोत थे । अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी देकर रातों रात सतलुज नदी के किनारे उनकी लाशें जलायीं । इनके सारे अंश हैं । लाशें जलाने के बाद उनको उन्होंने दरिया में बहा दिया लेकिन फिर भी रातों रात ही बहुत से लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए क्योंकि उनको इस बात का पता लग गया था तो इस तरह से ये लोग शहीद हो गए और इस तरह उन्होंने देश प्रेम की एक मशाल जलायी । उन्हें ऐसा करते देखते हुए देश के और नौजवानों में भी एक हौंसला पैदा हुआ और उसी के फलस्वरूप यह देश आजाद हुआ, जिसकी वजह से आज यह तरक्की हमारे सामने हुई है ।

अब मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया ।)

---

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आमरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे ।

**Construction of New Roads**

*1102. @Shri Dhir Pal Singh: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the total amount spent on the construction of new roads/repair of roads in Jhajjar and Bahadurgarh Sub-Divisions during the period from June, 1991 to December, 1994 yearwise separately ?

@Put by Sh. Satbir Singh Kadyan

**Public Works Minister** (Shri Amar Singh) : The expenditure details are as under :—

| Sr. No. | Particulars | June 91 to March, 92 (Rs. Lacs) | Year 92-93 (Rs. Lacs) | Year 93-94 (Rs. Lacs) | April, 1994 to Dec., 94 (Rs. Lacs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | On construction of new roads | 45.92 | 22.34 | 17.61 | 20.86 |
| 2. | On repair of roads | 188.13 | 94.05 | 149.18 | 110.31 |

श्री सतबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जी जानना चाहता हूं कि 1991-92 के बाद से लगातार बजट में यह घटौती क्यों आई । जैसे नए रोड बनाने पर 1991-92 में 45.92 लाख है और 1993-94 में 17.61 लाख है, इसी तरह रिपेयर पर 1991-92 में 188.13 लाख है और 1994 में 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपया है । सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं । ऐसा लगता है कि मंत्री जी यह समझते हैं कि सारी सड़कें बड़ी सुन्दर हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें और पैसा बढ़ाने का प्रावधान करेंगे ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कारण है जिनके तहत कम बजट खर्च किया गया ?

**श्री अमर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रान्त ही ऐसा प्रान्त है जिसमें टोटल भांव रोड्स से जुड़े हुए हैं । हरियाणा में टोटल रोड्ज 21579 किलोमीटर हैं जिसमें से 3135 किलोमीटर स्टेट हाइवे हैं और मेजर रोड्ज 1587 किलोमीटर हैं और रूरल रोड्ज 16857 किलोमीटर हैं । जहां तक नयी रोड्ज की कंस्ट्रक्शन और रिपेयर पर कम पैसा खर्च करने की बात है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब हम नई रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें पहले साल में अर्थ वर्क, सोलिंग वगैरह होती है, उसमें खर्च अधिक आता है । वर्ष 1991-92 में रोड्ज की रिपेयर पर 1 करोड़ 88 लाख 13 हजार रुपया खर्च किया । उसके बाद साल दो साल रोड चलती रही । उसके बाद इस बार हमने रिपेयर पर 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपया खर्च किया है । सारे हरियाणा में सड़कों का पैचवर्क हुआ है जो 313 किलोमीटर रोड हैवी रेन्ज और फ्लड से टूटी थी, उनको ठीक कर दिया गया है । अब ऐसी कोई रोड नहीं है जो बननी हो ।

**श्री सतबीर सिंह कादियान** : स्पीकर सर, जैसाकि कल माननीय सदस्य श्री सूरज मल जी ने बताया था कि उनका हल्का दिल्ली के साथ लगता है और दिल्ली के मुकाबले हरियाणा की सड़क देखें तो हमें शर्म आती है । सड़कें टूटी पड़ी हैं, आखिर रोहतक जिले के साथ यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं ? वर्ष 1991–92 का बजट हमारी सरकार ने पास किया था, उसके बाद इनकी सरकार आ गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भेदभाव की नीति की वजह से रोहतक जिले में सड़कों की रिपेयर और बनाने पर कम खर्च नहीं कर रहे हैं ?

**श्री अमर सिंह** : स्पीकर सर, अगर यह बात कोई और भाई बोले तो जच सकती है । इन्होंने तो अपने पौने चार साल के शासन काल में एक ईंट भी नहीं लगाई । कोई रोड बता दें जो इन्होंने बनवाई हो । जो फ्लडिड एरियाज हैं उनमें रोड टूट जाती हैं जिनकी वजह से काफी नुक्सान होता है । स्पीकर साहब, शायद इन्होंने हमारे जवाब को पढ़ा नहीं है । हमने हर साल रिपेयरिंग पर ज्यादा खर्चा दिखलाया है । वह 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार है, जोकि अप्रैल, 1994 से दिसम्बर 1994 तक का है ।

**चौधरी ओम प्रकाश बेरी** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने झज्जर और बहादुरगढ़ सब-डिवीजन्स में रोडज की रिपेयर का और नई सड़कें बनाने का इकट्ठा ही जवाब दे दिया है । इसलिये वे बताएं कि झज्जर सब डिवीजन में रोडज की रिपेयरिंग व नई रोडज बनाने के लिये और बहादुरगढ़ सब-डिवीजन में रोडज की रिपेयरिंग व नई रोडज बनाने के लिये सरकार ने कितना-कितना पैसा खर्च किया है । यह अलग से बताएं । इसके साथ साथ मैं इनको झज्जर सब-डिवीजन की कुछ सड़कों के नाम बताता हूं जो बिल्कुल टूटी हुई हैं, जैसे झज्जर से बेरी, झज्जर से गुढियानी, झज्जर से साहलावास, झज्जर से सांपला वगैरह, और भी कई सड़कें इस तरह की हैं जोकि बिल्कुल चलने के काबिल नहीं हैं । कहीं यह बात तो नहीं है कि सड़कों की रिपेयरिंग केवल कागजों में ही कर ली गई दिखाई हो और ऐक्चूअल वर्क कोई न किया गया हो । मन्त्री महोदय बेशक मौके पर मेरे साथ चल कर देख लें कि कहीं रिपेयर वर्क हुआ भी है या नहीं । मैं इनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं । इसलिये पुनः बताएं कि बहादुरगढ़ सब डिवीजन व झज्जर सब-डिवीजन में सड़कों की रिपेयर की व नई सड़कों की अब क्या हालत है ?

**श्री अमर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मेरे आदरणीय सदस्य ने जो नई सड़कों के निर्माण पर जो खर्चा हुआ है, उसके बारे में पूछा है, वह मैं बता देता हूं । 1991–92 में झज्जर सब डिवीजन में नई सड़कों का निर्माण हुआ 3.55 किलोमीटर, सोलिंग की गई 8.85 किलोमीटर, मैटलिंग की गई 6.55 किलोमीटर । बहादुरगढ़ सब-डिवीजन में 1991–92 में 2.49 किलोमीटर अर्थ वर्क, 7.69 किलोमीटर सोलिंग और मैटलिंग की गई 6.57 किलोमीटर । टोटल इन पर खर्चा आया 45.92 लाख रुपये । इसी तरह से वर्ष 4/92 से 3/93 तक

बहादुरगढ़ सब-डिवीजन में 0.17 किलोमीटर अर्थ वर्क, 1.83 किलोमीटर सोलिंग और मैटलिंग की गई 3.58 किलोमीटर । झज्जर सब-डिवीजन में केवल मैटलिंग वर्क हुआ 2.12 किलोमीटर इस पर खर्चा आया 22.34 लाख रुपये । इसी तरह से 4/93 से 3/94 तक झज्जर सब-डिवीजन में अर्थ वर्क और सोलिंग 0.20 किलोमीटर की गई । मैटलिंग हुई 0.20 किलोमीटर और बहादुरगढ़ सब-डिवीजन में 0.11 किलोमीटर में अर्थ वर्क, 0.36 किलोमीटर में सोलिंग और 0.36 किलोमीटर में मैटलिंग का कार्य हुआ जिसका खर्चा आया 1.61 लाख रुपये । इससे आगे मैं 4/94 से 12/94 तक की पोजीशन बताता हूं । झज्जर सब-डिवीजन में 0.65 किलोमीटर अर्थ-वर्क, 0.25 किलो मीटर सोलिंग और 0.25 किलो मीटर मैटलिंग वर्क हुआ और बहादुरगढ़ सब-डिवीजन में 1.75 किलोमीटर अर्थ-वर्क हुआ इस काम पर 20.86 लाख रुपये खर्चा बैठता है ।

इसी तरह से मैन्टीनैन्स/रिपेयर वर्क की ईयर-वाईज फिगर्ज इस प्रकार है :—

जून 1991 से मार्च, 1992 तक पैच वर्क पर 18.22 लाख रुपए, रिन्यूअल कोट और सरफेसिंग पर 27.52 लाख रुपए, स्पैशल रिपेयर पर 86.70 लाख रुपए, मिसलेनियस पर 55.69 लाख रुपए, टोटल 1 करोड़ 88 लाख 13 हजार रुपये खर्च आया । 1992–93 में पैच वर्क पर 33.26 लाख रुपए रिन्यूअल कोट और सरफेसिंग पर 36.13 लाख रुपए, स्पैशल रिपेयर पर 21.92 लाख रुपए, मिसलेनियस 2.74 लाख रुपये, टोटल 94.05 लाख रुपये खर्च हुए । 1993–94 में पैच वर्क पर 40.94 लाख रुपए, रिन्यूअल कोट पर 28.08 लाख रुपए स्पैशल रिपेयर पर 10.78 लाख रुपए और मिसलेनियस पर 69.38 लाख रुपए टोटल 149.18 लाख रुपये खर्च हुए । इसी तरह से अप्रैल 1994 से दिसम्बर, 1994 तक पैच वर्क पर 27.17 लाख रुपए, रिन्यूअल कोट पर 37.47 लाख रुपए, स्पैशल रिपेयर पर 27.03 लाख रुपए, मिसलेनियस पर 18.64 लाख रुपए इस पर टोटल 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपये खर्च हुए । इस तरह से यह अलग–अलग पोजीशन झज्जर सब-डिवीजन व बहादुरगढ़ सब-डिवीजन की जो नई सड़कों की थी और दूसरी मुरम्मत की थी, वह मैंने बता दी है । जहां तक बादली, छारा व बेरी की सड़कों का सवाल है, आनरेबल मैम्बर ने गांव दुबलधन के बारे में बताया है कि वे वहां पर कच्ची नाली है, उस पर बन्द लगा दिया गया है, आनरेबल मैम्बर उसको खुलवा दें तो रोडज ठीक हो जाएंगी । इसी तरह से छारा में इन्होंने पांच सौ मीटर नाली बन्द कर दी और गांव के लोगों ने उसे खोलने नहीं दिया । वहां पर हमारे एस० ई० कल गए थे । उन्होंने कहा कि यह रोड टूट रही है, आप पानी को निकलने दें लेकिन वे लोग लट्ठ ले कर खड़े हो गए । इसी तरह से हमारे भाई वीर पाल सिंह जी के बादली हल्के में 15 मीटर नाली पर कलवर्ट लगा रखा है । तो ये खुद तो रोड को तोड़ने की बात करते हैं ।

**चौधरी सूरज मल** : स्पीकर साहब, यहां पर बादली की रोडज का जिक्र आया है । चौधरी अमर सिंह ने बताया कि बहादुरगढ़ हल्के के अन्दर सड़कों का काम शुरू कर दिया है । लूनामाजरा से कसार नेशनल हाई-वे पर एक सड़क बनी थी । उस पर केवल तीन इंच रोड़ी पड़ी है और दो सौ मीटर के अन्दर तो थोड़ा सा बुरादे के तौर पर ही तारकोल डाला है और बाकी सारा वैसे ही पड़ा है । ठेकेदार और एस० डी० ओ० को कहा गया कि यह रोड कितने दिन चलेगी, इसमें तो केवल तीन इंच सोलिंग है । आप खुद जा कर चैक कर लें । उस पर केवल तीन इंच सोलिंग है और उसके ऊपर ही प्रिमिक्स कर दी है । तो जितनी शांक्शली और कशन इस महकमें में है और कहीं नहीं है । अगर आप इसको सुधार सकें तो देख लें वरना इसमें बहुत मिसयूज हो रहा है । इसके अलावा कसार रोड पर जो रोड़ी बिछाई थी वह अब इकट्ठी करने लग रहे हैं । पता नहीं क्या कारण है । वह रोड़ी डेढ़ किलोमीटर के अन्दर बिछा रखी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको इकट्ठी करने का क्या कारण है ।

**श्री अमर सिंह** : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल उठाया है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी धर्म पाल सिंह मलिक, आनरेबल मैम्बर और मैं वहां गए थे । उन रोडज पर बाकायदा काम शुरू है । जहां तक ये रोड़ी उठाने की बात कह रहे हैं, हमने उसकी स्ट्रैन्थनिंग करनी है । तो जब तक रोड़ी नहीं उठाई जाएगी तो रेजिंग कैसे होगी । वहां पर बाकायदा काम शुरू हो रहा है । जिन रोडज का इन्होंने जिक्र किया है उनको अगस्त, 1995 तक बाकायदा बेहतर बना दिया जाएगा और इनकी तसल्ली करवा दी जाएगी रोड़ी और तारकोल, मोटी रोड़ी और जीरा रोड़ी के जितने भी प्रावधान हैं वे बाकायदा मेनटेन हो रहे हैं । अगर इनको कोई शिकायत है तो मुझे बता दें ।

**श्री अध्यक्ष** : आप इनके साथ विजिट कर लें ।

**श्री अमर सिंह** : ठीक है जी, मैं सैशन के बाद मैम्बर साहब को साथ लेकर जाऊंगा और बाकायदा इनको तसल्ली करवाऊंगा ।

---

**Opening of Veterinary Hospital at Village Singhwal**

*1050. @Shri Bharath Singh : Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Veterinary Hospital in village Singhwal of District Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Hospital is likely to be be opened ?

---

@Put by Sh. Amar Singh Dhandey.

पशुपालन राज्य मंत्री (राव धर्मपाल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

**Construction of Bus Stand at Julana**

*1058. @Shri Suraj Bhan Kajal : Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Julana during the year 1995 ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह) : जी हां।

श्री सतबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाना का बस स्टैण्ड कब मंजूर हुआ था, उसके लिए कितना पैसा रखा गया था, उस पर कब काम शुरू करवाएंगे और उसको कब तक कम्पलीट करवा देंगे ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, उस बस स्टैण्ड की भूमि 7-10-90 को एक एकड़ एक्वायर की गई थी और दो एकड़ भूमि 1/92 को एक्वायर की गई थी यानि तीन एकड़ भूमि एक्वायर की गई है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उस बस स्टैण्ड को इसी वित्तीय वर्ष में कम्पलीट करवा दिया जाएगा ।

श्री अजमत खां : स्पीकर साहब, हथीन और हसनपुर में बस स्टैण्ड बनाने के लिए चार पांच साल से जमीन एक्वायर हो चुकी है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर बस स्टैण्ड बनाने का काम कब तक शुरू करवा दिया जाएगा और कब तक उनको कम्पलीट करवा दिया जाएगा ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, हथीन में बस स्टैण्ड के लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है और उसको बनाने का काम हम जल्दी ही शुरू करवा देंगे । जहां तक हसनपुर का सवाल है वहां पर अभी तक बस स्टैण्ड के लिए जमीन एक्वायर नहीं हुई है ।

श्री अजमत खां : स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी हथीन में बस स्टैण्ड बनाने का काम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करवा देंगे ?

श्री बलबीर पाल शाह : जी हां ।

---

@Put by Sh. Satbir Singh Kadyan.

**श्री शेर चन्द** : स्पीकर साहब, रतिया में बस स्टैण्ड बनाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पत्थर रखा था लेकिन वे यहां पर बस स्टैण्ड नहीं बना सके । हमारे मुख्य मंत्री जी रतिया गए थे, उस समय इन्होंने कहा था कि वह सरकार तो यह बस स्टैण्ड नहीं बना सकी, हम इस बस स्टैण्ड को जल्दी से जल्दी बना देंगे । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बस स्टैण्ड इसी वर्ष 1994-95 में कम्पलीट करा दिया जाएगा ?

**श्री बलबीर पाल शाह** : स्पीकर साहब, वर्ष 1994-95 तो खत्म होने वाला है लेकिन उस बस स्टैण्ड को बनाने का काम 1995-96 में शुरू करवा देंगे । उस बस स्टैण्ड का कांटेदार तार लगवाने का काम कर दिया गया है ।

**श्री मनी राम कैहरवाला** : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कितने बस स्टैण्डज का काम शुरू है और रानिया बस स्टैण्ड बनाने का काम जो शुरू है, उसको कब तक कम्पलीट करवा दिया जाएगा ?

**श्री बलबीर पाल शाह** : स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है कि रानिया बस स्टैण्ड 6 महीने के अन्दर बन कर तैयार हो जाएगा ।

**चौधरी सूरज मल** : स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ बस-स्टैण्ड के अन्दर बारिश के दिनों में तीन-तीन फुट पानी खड़ा रहता है, क्या यह बात मंत्री जी के नोटिस में है, अगर उनके नोटिस में है तो उस समस्या का समाधान कब तक करवा दिया जाएगा ? उस बस स्टैण्ड को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें पानी न खड़ा रहे ।

**श्री बलबीर पाल शाह** : स्पीकर साहब, बहुत से बस स्टैण्ड ऐसे हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं, उनमें पानी की निकासी की समस्या आ रही है । लोग चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वह अपनी जमीन में मिट्टी भर कर ऊंचा कर लेते हैं, उसके कारण पानी की निकासी की समस्या आती है । मैं बहादुरगढ़ के बस स्टैण्ड को दिखवा लूंगा । अगर वहां पर यह समस्या है तो उसको इसी वित्तीय वर्ष में दूर करवा देंगे ।

**श्री सतबीर सिंह कादियान** : स्पीकर साहब, जिन बेरोजगार लोगों को बसों के प्राइवेट परमिट दिए गए हैं, वे नेशनल हाई-वे पर बस स्टैण्ड से 10-10 किलो-मीटर दूर सवारियों को उतार देते हैं और उन सवारियों को हरियाणा रोडवेज की बसें बिठाती नहीं हैं । जैसे मतलोडा है और नौलथा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन जगहों पर सरकार बस स्टैण्ड बनाने के बारे में विचार करेगी ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो ?

**श्री बलबीर पाल शाह** : स्पीकर साहब, इसराना में इसी साल में बस-स्टैण्ड का निर्माण करा देंगे और नौलथा में बस स्टैण्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि

नीलखा ,इसराना के बिल्कुल साथ लगता हुआ है । जहां तक वहां पर क्यू शैल्टर बनाने की बात है, वह बनवा दिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा हो ।

---

**'Apni Beti Apna Dhan' Scheme**

***1075. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) the number of families provided the benefits under 'Apni Beti Apna Dhan' scheme in the State at present, together with the criteria adopted thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the benefits of the scheme as referred to in part (a) above to each family of the State ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) एवं (ख) विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है ।

विवरणी

(क) अपनी बेटी अपना धन योजना के अन्तर्गत दिनांक 28-2-95 तक राज्य में 16339 परिवारों को लाभ दिया जा चुका है पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं :—

(i) गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनुसूचित जाति के परिवार जिनमें लड़की का जन्म 2-10-94 को या उसके बाद हुआ हो ।

(ii) अनुसूचित जाति के परिवार जिनमें बेटी का जन्म 2-10-94 या उसके बाद हुआ हो, बशर्ते कि माता-पिता श्रेणी I अथवा II के राजपत्रित अधिकारी न हों अथवा आयकर दाता न हों,

उपरोक्त I एवं II के लिए यह भी शर्त है कि :—

नवजात शिशु कन्या परिवार का पहला, दूसरा या तीसरा बच्चा ही हो । तीन से अधिक बच्चों वाले परिवार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं ।

परन्तु, यदि तीसरी और चौथी बच्ची जुड़वां है तो चौथी बच्ची को भी लाभ दिया जायेगा ।

(iii) बच्चे के माता-पिता हरियाणा राज्य के अधिवासी हों ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि जो 16339 बैनिफिशरीज की संख्या इन्होंने बताई है, इसमें जिलावाईज संख्या क्या-क्या है ? दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्टस के जो अधिकारी श्रेणी-I व II में आते हैं, क्या उनको भी यह सुविधा दी जाएगी ? तीसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुड़गांव जिले में और फरीदाबाद जिले में जो लोग खेती करते हैं, उनको पानी की सुविधा न होने के कारण उनकी खेती भी ठीक प्रकार से नहीं होती और सरकारी हिदायतों के अनुसार वे गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, जबकि असलियत में उनकी हालत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों से भी बदतर है । क्या उनको भी इस श्रेणी में सुविधा दी जाएगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो 16339 बैनिफिशरीज हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र में 14089 व शहरी क्षेत्र में 2250 हैं । ग्रामीण क्षेत्र में बैनिफिशरीज की संख्या जिला वाईज इस प्रकार है :—अम्बाला में 809, जिसमें से 620 एस0 सी0 कैटेगिरीज के, 189 जनरल कैटेगिरी के हैं, यमुनानगर में 852, कुरुक्षेत्र में 466, कैथल में 800 , करनाल में 547, सिरसा में 865, सोनीपत में 576, रोहतक में 1314, फरीदाबाद में 561, जीन्द में 1179, रिवाड़ी में 590, भिवानी में 1395, महेन्द्रगढ़ में 429, हिसार में 2305, गुड़गांव में 853, पानीपत में 530, शहरी क्षेत्र में बैनिफिशरीज की संख्या है —अम्बाला 881, यमुनानगर 897, कुरुक्षेत्र 548, कैथल 889, करनाल 711, सिरसा 1018, तथा सोनीपत 1522, फरीदाबाद 68, जीन्द 1345, रिवाड़ी 640, भिवानी 1499, 10.00 बजे | महेन्द्रगढ़ 491, हिसार 2834, गुड़गांव 1047, पानीपत 811, और इसके बाद शहरों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का विवरण इस प्रकार है अम्बाला के अन्दर 72, यमुनानगर 45, कुरुक्षेत्र 82, कैथल 89, करनाल 164, सिरसा 153, सोनीपत 120, रोहतक 238, फरीदाबाद 1191, जीन्द 148, रिवाड़ी 50, भिवानी 104, महेन्द्रगढ़ 62, हिसार 529, गुड़गांव 194, पानीपत 81 यह शहरों का टोटल 20250 बनता है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्राईटेरिया के बारे में पूछा है । मैं इनको बताना चाहूंगा कि गरीबी रेखा के नीचे 8.381 प्रतिशत फैमिलीज हैं । यह फिगर डी0 आर0 डी0 ने 1991-92 की जनसंख्या निर्धारित की थी, उसके मुताबिक हैं । यह स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं । इस स्कीम से बैनिफिटिड होने वालों में 40 प्रतिशत एस0 सीज0, 21 प्रतिशत बी0 सीज0 हैं । इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि खासतौर पर बेटी को बोझ समझा जाता है, इससे लोगों की सोच को बदला जाए और लड़की को पूरा मान-सम्मान मिल सके। इस स्कीम के तहत 500 रुपये जच्चा की खुराक के लिए दिए जाते हैं ताकि गरीबों को कोई दिक्कत न हो । अमीर आदमी तो खुराक दे सकता है लेकिन गरीब आदमी को दिक्कत होती है । इसके साथ ही बेटी पैदा होने से जो हीन भावना होती है, उसको दूर करने के लिये 500 रुपये खुराक के अतिरिक्त 2500 रुपये पैदा होने वाली लड़की के खाते में जमा करवाए जाते हैं

जो कि लड़कियों की शादी के समय निकलवाए जा सकते हैं । उस वक्त तक यह राशि 25,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से यह स्कीम जनसंख्या रोकने के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकेगी । इस स्कीम का एक दूसरा उद्देश्य यह है कि पुरुष स्त्री का अनुपात 1000 के पीछे 865 है और उस रेशो को भी पूरा किया जा सके ताकि लड़कों के बराबर लड़कियां पैदा हों तथा लोगों में यह भावना पैदा न हो कि उसके लड़की ने जन्म लिया है, लोगों की इस सोच को बदलना है। जहां तक लड़कियों की मृत्यु दर का ताल्लुक है, वह पहले ही काफी कम है ।

**श्री कर्ण सिंह दलाल** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे लगता है कि वे लड़कियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इस लिए इस स्कीम को लागू किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्लास–I तथा क्लास II के जो अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह इतनी नहीं मिलती कि वे बच्चों का सही पालन पोषण कर सकें, क्या उनके लिए भी यह स्कीम लागू की गई है या नहीं ? मेरे सवाल का जवाब मन्त्री जी ने नहीं दिया । इसके अलावा जो मेरा सवाल था, वह यह था कि रिकार्ड के आधार पर जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर माने गए हैं लेकिन जिनकी हालत ऐसी है कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, क्या उन लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे ? अध्यक्ष महोदय फरीदाबाद बाद तथा गुड़गांव के लोग बहुत गरीब हैं । वहां धरती में पानी नहीं लगता, नौकरी लोगों को मिलती नहीं, इसलिए आपके माध्यम से मन्त्री जी से मेरा यह सवाल है कि क्या उन लोगों को भी इस स्कीम में शामिल करेंगे ?

**कैप्टन अजय सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इनको बता दिया है कि यह स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं । इसका और कोई क्राईटेरिया नहीं है ।

---

## Road Accidents in the State

*1095. **Prof. Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of motor vehicles and other accidents occurred in the State during the years 1993-94 and 1994-95 ;

(b) the total number of persons died and injured in the above said accidents during the said period, separately ; and

(c) the amount of compensation, if any, given by the Government in each case to the percns injured and the families of deceased

[Prof. Sampat Singh]

involved in the accidents as referred to in part (a) above ?

**Mr. Speaker** : Extension for giving reply to this question has been requested by the Govt. which has been granted. Interim reply is as under".

**Interim Reply**

"BHAJAN LAL

D.O. No. 52/8/95-7HG-II
**Chief Minister, Haryana,**
**Chandigarh.**
March 1995.

*Subject* : **Reply to starred question No. 1095—Extension/Deletion of Part (c).**

My Dear Speaker Sahib,

Starred question No. 1095 relating to road accidents in the State has not so far been listed for reply. The part (C) of the question relates to the information with regard to the amount of compensation, if any, given by Govt. in each case to the persons injured and the families of deceased involved in the accidents. The compensation is awarded by the following agencies :—

(i) Courts in MACT cases.
(ii) Deputy Commissioners from Red Cross.
(iii) State Govt. from Govt. fund.
(iv) Ministers out of their discretionary fund.
(v) Chief Minister out of Govt. fund or discretionary fund.
(vi) Various courts out of fine imposed.
(vii) Insurance companies, Workmen-compensation Act.
(viii) E.S.I.
(ix) Insurance companies against claim filed.

The collection of the requisite information from the above mentioned authorities will be a colossal task and may take 6 months. It is felt that the significance of collection of such figures may not be commensurate with the efforts and labour involved. I am, therefore, to request that either a period of 6 months may be granted for collection of figures or part (c) of the question may be deleted.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(BHAJAN LAL)

Ch. Ishwar Singh,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha."

**Repair/Construction of Roads in the State**

*1010. **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state—

(a) the districtwise total amount spent on the repair of roads, in the State during the period from July 1991 to date ;

(b) the total amount spent on the construction of new roads in the State during the period from July, 1992 to date ;

(c) whether all the villages have been conected with the metalled road in the State, if not, the names of such villages which have not been connected so far together with the time by which these are likely to be connected with the metalled road ?

**Public Works Minister** (Shri Amar Singh) :

(a), (b) & (c) A statement is laid on the table of the House.

**Statement**

(a) District-wise amount spent on the repair of roads during the year July, 1991 to date is as under :—

| Sr. No. | Name of District | Amount spent (Rs. in lacs) |
|---|---|---|
| 1. | Ambala | 715 |
| 2. | Bhiwani | 752 |
| 3. | Faridabad | 690 |
| 4. | Gurgaon | 915 |
| 5. | Hisar | 1440 |
| 6. | Jind | 579 |
| 7. | Kaithal | 410 |
| 8. | Karnal | 680 |
| 9. | Kurukshetra | 652 |
| 10. | Mohindergarh | 389 |
| 11. | Panipat | 447 |
| 12. | Rewari | 360 |
| 13. | Rohtak | 1044 |
| 14. | Sirsa | 646 |
| 15. | Sonepat | 566 |
| 16. | Yamuna Nagar | 508 |

[Shri Amar Singh]

(b) Amount spent on the construction of roads during the period July, 1992 to date is Rs. 1417 Lacs.

(c)(i) Out of 6745 villages only 7 villages covered under the policy remain to be connected with metalled road. The details are as under :—

| Sr. No. | Name of Village | District |
|---|---|---|
| 1. | Prem Pura | Ambala |
| 2. | Khol Fateh Singh | ,, |
| 3. | Khol Mola | ,, |
| 4. | Bhoj Khudana | ,, |
| 5. | Bhoj Rajpura | ,, |
| 6. | Dakrog | ,, |
| 7. | Khoi | ,, |

(ii) Besides this the following villages wth population less than 250 in plain & 150 in hills and which are not covered under existing policy have also not been connected by metalled roads :—

| Sr. No. | Name of Village |
|---|---|
| | **Ambala District** |
| 8. | Sangoli |
| 9. | Peerwali |
| 10. | Pamiwala |
| 11. | Udhamgarh |
| 12. | Rampur Gainda |
| 13. | Kurewala |
| 14. | Belgarh |
| 15. | Kamiawala |
| 16. | Khan Puri |
| 17. | Khol Albela |
| 18. | Banoi Sanwalia |
| 19. | Tibbi |
| 20. | Gawahi |
| 21. | Gumthala |
| 22. | Bhagrani |
| 23. | Dhamso |

| Sr. No. | Name of Village |
|---|---|
| 24. | Jaithal |
| 25. | Nalah Dakrog |
| | **Karnal District** |
| 26. | Nabiabad |
| 27. | Sadiqpur |
| 28. | Sherpur Viran |
| | **Kurukshetra District** |
| 29. | Kohli Khera |
| 30. | Theh Mujibulah |
| 31. | Teokran |
| | **Rohtak District** |
| 32. | Bir Dadri |
| 33. | Bir Sumariwala |
| | **Sonepat District** |
| 34. | Munirpur |
| 35. | Dhiki |
| | **Faridabad District** |
| 36. | Akbarpur |
| 37. | Shekhpur |
| 38. | Mauzmabad |
| 39. | Latifpur |
| 40. | Dulapur |
| 41. | Masudpur |
| 42. | Beurampur |
| 43. | Naglia |
| 44. | Jhuppa |
| 45. | Dalepur |
| 46. | Tajpur |
| 47. | Dostpur |
| 48. | Qureshipur |
| 49. | Sherpur Khadder |
| | **Gurgaon District** |
| 50. | Ranika Notab |
| 51. | Rehaka |
| 52. | Hamirpur |

[Shri Amar Singh]

| Sr. No. | Name of Village |
|---|---|
| 53. | Zakopur |
| 54. | Dholi |
| 55. | Jakh |
| 56. | Kharli Tor |
| 57. | Kharak Sohna |
| 58. | Bidhuwas |
| 59. | Nahrepur |
| 60. | Siyanika |
| | **Bhiwani District** |
| 61. | Rohrodi Khurd |
| | **Hisar District** |
| 62. | Saladheri |
| | **Sirsa District** |
| 63. | Kasankhera |
| 64. | Sawaipur |
| 65. | Bukhara Khera |
| 66. | Moranwali |
| | **Mohindergarh District** |
| 67. | Muradpuri |

Villages at Sr. No. 1 to 7 will be connected with metalled road, as soon as possible, depending upon availability of funds. There is at present no proposal under consideration to provide link roads to villages at Sr. No. 8 to 67 above.

**प्रो० छतर सिंह चौहान** : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने चौधरी बीरपाल सिंह जी के सवाल के जवाब में बताया है कि जो फुल्ली एफैक्टिड एरियाज हैं, जहां पर वर्षा के दौरान सड़कें टूट जाती हैं, उनकी रिपेयर हो गई है, यह अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उन के मुताबिक इन्होंने पिछले सालों में जो पैसा खर्च किया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री महोदय और इनकी सरकार लोगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि पौलिटिकल आधार पर पैसा खर्च करती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि जुलाई 1991 से आज तक जो खर्चा हुआ है उसमें से हिसार में 1440 लाख, कैथल में 460 लाख, करनाल में 680 लाख और कुरुक्षेत्र में 652 लाख रुपए खर्च किए

हैं । भिवानी जिला ऐसा जिला है जहां पर करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र से ज्यादा बाढ़ आने लगी है, क्या वहां पर पैसों की ज्यादा व्यवस्था करेंगे ? (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न के "बी" पार्ट के जवाब में माना है कि—

"Amount spent on the construction of Roads during the period July, 1992 to date is Rs. 1417 Lacs."

तो यह जो 1417 लाख खर्च किया है उसमें से हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट-वाईज कितना-कितना खर्च किया है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जो लिस्ट दी है उस बारे में मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि 1994 में मिठी गांव में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, क्या उसकी पूर्ति भी ये करेंगे और जो गांव सड़क से नहीं जोड़े हैं, उनको कब तक जोड़ने का ये इरादा रखते हैं ?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और ये प्रोफैसर हैं, गोल्ड मैडलिस्ट भी हैं । मैंने तो इनके सवालों का जवाब डिटेल में दिया हुआ है । मैं इनको बताना चाहूंगा कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 237 किलोमीटर स्टेट हाई-वे, 50 किलोमीटर अदर और डिस्ट्रिक्ट विलेज रोड 1313 किलोमीटर हैं, यह टोटल 1600 किलोमीटर बनता है, इस पर 718 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है । भिवानी में 442 किलोमीटर स्टेट हाई-वे, 239 किलोमीटर मेजर रोडज और 1328 किलोमीटर रूरल रोडज हैं, यह टोटल 2009 किलोमीटर बनता है और इस पर 7 करोड़ 92 लाख रुपए खर्चा आया है । इसी तरह से हिसार सबसे बड़ा जिला है और इसमें सबसे ज्यादा लम्बी रोडज हैं । 391 किलोमीटर स्टेट हाई-वे, 211 किलोमीटर मेजर रोडज और अदर रोडज 2222 किलोमीटर हैं । यह टोटल 2824 किलोमीटर बनती हैं । इस पर टोटल खर्चा 14.40 करोड़ आया है । यह सब फिगर्ज 1-7-91 से लेकर 31-1-1995 तक की हैं । हमने सारी डिस्ट्रिक्टस की तो इंफर्मेशन दी हुई है, फिर ये हाउस का समय क्यों खराब कर रहे हैं ? इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इनको सवाल के जवाब को देखकर ही अपनी सप्लीमैन्ट्री करनी चाहिए ।

मुख्य मंत्री (चौ० भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी से जानना चाहिए लेकिन मैं छत्तर सिंह जी से जानना चाहता हूं क्योंकि ये अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं । भिवानी जिले की आबादी हिसार जिले से आधे से भी कम होगी लेकिन फिर भी हमने आधे से भी ज्यादा पैसा आपको दे रखा है । परन्तु इनको तो हिसार जिले के नाम से फोबिया हो गया है । हमने 7 करोड़ 52 लाख रुपया भिवानी जिले को और 14 करोड़ रुपया हिसार जिले को दिया है जबकि रोहतक को दस करोड़ रुपये दिए हैं, यानि किसी भी इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, इसलिए आपको देखना चाहिए कि भिवानी जिले की आबादी कितनी है ? इसी तरह से फरीदाबाद जिले को 6 करोड़ 90 लाख रुपये दिए गए हैं ।

[चौधरी भजन लाल]

(विघ्न) हिसार तो सबसे बड़ा जिला है और इसके बाद रोहतक का नम्बर आता है । (विघ्न)

---

## तारांकित प्रश्न सं0 1139

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

---

**Amount spent on the Repair of Roads of District Kaithal**

*1118. **Shri Amar Singh Dhandey :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the constituency-wise total amount incurred by the Government on the repair of roads in district Kaithal during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 separately ?

**Public Works Minister (Shri Amar Singh) :** A statement is laid on the table of the House.

**Statement**

Constituency-wise total amount incurred on repair of roads in Kaithal District.

| Sr. No. | Name of Constituency | Year-wise expenditure (Rs. in lacs) | | | | Total expenditure from April, 1991 to January, 1995 (Rs. in lacs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 upto 1/95 | |
| 1. | Guhla | 20.56 | 19.62 | 11.11 | 17.15 | 68.44 |
| 2. | Kaithal | 28.23 | 17.57 | 28.11 | 13.60 | 87.51 |
| 3. | Pundri | 39.67 | 24.28 | 22.06 | 16.41 | 102.42 |
| 4. | Pai | 43.95 | 23.62 | 12.83 | 17.46 | 97.86 |
| 5. | Rajound (in Kaithal District) | 0.72 | 0.66 | 3.80 | 7.59 | 12.77 |
| 6. | Kalayat | 24.55 | 11.12 | 10.86 | 20.20 | 66.73 |
| | Total | 157.68 | 96.87 | 88.77 | 92.41 | 435.73 |

**श्री अमर सिंह ढांडे** : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैथल जिले में इन्होंने जो पैसा खर्च किया है, उसमें से सबसे कम पैसा गुहला में ही क्यों खर्च किया गया है ? गुहला हल्का तो पूरी तरह से फलडिड एरिया है वहां पर कई बार लगातार बाढ़ आयी थी इसलिए वहां पर सड़कों की बुरी हालत है । मैं जानना चाहूंगा कि गुहला हल्के के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? मैंने इस बारे में कई बार पहले भी कहा था कि पैसा सड़कों पर खर्च न होकर कहीं और खर्च होता है । स्पीकर सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाएं जो जांच करे कि क्या वहां पर एक्चुअल में पैसा खर्च हुआ है या नहीं ?

**श्री अमर सिंह** : स्पीकर सर, गुहला में ईयरवाईज जो पैसा खर्च किया गया है, उसके बारे में मैं इनको बता देता हूं । वर्ष 1991–92 में 20.56 लाख रुपये और 1992–93 में 19.62 लाख रुपये 1993–94 में 11.11 लाख रुपये 1994-95 में जनवरी 1995 तक 17.15 लाख रुपये खर्च किए गए हैं यानि गुहला में टोटल 68.44 लाख रुपये खर्च किए गए हैं । इसी तरह से कैथल में 87.51 लाख रुपये खर्च किए गए हैं ।

**श्री अमर सिंह ढांडे** : लेकिन गुहला में सबसे कम पैसा क्यों खर्च किया गया है ?

**श्री अमर सिंह** : स्पीकर सर, इसी तरह से राजौंद में टोटल 12.77 लाख रुपये खर्च किए गए हैं । किसी भी हल्के के साथ पक्षपात की बात नहीं है । हर गांव में सड़कें भेजी हुई हैं, हर गांव में पीने के पानी का इन्तजाम है । आप ऐसा एक भी गांव बता दें जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम के द्वारा पीने का पानी न पहुंचता हो । (विघ्न) मैं भी सड़कों की ही बात कर रहा हूं । कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा गया जहां सड़क न पहुंची हो, सारे गांव सड़कों से मिले हुए हैं । जहां तक पैसे की बात है, बकायदा गुहला में अलग-अलग साल में अलग-अलग पैसा खर्च किया गया है । 1991–92 में सरफेसिंग पर 12 लाख रुपये खर्च हुए । इसी तरह से 1991–92 में रिपेयर पर 35.35 लाख रुपये खर्च किए गए । इसके अलावा 1992–93 में रिपेयर पर, सरफेसिंग पर और स्ट्रैंथिंग पर 13 लाख रुपये खर्च हुए हैं। 1994–95 में जनवरी तक गुहला में 17.15 लाख रुपये खर्च हुए हैं । इसी तरह से 1993–94 में 11.11 लाख रुपये, 1992–93 में 19.62 लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला** : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी बहुत ढोल पीटते हैं कि हमने अपने टाइम में हरियाणा के हर गांव को मैटल रोड से जोड़ दिया । यह बात सत्य नहीं थी । बहुत से गांवों को चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने जोड़ा है । विशेषकर हमारा जिला फरीदाबाद खादर में पड़ता है ।

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

चौधरी अमर सिंह जी वहां गए थे इनकी विशेष कृपा है लेकिन इन्होंने एक सूचना सदन के पटल पर दी है कि 250 की पापुलेशन से नीचे के ये गांव हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन सब गांवों में जैसे अकबरपुर, शेखपुर, लतीफपुर, दुलेपुर, मसूदपुर, बहरामपुर, नगलिया, झुग्गा दलेलपुर, दोस्तपुर और कुरैशीपुर इत्यादि गांव हैं, 250 से ज्यादा पापुलेशन है । क्या मंत्री जी सैशन के बाद वहां चलेंगे, मैं इनको सारे गांव दिखा दूंगा । अगर इन गांवों की पापुलेशन ज्यादा मिली तो क्या ये मौके पर आदेश देंगे कि वहां पर सड़क फौरन बना दी जाए ?

**श्री अमर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक फरीदाबाद जिले में 14 ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 250 से कम है । यह हमारी पॉलिसी में नहीं आता । अगर माननीय सदस्य बता देंगे कि 250 से ऊपर आबादी है तो हम प्रावधान करेंगे ।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला** : हम आपको हाथ खड़े करके गिनवा देंगे ।

**श्री अमर सिंह** : अगर हाथ खड़े करवा कर गिनवा देंगे तो हम इन गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे ।

**श्री अजमत खां** : अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने जो बात कही है वह एरिया मेरे हल्के के साथ है । मेरे हल्के में कुम्हेड़ा, टीका और साढ़-चिल्ली, ये तीन ऐसे गांव हैं जिनमें से दो गांव की आबादी 800 से एक हजार के बीच है और एक गांव की आबादी 400 के लगभग है । मंत्री जी हमें टाइम दे दें, हम इन्हें मौके पर दिखा देंगे । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक इन गांवों को सड़कों से जुड़वा देंगे ?

**श्री अमर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी । नये बजट के मुताबिक जो गांव, जो ढाणियां हैं, जिनकी आबादी 250 से ऊपर हो गई होगी, उनको 1995-96 में जरूर रोड से मिला देंगे ।

**श्री लहरी सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गांव गूढ़ी डायरैक्टरी विलेज है, बड़ा गांव है जिसकी एक हजार आबादी है, वह आज तक सड़क से नहीं जुड़ा । इसमें सिर्फ छह सड़कों का ब्यौरा दिया है । यह गूढ़ी गांव किसी भी तरफ से सड़क से नहीं जुड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कब तक इस गांव को सड़क से जोड़ देंगे ? मैंने लिखकर भी भेजा है ।

**श्री अमर सिंह** : उस गांव की आबादी 250 से ज्यादा है तो उसको भी सड़क से जोड़ देंगे ।

**Sprinkler Sets**

*1179. **Shri Om Parkash Beri** : Will the Minister for Co-operation be pleased to state whether any case of payment made by the Land Development Bank in Bhiwani and Mohindergarh districts to un-approved sprinklers supplying firm has come into the notice of the Government during the year 1994; if so, the action taken thereon ?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : वर्ष 1994 में भिवानी एवं महेन्द्रगढ़ जिलों में भूमि विकास बैंकों द्वारा अमान्य स्प्रिंकलर सैट सप्लाई करने वाली किसी भी फर्म को किसी स्प्रिंकलर सैट के लिये वित्त उपलब्ध नहीं करवाया गया । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

**श्री ओम प्रकाश बेरी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा बहिन जी ने बताया कि किसी को लोन नहीं दिया गया । जिसको लोन दिया गया है उसका मैं आपको चैक नम्बर भी बता सकता हूं और डेट भी बता सकता हूं । मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा स्टेट भूमि विकास बैंक ने, अपने पत्र नंबर 2350 दिनांक 18-4-94 के द्वारा हरियाणा राज्य में जो भूमि-विकास बैंक हैं, उनके मैनेजर्ज को चिट्ठी लिखी थी कि रूंगटा इरीगेशन कंपनी को जिंदल इरीगेशन कम्पनी मानकर, उसको नयी कम्पनी न माना जाए और इसके जरिए किसानों को स्प्रिंकलर सेट का कर्जा दे दिया जाए ?

दूसरी बात यह है कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी इस प्रदेश के अन्दर बनी हुई है जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं और स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने का मामला इसी परचेज कमेटी के मातहत आता है । 27-7-94 को इसी हाई-पावर्ड परचेज कमेटी की मीटिंग हुई । इस मामले से संबंधित मेरे पास एक लैटर है । इस मीटिंग में यह निर्णय इस पर लिया गया कि रूंगटा इरीगेशन लिमिटेड को जिन्दल इरीगेशन लिमिटेड न माना जाए और नई कम्पनियों की तरह हरियाणा में माल बेचने के लिये नये तरीके से कम्पनी के प्रोडक्ट का इवैलुऐशन टैस्ट देना होगा । उसका लिखित आदेश कृषि विभाग द्वारा पत्र संख्या 659/74टी-ए II एस-ई, दिनांक चण्डीगढ़ 4-10-94 को सूचित किया गया कि यह टैस्ट निजी कम्पनी के साथ दिनांक 7-11-94 से 10-11-94 को भिवानी शिक्षा बोर्ड में होगा और 8-11-94 को यह टैस्ट हुआ । उससे पहले यह कम्पनी कतई तौर पर अन-ऐप्रूवड कम्पनी थी । प्रबन्धक निदेशक ने जो चिट्ठी लिखी वह इस अन-ऐप्रूवड कम्पनी को किसानों को लोन बांटने की बात लिखी गई थी । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्या उस एम0 डी0 ने हरियाणा प्रदेश के सभी भूमि विकास बैन्कों के मैनेजर्ज को यह चिट्ठी लिखी है कि रूंगटा इरीगेशन लिमिटेड को जिंदल इरीगेशन लिमिटेड मान कर इसके जरिये किसानों को स्प्रिंकलर सैट्स के लिये लोन दे दिया जाये ? इसके साथ क्या यह भी सही है कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी का जो

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

फैसला है उसके अनुसार इसको जिंदल इरीगेशन लिमिटेड न माना जाए, क्या यह बात मन्त्री महोदया के नोटिस में है ।

इसके साथ-साथ स्पीकर साहब, जैसाकि इन्होंने यह भी कह दिया कि लौहारू या महेन्द्रगढ़ के बैंकों से किसी किस्म का कोई लोन किसानों को स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने के लिये नहीं दिया गया है । स्पीकर साहब, इस बारे में मेरे पास कुछ चैकस के नम्बर उपलब्ध हैं कि किस-किस को कितना-कितना पैसा दिया गया है ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर सर, मेरे पास यह 32 कंपनियों के नाम हैं इनमें रूंगटा कंपनी भी शामिल है । वह ऐंप्रूवड कंपनी है और उसमें किसी अकेले एम0 डी0 का हाथ नहीं होता । उसमें हाई-पावर्ड परचेज कमेटी ही सारा निर्णय करती है और इस बारे में 27-7-94 को रूंगटा कंपनी से हमारी बातचीत 16 स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने के बारे में हुई । बेरी साहब के पास जो लैटर है, यह हमारे पास नहीं है । अगर इस तरह का पत्र इनके पास था तो वह कंपनी के हित में होता किसानों के हित में ही होता तो इस बारे में आप हमें वैसे ही सूचित कर देते, हम मान लेते । ऐसी कोई बात नहीं है । बेरी साहब मैं तो वैसे भी आपका मान करती हूं ।

---

**Construction of Bye-Pass at Pehowa**

*1172. @Shri Jaswinder Singh : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass on Ambala-Hisar road in Pehowa ; and

(b) if so, the time by which the bye-pass as referred to in part (a) above is likely to be constructed ?

**Public Works Minister** (Shri Amar Singh) :

(a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि अम्बाला-हिसार सड़क पर बाई-पास का निर्माण करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहूंगा कि यह सड़क स्टेट हाई-वे पेहवा के बीच से गुजरती है और अध्यक्ष महोदय, यह आपके पड़ोस में ही है । इस सड़क पर काफी ऐक्सीडैन्ट्स होते हैं । क्या मन्त्री

@Put by Shri Amar Singh Dhandey

महोदय अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और बाई-पास बनाने की कृपा करेंगे क्योंकि यह बाई-पास हर लिहाज से बड़ा ही जरूरी है ।

**श्री अमर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी ठीक है कि अम्बाला-हिसार सड़क पेहोवा में से गुजरती है और इस सड़क की फोरलेनिंग का प्रावधान 47,69,200 रुपया लगाकर कर रहे हैं । 1995-96 में जब यह फोर लेन बनकर तैयार हो जाएगी । इसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो बाई-पास बनाने की बात की जा सकती है । फिलहाल बाई-पास बनाने का कोई सवाल नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष :** आप पेहवा के पास कोई साइड रोड बनाने की सोचें ताकि कैथल से आते हुए वह बाहर-बाहर से ही निकल जाए । ऐसा सोचें तो ठीक है ।

---

## Opening of Ayurvedic and Unani Colleges

*1181. **Sbri Azmat Khan:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to open Ayurvedic and Unani Colleges in the State ; if so, the places at which the said Colleges are likely to be opened?

**स्वास्थ्य मंत्री** (बहिन करतार देवी) : नहीं ।

**श्री अजमत खां :** स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अगर आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज खोल दें तो जो बच्चे वहां से पढ़ कर आएंगे उनको लाइसैंस मिल जाएगा । ऐसा होने से उनको रोजगार भी मिल जाएगा और सरकार का भी नौकरियां देने का बोझ घट जाएगा । ऐसा करने से एक तरफ तो बेरोजगारी खत्म होगी और दूसरी तरफ लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा । तो क्या मन्त्री जी मेरे सुझाव पर दोबारा विचार करेंगे ?

**बहिन करतार देवी :** स्पीकर साहब, इस वक्त राज्य में एक सरकारी और तीन प्राइवेट आयुर्वेदिक कालेज कार्य कर रहे हैं । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि श्री मस्त नाथ आयुर्वेदिक कालेज बोहर में, श्री माडू सिंह मैमोरियल महिला डिग्री आयुर्वेदिक कालेज खानपुर कलां में और श्री गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कालेज रोहतक में चल रहे हैं । सरकार द्वारा श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कालेज कुरुक्षेत्र में कार्यरत है । जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, कई प्रश्नों के उत्तर में मैंने सदन में बताया है कि इनफरास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, हरियाणा देश की गिनी चुनी स्टेट्स में है जिसमें कि राष्ट्रीय पालिसी के मुताबिक हमने तीन तरफ से, हैल्थ साइड से भी हर पांच हजार की आबादी पर सब सैंटर, बीस हजार की आबादी पर पी० एच० सी० और एक लाख की आबादी पर सी० एच० सी० बनाने का प्रोग्राम है । इसमें से पी० एच० सी० का प्रोग्राम तो हमने पूरा कर लिया है बल्कि चार ज्यादा बना चुके हैं । जहां तक

[बहिन करतार देवी]
आयुर्वैदिक और यूनानी डिस्पैंसरियों का सवाल है, स्पीकर साहब, इस वक्त स्टेट में 401 आयुर्वैदिक, 20 होम्योपैथिक और 20 यूनानी डिस्पैंसरीज काम कर रही हैं और इनसे जनता को स्वास्थ्य की पूरी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैंने माननीय सदस्य को जवाब दिया है कि इस समय कोई नया कालेज तो विचाराधीन नहीं है लेकिन श्री कृष्णा आयुर्वैदिक कालेज के ढांचे को उत्तम और देश की अच्छी संस्थाओं में से एक बनाने का प्रयास सरकार कर रही है।

**श्री अध्यक्ष :** क्या आप यह भी कंसिडर करेंगे कि आयुर्वैदिक पी0 एच0 सी0 भी खोलेंगे ? डिस्पैंसरीज तो आपकी पहले हैं ही।

**बहिन करतार देवी :** अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी तीन आयुर्वैदिक पी0 एच0 सीज0 पहले हैं। दो और खोलने के लिए मामला सरकार के विचाराधीन है। यह केस फाइनैंस डिपार्टमैंट में पड़ा है। इन दो में एक आपका फरल गांव भी है।

**श्री अध्यक्ष :** क्या फाइनैंस मिनिस्टर इसको कंसिडर करेंगे ?

**वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :** स्पीकर साहब, जरूर करेंगे।

---

**श्रीमती चन्द्रावती :** स्पीकर साहब, झूठे सर्टिफिकेट्स के बारे में मेरा एक सवाल था जिसको आपने पोस्टपोन कर दिया था, वह कब लगेगा ? आप उसे कल लगा दें क्योंकि कल हाउस खत्म हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष :** क्वैश्चन प्रायरिटी के हिसाब से लगता है।

**श्रीमती चन्द्रावती :** स्पीकर साहब, वह आपने पोस्टपोन किया था तो आप उसको कल लगवा दें क्योंकि सैशन का कल लास्ट डे है।

**श्री अध्यक्ष :** यह कंसिडर कर लेंगे।

---

**Relief to the Amputated Persons**

***1186. Sathi Lehri Singh :** Will the Minster for Agriculture be pleased to state the total number of applications received by the Haryana State Agricutural Marketing Board for the grant of relief on account of amputation of limbs while operating Agricultural Machines during the

years 1987 to 1990 and 1991 to 1994; togetherwith the amount of relief paid to each applicant during the said period ?

**Mr. Speaker** : Extension for giving reply to this question has been requested by the Govt. which has been granted. Interim reply is as under :—

**Interim Reply**

"**HARPAL SINGH**

D.O. NO. AS-III-95/

Agriculture Minister,
Haryana, Chandigarh

Dated 22-3-1995.

*Subject* : **Starred Assembly Question No. 1186 raised by Sh. Lehri Singh, M.L.A.**

Dear Shri Ishwar Singh Ji,

Starred Assembly Question No. 1186 regarding relief to the amputated persons, raised by Shri Lehri Singh, M.L.A. has been listed for 23-3-1995. The question relates to financial assistance given by the Agricultural Marketing Board/Market Committees to each of the victims of agricultural operations during the eight years period from 1987 to 1994. Shri Lehri Singh has asked the total nos. of applications received for the grant of relief during the year 1987 to 1990 and 1991 to 1994. He has also asked the amount of relief paid to each applicant.

The collection of information will take a lot of time because the figures/information relates to several thousand persons and is spread over 100 market committees. In order to frame proper reply and furnish correct information, a period of 2 months is required.

It is, therefore, requested that a time of 2 months may be given to enable us to submit reply to you.

Yours sincerely,

Sd/-
(HARPAL SINGH)

Shri Ishwar Singh,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha."

**Mr. Speaker** : Question Hour is over.

## ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनायें

**श्री कर्म सिंह दलाल:** स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था कि मेरे हल्के के गांवों में जिनके नाम मैंने अपने मोशन में लिखे हुए हैं, जोहड़ों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इस बारे में मेरी सिंचाई मंत्री जी से बात भी हुई थी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अधिकारियों को कहा भी है लेकिन उसके बावजूद भी उनमें पानी नहीं पहुंचा है। अधिकारी कहते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनमें पानी पहुंच जाएगा। स्पीकर साहब, अप्रैल तक तो बेचारे पशु बिना पानी के मर जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जिन गांवों के नाम मैंने अपने मोशन में लिखे हैं क्या उन गांवों के जोहड़ों में दो चार दिन में पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा मेरा एक काल अटैंशन मोशन था कि पलवल में एक आदमी की 'एड्स' से मौत हुई है उस कारण से सारे पलवल शहर में दहशत फैली हुई है।

**श्री अध्यक्ष:** ये दोनों प्रस्ताव कोमैंटस के लिए गवर्नमैंट को भेजे हुए हैं। आप बैठ जाइए।

**श्री ओम प्रकाश बेरी:** अध्यक्ष महोदय, मैंने चार पांच दिन पहले एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में मोशन दिया था और दूसरा यमुना वाटर एग्रीमैंट के बारे में दिया था। ये दोनों इशू बहुत अहम हैं और इनके बारे में पूरा हरियाणा प्रदेश चिन्तित है। आप इनके बारे में दो घंटे की बहस करवाने की इजाजत दें ताकि सारी बात क्लीयर हो जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज और कल दो दिन का सैशन रह गया है और प्रो0 छतर पाल सिंह बहुत अर्से से सैशन से निलम्बित किए हुए हैं, उनको सदन में आने की इजाजत मिलनी चाहिए। वे अब बिल्कुल चुपचाप हैं। अब न उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है और न ही धरने पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूं कि सरकार उनके खिलाफ सस्पैंशन का प्रस्ताव ले कर आई और वह पास भी हो गया लेकिन आप उस पर पुनः विचार करें। अब तो केवल दो दिन का ही सैशन रह गया है, यदि उनको सैशन में आने की इजाजत नहीं मिलती तो खिराय हल्का अनरीप्रैजैंटिड रह जाएगा।

**प्रो0 राम बिलास शर्मा:** स्पीकर साहब, आपके चैम्बर में सरकार के संसदीय मंत्री महोदय ने प्रो0 छतर पाल सिंह का मौन व्रत तुड़वाया था। आपके सामने चौधरी जगदीश नेहरा जी ने आश्वासन दिया है। आपके आश्वासन के बाद तो उनको सदन में आने की इजाजत मिलनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** मैंने तो कोई आश्वासन नहीं दिया।

**प्रो० राम विलास शर्मा :** स्पीकर साहब, आपने तो आश्वासन नहीं दिया लेकिन आपकी उपस्थिति में आपके चैम्बर में अगर कोई बात हुई हो तो वह बहुत अहमियत रखती है । विपक्ष के नेता की मौजूदगी में मेहरा जी ने उनका मौन व्रत तुड़वाया था । इसलिए स्पीकर साहब मैं कहता हूं कि बेरी साहब की बात को मान लिया जाए । अब एक दिन का तो सैशन रह गया है । उस बात को खत्म करके उनको सदन में आने की इजाजत दें । स्पीकर साहब, कल मैंने यहीं पर खोड़क गांव के हरिजनों के पलायन की बात उठाई थी और मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा था कि कुछ हरिजन परिवारों ने भय के कारण गांव से पलायन कर लिया था ।

**श्री अध्यक्ष :** आप यह बात किस लिए कहना चाहते हैं ?

**प्रो० राम विलास शर्मा :** स्पीकर साहब, यह हरिजनों का गांव से पलायन का सवाल है, जब किसी को अपना घर छोड़ कर चलना पड़ता है तो यह एक बहुत ही गम्भीर बात है । आज मैं उनकी लेटैस्ट लिस्ट ले कर आया हूं । हरिजनों के 25 परिवार आज भी कैथल में हैं । सदन के किसी भी मैम्बर को भेजकर आप पता करवा लें कि उन 25 परिवारों के घरों पर ताले लगे हुए हैं या नहीं । (शोर)

**श्री किताब सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कॉल अटैंशन मोशन सीड की मैक्सिमम लिमिट फिक्स करने के बारे में दिया था । उसका क्या हुआ ।

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठिये । वह 24 तारीख के लिए लगा दिया गया है ।

**श्री बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं पहले कल की कुछ आनरेबल मैम्बर्ज की स्पीच देखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पर कुछ आक्षेप लगाए गए । दूसरी बात यह है कि जिस रोज मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो मैंने उस वक्त इंटरवीन किया था तो आप कहने लगे कि पहले मुख्य मंत्री को बोल लेने दो, बाद में आप बोल लेना । लेकिन उस वक्त मुझे समय नहीं मिला । कृपया मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए आप समय दे दें ।

**श्री अध्यक्ष :** आज भी बोलने का टाईम है, कल भी है । उस वक्त आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें ।

**श्री बंसी लाल :** मैंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी है और कुछ मुख्य मंत्री से क्लैरिफिकेशन लेनी है ।

**श्री अध्यक्ष :** जिस समय आपको बोलने का मौका देंगे, उस समय आप अपनी पर्सनल एक्स्प्लेनेशन दे दें ।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, प्रो० छबपाल सिंह जी को गलत तरीके से हाउस से निकाला गया है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप उनको बुलाईए ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, बार-बार उसी बात को रिपीट करने का क्या फायदा । कृपया आप बैठिये ।

---

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

### थर्मल पावर प्लांट, पानीपत के गन्दे पानी तथा राख के कारण प्रदूषण से बीमारियां फैलने संबंधी

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attenton Motion No. 27, given notice of by Shri Satbir Singh, M.L.A. regarding pollution due to waste and dirty water of Thermal Power Plant, Panipat and spreading of diseases in the nearby villages. I admit it. Shri Satbir Singh Kadian may please read out his notice and the concerned Minister may make a statement, thereafter.

**Shri Satbir Singh Kadian :** Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the waste ash of Thermal Power Plant, Panipat showers on villages Khukhrana, Sutana, Asan Kalan, Asan Khurd and Bohal etc. and dirty water remains accumulated in the streets of said villages due to which various kinds of diseases are breaking out there. The water table has gone up on account of not having proper out-letting of dirty water which has caused water logging. On account of it crops are not sown in time. The Government does not pay attention towards the proper maintenance of the said plant and controlling of pollution caused by therefrom. A great resentment and worry is prevailing amongst the people over this issue. It is a matter of urgent public importance. Therefore, I request the Government to clarify its position by making a statement in this regard on the floor of the House.

---

## वक्तव्य

### वन मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

**वन मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर) :** 650 मैगावाट क्षमता का पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट, पानीपत-असंध रोड पर पानीपत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी पांच इकाईयां हैं जिनमें से चार इकाईयों की क्षमता 110 मैगावाट प्रति इकाई है और पांचवीं इकाई की क्षमता 210 मैगावाट है । वायु और जल-प्रदूषण सम्बन्धित इकाई का प्रदूषण ब्यौरा निम्नलिखित है :—

**वायु प्रदूषण**

थर्मल पॉवर प्लांट की पूरी क्षमता पर चलाने के लिए 8,600 मिट्रिक टन कोयला और 125 किलोलीटर तेल प्रतिदिन ईंधन के रूप में जरूरत है । थर्मल पॉवर प्लांट की इकाई नम्बर एक और दो में मकैनिकल प्रैसिपिटेटर लगाए हुए हैं जोकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसकी जगह इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रैसिपिटेटर लगाने के लिए प्लांट के अधिकारियों को कहा गया है जिसके लगाने के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीद लिया है । थर्मल पावर प्लांट की इकाई नम्बर तीन में जो इ० एस० पी० लगाए हुए हैं उनकी मुरम्मत की जा रही है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनकी मुरम्मत शीघ्र ही पूरी कराने के लिए कह दिया है ।

थर्मल पॉवर प्लांट की इकाई नम्बर चार और पांच में पहले से ही इ० एस० पी० लगे हुए हैं परन्तु क्योंकि उनके आस-पास की हवा के नमूनों की टैस्ट रिपोर्ट में एस० पी० एम० निर्धारित सीमा से ज्यादा पाए गए थे । इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट के अधिकारियों को इन संयंत्रों को सुधारने के लिए निर्देश दिए हैं ।

थर्मल पॉवर प्लांट में कोयला तोड़ने के लिए दो अनुभाग हैं जो कि एक तो इकाई नम्बर एक से चार और दूसरा इकाई नम्बर पांच के साथ लगे हुए हैं । कोयले की धूल को नियंत्रित करने के लिए प्लांट अधिकारियों द्वारा dust containment system (धूल को रोकने के लिए संयंत्र) और water spray arrangement (पानी का छिड़काव) संयंत्र लगाये जा रहे हैं ।

**जल प्रदूषण**

जहां तक खुखराना, सुताना, आसनकलां, आसन-खुर्द और भादड़ आदि गांव की गलियों में गंदा पानी इकट्ठा होने का प्रश्न है इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पानीपत थर्मल प्लांट के अधिकारियों द्वारा जले हुए कोयले की राख की शलरी (गाद) लम्बी पाईपों द्वारा ऐश पॉड (Ash Pond) में डाली जाती है । राख तो ऐश पॉड में सैटल हो जाती है और उससे पानी निकर कर ड्रेन नम्बर 3 में चला जाता है । कुछ राख भी पानी के साथ बह कर ड्रेन नम्बर 3 में जमा होती जाती है । इसके इलावा पानीपत थर्मल प्लांट से प्रतिदिन 12,000 किलोमीटर गंदा पानी जिसमें कूलिंग टावरज के ओवर फलो का पानी (boiler) ब्वायलर और रिहायशी कलोनियों का गन्दा पानी भी शामिल है ( Untla Drain ) उन्तला ड्रेन में डाला जाता है । कोयले की शलरी के इकट्ठा होने के कारण लिंक ड्रेन, उंतला ड्रेन में chokting से ध्यानाकर्षण नोटिस में वर्णित चार गांवों में पानी फैल जाता है और सिंचाई विभाग इनडेंस की डिसिल्टिंग का काम बिजली बोर्ड के खर्च पर करता है जो कि प्रगति पर है । बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने खुखराना गांव की ओर Ash Dykes के बाहरी बाहर वृक्ष लगाकर 15 मीटर से 20 मीटर चौड़ी एक

[श्री राम पाल सिंह कंवर]

हरी पट्टी बना दी है । वहां पर खड़े सरकण्डों को, जो पहले नीलामी द्वारा बेचा जाता था वह भी पिछले दो साल से नहीं काटा गया है जिससे कोयले की धूल को हवा में उड़ने में बहुत राहत मिली है ।

खुखराना, आसनखुर्द, आसनकलां गांवों में रुके हुए पानी की जो समस्या ध्यान में आई है वह कुछ तो अधिक वर्षा के कारण और कुछ उत्तला ड्रेन में राख जमा होने से रुकने के कारण से भी है । यहां यह कहना भी उचित होगा कि इस क्षेत्र के गांवों में पानी खड़ा होने की जो समस्या है वह पानीपत थर्मल प्लांट शुरु होने से पहले भी थी और इस समस्या को हल करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा खुखराना गांव में खड़े पानी को निकालने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम भी खुखराना गांव के आसपास चार गहरे (डीप) नलकूप लगायेगी जिससे वहां जो वर्षा के कारण पानी का स्तर ऊपर आ जाता है वह समस्या भी हल हो जायेगी ।

कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ध्यानाकर्षण नोटिस में वर्णित गांवों में थर्मल प्लांट से निष्कासित पानी के कारण फसल की बिजाई में कोई देरी नहीं हुई है । इन गांवों में जो भूमिगत पानी का स्तर 60 फुट से 50 फुट तक आ गया है वह केवल थर्मल पावर प्लांट से निष्कासित पानी के कारण ही नहीं बल्कि वर्ष 1993 और 1994 के जुलाई के महीनों में हुई भारी वर्षा के कारण से भी हुआ है । इन गांवों में वर्ष 1993 के जुलाई के महीने में 320.2 मिलीमीटर और जुलाई, 1994 में 354.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी जबकि वर्ष 1992 के जुलाई के महीने में यह केवल 110.5 मिलीमीटर हुई थी ।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न तो इन गांवों में कोई बिमारी फैली है और न ही बिमारियां बढ़ी हैं ।

वर्ष 1993 में ग्राम सुधार समिति खुखराना ने बतौर पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन एक सिविल रिट पैटीशन नं0 4729 आफ 1993, पानीपत थर्मल प्लांट के विरुद्ध दायर की हुई है और इस केस में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायलय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पॉवर प्लांट द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने के कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कार्य को मॉनिटर (Monitor) करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है और उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार यह कमेटी थर्मल पॉवर प्लांट में समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने के कार्य का निरीक्षण भी करती है ।

**श्री सतबीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट के लिए अपनी बात कहूंगा कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह तथ्यों

से बहुत दूर है । अध्यक्ष महोदय, खुखराना, सुताना, आसन कलां और आसन-खुर्द गांव के पास जिस पौंड में लम्बी पाइपों द्वारा कोयले की राख की गाद डालते हैं, वह पौंड बार-बार टूट जाता है और जो राख होती है वह किसानों के खेतों में दो-दो फुट तक जम जाती है । आज खुखराना गांव में ऐसे हालात हैं कि अगर वहां पर पशुओं को बांधने के लिए खूंटा गाड़ें तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है । दूसरे इन्होंने जो बताया है कि वहां पर हरी पट्टी बना रखी है तो मुझे वह पट्टी कहीं पर भी नजर नहीं आई । हो सकता है कि राख की वजह से वह ढक गई होगी इसलिए मुझे नजर नहीं आई होगी । इसी साल फ्लड की वजह से राख खुखरान ड्रेन में चली गई है जिसके कारण उस ड्रेन में आज भी पानी नहीं जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, फ्लड की वजह से हुए नुकसान के नाम पर कुछ प्रभावशाली लोगों को नौकरियां तो दे दी गई लेकिन ऐक्चुअल में जिनका नुकसान हुआ है और जो लोग नौकरियों से वंचित हैं, क्या उनको भी नौकरियां देंगे ? कहीं ऐसा न हो कि वे रह जाएं । अध्यक्ष महोदय, उनको नौकरियां दी जाएं । दूसरे आस-पास के गांवों में जो प्रदूषण फैल रहा है, क्या उनको इससे बचने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ? उन गांवों को बिजली भी नहीं मिल रही है । इसके लिए प्रदूषण बोर्ड और बिजली बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं ? इसके साथ ही इस वजह से जिन लोगों के फेफड़े गल गए हैं और दूसरी बिमारियां लग गई हैं, क्या उनको वह सरकार मुआवजा देने जा रही है ?

**श्री रामपाल सिंह कंवर :** स्पीकर सर, इनको केवल सवाल करना चाहिए था लेकिन इन्होंने तो अच्छा खासा भाषण दे डाला । इन्होंने अपने भाषण में दो-तीन बातें कही हैं । एक तो यह कि उन्सला ड्रेन कोयले की राख से अट गयी है और उसकी सफाई नहीं हुई है । स्पीकर सर, इनकी यह बात सत्य नहीं है । इन ड्रेनों में जब जब भी राख गयी है, जैसा मैंने अपने जवाब में भी बताया है कि इनमें कोयले की राख पानी के साथ जरूर चली जाती है लेकिन हम पानी ट्रीट करके आगे भेजते हैं । मैंने अपने जवाब में यह भी कहा है कि इस पानी के साथ कुछ राख जरूर ड्रेन में चली जाती है लेकिन उसकी सफाई करने के लिए बिजली बोर्ड ने ड्रेनेज डिपार्टमैंट के पास पैसा जमा करवा दिया है । सर, इस साल भी अगर कादियान साहब वहां पर जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि वहां पर हमारी ड्रेग लाइन सफाई करने के लिए लगी हुई है । इस साल में तीनों ड्रेनों की सफाई करने के लिए 3.70 लाख रुपया बिजली बोर्ड ने ड्रेनेज डिपार्टमैंट के पास जमा करा दिया है । लेकिन स्पीकर सर, ज्यों ही वहां पर काम शुरु किया गया तो किसानों ने रिक्वैस्ट की कि आप 15 दिनों तक इस काम को रोक दें क्योंकि तब तक हमारी सारी फसलें कट जाएंगी । इसलिए स्पीकर सर, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाद इस संबंध में तेजी से काम करेंगे । हम जून के अंत तक तीनों ड्रेनों की सफाई करवा देंगे । इसके अलावा, इन्होंने यह भी कहा कि किसानों की खेती भी नहीं हो पायी है । मैं इनको इस बारे में ईयरवाइज बता देता हूं । (विघ्न) आपने

[श्री राम पाल सिंह कंवर]

कहा है कि बिजाई में बहुत देरी हो गयी है । मैं आपको बता देता हूं कि 1994-95 में पैड़ी में खुखराना में तीन हैक्टेयर, सुताना में सिर्फ 0.21 हैक्टेयर, आसनकलां में 13 हैक्टेयर, जाटल में चार हैक्टेयर और आसनखुर्द में दो हैक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर खेती नहीं हो पायी है । इसी तरह से 1994-95 में खुखराना में पांच हैक्टेयर, सुताना में भी दस हैक्टेयर, आसनकलां में दो हैक्टेयर, आसनखुर्द में पांच हैक्टेयर और जाटल में नौ हैक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर शुगरकेन की फसल नहीं हो पायी है । इसी प्रकार से 1994-95 में खुखराना में तीन हैक्टेयर, सुताना में भी तीन हैक्टेयर, आसनकलां में चार हैक्टेयर, आसन खुर्द में दो हैक्टेयर और जाटल में चार हैक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर गेहूं की फसल नहीं हो पायी है । जबकि मेरे साथी कादियान साहब ने कहा है कि सारी जमीन बेकार हो गयी है और कोई खेती नहीं हो रही है । यह फिगर्ज मैंने दी हैं जिससे पता चलता है कि कितनी जमीन ऐसी है जिसमें फसल नहीं हो पायी है । अगर इससे अधिक रकबा जिसमें फसल नहीं हुई है, रह गया है और वह इनके नालेज में है तो यह हमें बता दें । स्पीकर सर, एक बात तो हो सकती है कि किसी कारण से किसी फसल की बिजाई में देरी हो सकती है, यह बात तो मैं मान सकता हूं लेकिन यह कहना कि बिजाई बिल्कुल नहीं हो रही है, यह मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैंने आपके सामने फिगर्ज दी हैं कि इतना इतना रकबा है जिसमें बिजाई नहीं हो सकी है । इसके अलावा, इन्होंने दूसरा सवाल किया कि पानी का लैवल नीचा होना चाहिए । स्पीकर सर, एम0 आई0 डी0 सी0 ने वहां पर चार ट्यूबवैल्ज लगाने का प्रावधान किया हुआ है जब वह ट्यूबवैल्ज लगेंगे और पानी को ऊपर खींचेंगे तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा । जो पानी ऊपर आ रहा है, ऐसा होने से लाजिमी तौर पर पानी ऊपर आने से रुक जाएगा ।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, आप पर्सनली वहां पर विजिट करें क्योंकि खुखराना में वास्तव में यह प्राब्लम है । वह एक छोटा गांव है, अगर उस गांव को कहीं दूसरी जगह पर जमीन ऐक्वायर करके बसाया जा सकता हो तो ऐसा अवश्य करें क्योंकि केवल तीन चार एकड़ जमीन में ही काम चल जाएगा और फिर उस गांव के लोग दूसरी जगह पर बसने के लिए तैयार भी हैं ।

**श्री रामपाल सिंह कंवर :** स्पीकर सर, मैंने अपने जवाब में खुद माना है कि वहां पर प्राब्लम है लेकिन मैंने अपने जवाब में इस प्राब्लम को हल करने के लिए भी बताया है कि थर्मल प्लांट का जो पानी जा रहा है, उसके बारे में उनसे कहा गया है कि आप इस पानी को ट्रीट कीजिए और अन ट्रीटेड पानी को न चलाईये ।

स्पीकर सर, इस साल भी हमें बिजली बोर्ड ने इसके लिए आश्वासन दिया है कि जो सिवरेज वगैरह का गंदा पानी जा रहा है, उसके लिए उन्होंने बीस लाख रुपये इस साल रखे हैं और कहा है कि वे पानी को ट्रीट करके ही चलाएंगे । इसी तरह से जो थर्मल प्लांट की यूनिट नम्बर एक और दो हैं, उसके लिए भी बीस लाख रुपये खर्च किए गए हैं ताकि जो वहां पर पानी का ट्रीटमैंट करने के लिए मशीन लगी हुई हैं, उनमें कुछ कमी आ गयी है, कुछ पुरानी हो गयी हैं, उनकी री-कंडीशन किया जा सके । इसी प्रकार से यूनिट नम्बर 2 के लिए अब तीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । यह प्रोजैक्ट हमने पॉवर फाइनैंस कार्पोरेशन से क्लीयर करवा लिया है, उन्होंने केस वर्ल्ड बैंक को भेज दिया है । उम्मीद है कि 2-3 महीने में वर्ल्ड बैंक से क्लीयर हो जाएगा । क्लीयर होने के बाद इस पर काम शुरु करा दिया जाएगा । इसी प्रकार से सीवर कंस्ट्रक्शन वर्क तकरीबन कंपलीट हो चुका है । इसी प्रकार से ई0 एस0 पी0 के लिए बी0 एच0 ई0 एल0 से 10.2 करोड़ का सामान थर्मल पॉवर प्लांट में आ चुका है, यह प्रौसेस जारी है, ज्यों-ज्यों सामान आता जायेगा, काम करवाते रहेंगे ताकि प्रदूषण न फैल सके । यूनिट-5 का ई0 एस0 पी0 का काम कम्पलीट हो चुका है, यूनिट-4 के ई0 एस0 पी0 को सुधारने का काम हो जाएगा । चौथी यूनिट की ओवरहालिंग . . . (विघ्न)

**श्रीमती चन्द्रावती :** उस गांव में सफाई कैसे कराएंगे, इस बारे में बोलिए ? बिजली के बारे में मत बोलिए ।

**श्री अध्यक्ष :** बहिन जी, ये समाधान की बात ही कह रहे हैं ।

**श्री रामपाल सिंह कंवर :** स्पीकर सर, जब तक मैं यह नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या स्टैप्स लिए जा रहे हैं तो प्रदूषण कैसे रुकेगा । (विघ्न) जून के एंड तक सफाई करा दी जाएगी । स्पीकर सर, इसी प्रकार से कोयले के कॉलिंग सैक्शन के अंदर स्प्रे सिस्टम इंस्टाल हो चुका है । टैलीस्कोप एक महीने के अंदर लगा दिया जाएगा, इस टैलीस्कोप से यह होगा कि जहां कोयला टूटता है, उसकी राख उड़ती है, वह राख कम से कम उड़े, जितनी ऊंचाई पर उसकी जरूरत है, उतनी ऊंचाई पर सैट हो सकता है, उसको सैट करने के बाद कोयले की राख को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है ।

**बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) :** स्पीकर सर, सतबीर सिंह काढियान जी की जो दो-तीन शंकाएं थी, उनके बारे में मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया । जो थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, उनका मैं निवारण कर देता हूं । एक तो ऐश डाइक है, उसकी सतह कच्ची है, इस वजह से सारा पानी बह जाता है । हमने नयी ऐश डाइक्स की कंस्ट्रक्शन दो अढ़ाई महीने से शुरु कर दी है । जब वह पूरी बन जाएगी तो उसके चारों ओर ग्रीन बैल्ट बना दी जाएगी ताकि आस पड़ोस के गांवों में जो नुकसान हो रहा है, फिर वह न हो । दूसरे, फर्स्ट और सैकेण्ड यूनिट के लिए 10

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

करोड़ रुपए का सामान हम खरीद चुके हैं। इसके अलावा, 20 करोड़ रुपया बहुत जल्दी ही पॉवर फाइनैंस कार्पोरेशन से मंजूर होने वाला है। पूरे 30 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं। यह जो राख इनवीरनमैंट को खराब कर रही है, इसके लिए 30 करोड़ रुपया फर्स्ट एण्ड सैकिण्ड यूनिट पर इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। 20 से 30 लाख रुपये के मैकेनिकल प्रैसिपिटेटर होते हैं, वे उन पर लगाएंगे ताकि जब भी उनको रिप्लेस करें तो आसपास के एरिया का वातावरण खराब न हो। तीसरी बात मैं कादियान साहब को बताना चाहूंगा कि यह जो पानी बहकर चला जाता है, हर साल सफाई के लिए हम इरीगेशन डिपार्टमैंट के पास पैसा डिपोजिट करते हैं, अब भी पैसा डिपोजिट किया हुआ है, काम चालू है और इसके लिए बिजली बोर्ड बाकायदा जागरूक है। प्रदूषण से जो गंदगी फैल रही है, इसकी रोकथाम के लिए हम पूरी तरह से जागरूक हैं और बहुत जल्दी समाधान होगा।

**श्री अध्यक्ष :** खुखराना गांव में थोड़ी सी आबादी है, वहां के लोग कह रहे हैं कि जमीन ऐक्वायर करके हमें थोड़ी-सी दूरी पर बसा दो। क्या आप इस बारे में सोचेंगे क्योंकि वह सस्ता भी पड़ेगा।

**11.00 बजे**

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :** अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि खुखराना गांव के लोग कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी दूरी पर जमीन एक्वायर करके बसा दें। अगर वे लोग चाहते हैं कि उनको दूसरी जगह बसा दिया जाए तो हम उन भाईयों से बातचीत करके डी0 सी0 के जिम्मे यह काम लगाएंगे ताकि वे खुद भी उन लोगों से पूछ लें और उनसे जगह का भी पूछ लें कि कौन सी जगह पर उनको बसाया जाए। अगर यह छोटा सा सारा गांव सहमत हो गया तो हम उन लोगों को दूसरी जगह पर बसा देंगे।

**श्री सतबीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, 'प्रदूषण मन्त्री' ने यह माना है और चौ0 बीरेन्द्र सिंह जी ने भी यह माना है कि वे प्रैसिपिटेटर को मकैनिकल की जगह इलैक्ट्रोस्टेटिक कर रहे हैं। इसके इलावा उन्होंने यह भी बताया है कि 10 कंटेनर्ज हैं, फव्वारे हैं, स्प्रेयर्ज हैं, वे लगातार रेगुलरली चल रहे हैं लेकिन मेरे नोटिस में यह बात है कि नहीं चल रहे, काम नहीं करते, इसलिये राख़ी जाती है उसके कारण से प्रदूषण है। इसके इलावा, एक और क्लैरीफिकेशन मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा। जैसाकि आपके अनुरोध पर उन्होंने मान लिया है कि पांच एकड़ जमीन देकर उन लोगों को कहीं दूसरी जगह पर बसाया जाएगा तो मैं सरकार से कहूंगा कि जो लोग उजड़ेंगे, क्या उनको उनकी कंस्ट्रक्शन के लिये सरकार कुछ मदद करेगी? जिस तरह से कहीं जमीन एक्वायर सरकार करती है तो उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाता है। इसके साथ-साथ मैंने जो नौकरियों के बारे पूछा था, उसका

उत्तर नहीं आया, स्पीकर साहब क्या नौकरियां भी उनको देंगे या नहीं देंगे ? इस तरह का आश्वासन इनसे लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, जो नौकरी लगे हुए हैं, उनको हटाएंगे नहीं ।

श्री रामपाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, अभी कादियान साहब ने 'प्रदूषण मन्त्री' का जिकर किया । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हम तो प्रदूषण रोकते हैं और इन्होंने तो सियासी प्रदूषण फैला दिया है । इसको हम कैसे हटाएंगे ? (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारी जो पिछली सरकार थी, उसमें चौ० वीरेन्द्र सिंह जी भी मन्त्री थे । उस समय आसन कलां और आसन खुर्द गांव के बिजली के कनैक्शंज डायरैक्ट हुआ करते थे और इस सरकार ने आकर वह कनैक्शन काट दिये । क्या इन गांवों को जोकि बिजली की चमक दमक हर वक्त देखते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है, कम से कम बिजली तो सरकार दे दे, और कुछ नहीं दे सकती तो इतना तो सरकार कर दे, क्योंकि उन हरिजन बस्तियों में बुरी तरह से प्रदूषण फैल रहा है । पानी खड़ा हुआ है और बीमारियां फैल रही हैं । इसलिये इन गांवों के लोगों को सरकार कुछ तो राहत दे । इस तरह का आश्वासन सरकार की तरफ से आना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर ऐसी कोई बात है और कनैक्शंज काट लिये गये हैं तो इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे । ऐसी कोई बात कादियान साहब नहीं है । आप मुझे मिल लेना, बात कर लेंगे ।

---

## समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

### (i) लोक लेखा समिति

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members as you know, the leave of absence has been granted by the House to Shri Hari Singh Nalwa, Chairman, Committee on Public Accounts and therefore, he is not present in the House. Under Rule 223 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I, therefore permit Shri Ram Bilas Sharma, a member of the Committee to present the Thirty Ninth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1994-95, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1989-90.

प्रो० राम बिलास शर्मा (सदस्य, लोक लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के लिये हरियाणा के विनियोग लेखों, वित्तीय लेखों पर लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं ।

(ii) आश्वासन समिति

**Mr. Speaker** : Honble Members, Shri Dhir Pal Singh, Chairman, Committee on Government Assurances is not present. Therefore, I permit Mohd. Aslam Khan, a member of the Committee to present Twenty Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1994-95.

**Mohd. Aslam Khan** (Member, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Twenty Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1994-95.

(iii) अनुसूचित जातियों तथा जनजाति कल्याण समिति

**Mr Speaker** : Now Shri Lehri Singh, Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes will present the Twentieth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1994-95.

**Sathi Lehri Singh** (Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) : Sir, I beg to present the Twentieth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1994-95.

(iv) आकलन समिति

**Mr. Speaker** : Now Shri Suraj Mal, Chairman, Committee on Estimates will present the Twenty Seventh Report of the Committee on Estimates for the year 1994-95.

**Ch. Suraj Mal** (Chairman, Committee on Estimates) : Sir, I present the Twenty Seventh Report of the Committee on Estimates for the year 1994-95.

---

## वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

**Mr. Speaker** : Hon'ble Members, now discussion and voting on the demands for grants on Budget for the year 1995-96 will take place. As per past practice and to save the time of the House, all the demands on the order paper (1 to 25) on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon. Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs. 2,94,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 1—*Vidhan Sabha*.

That a sum not exceeding Rs. 61,94,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 2—*General Administration*.

That a sum not exceeding Rs. 1,87,44,12,000 for revenue expenditure and Rs. 4,95,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 3—Home.*

That a sum not exceeding Rs. 26,24,83,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 4—Revenue.*

That a sum not exceeding Rs. 16,81,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 5—Excise & Taxation.*

That a sum not exceeding Rs. 1,57,85,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 6—Finance.*

That a sum not exceeding Rs. 16,68,78,70,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 7—Other Administrative service.*

That a sum not exceeding Rs. 97,85,59,000 for revenue expenditure and Rs. 92,96,33,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 8—Buildings & Roads.*

That a sum not exceeding Rs. 5,45,56,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 9—Education.*

That a sum not exceeding Rs. 2,53,96,31,000 for revenue expenditure and Rs. 76,05,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 10—Medical & Public Health.*

That a sum not exceeding Rs. 17,39,91,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 11—Urban Development.*

That a sum not exceeding Rs. 35,47,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 12—Labour & Employment.*

That a sum not exceeding Rs. 2,36,83,85,000 for revenue expenditure and Rs. 2,57,27,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.*

That a sum not exceeding Rs. 8,76,38,000 for revenue expenditure and Rs. 3,67,00,16,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 14—Food & Supplies.*

That a sum not exceeding Rs. 4,55,82,20,000 for revenue expenditure and Rs. 1,81,27,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 15—Irrigation.*

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs. 33,31,49,000 for revenue expenditure and Rs. 36,29,57,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 16—Industries.*

That a sum not exceeding Rs. 1,41,39,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 17—Agriculture.*

That a sum not exceeding Rs. 42,61,19,000 for revenue expenditure and Rs. 11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 18—Animal Husbandry.*

That a sum not exceeding Rs. 10,68,50,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 19—Fisheries.*

That a sum not exceeding Rs. 56,39,52,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 20—Forest.*

That a sum not exceeding Rs. 69,35,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 21—Community Development.*

That a sum not exceeding Rs. 18,63,29,000 for revenue expenditure and Rs. 14,50,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 22—Co-operation.*

That a sum not exceeding Rs. 2,93,89,56,000 for revenue expenditure and Rs. 42,33,70,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 23—Transport.*

That a sum not exceeding Rs. 27,00,000 for revenue expenditure and Rs. 3,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 24—Tourism.*

That a sum not exceeding Rs. 3,63,53,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.*

I have also received notices of cut motions to the various demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, I will put the various cut motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such members may, however, participate in the discussion.

**Demand No. 2**

1. **Shri Bansi Lal,**
   **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.As.** :

That Demand No. 2 of Rs. 61,94,94,000 on account of General Administration be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 3**

2. **Shri Bansi Lal,**
   **Shri Om Parkash Beri, M.L.As.**

That Demand No. 3 of Rs. 1,92,39,12,000 on account of Home be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 5**

3. **Shri Ram Bhajan,**
   **Shri Om Parkash Beri, M.L.As.**

That Demand No. 5 of Rs. 16,81,11,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 6**

4. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.**

That Demand No. 6 of Rs. 1,57,85 85,000 on account of Finance be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 8**

5. **Shri Bansi Lal,**
   **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.As.**

That Demand No. 8 of Rs. 1,90,81,92,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 9**

6. **Shri Chhattar Singh Chuahan,**
   **Shri Om Parkash Beri, M.L.As.**

That Demand No. 9 of Rs. 5,45,56,03,000 on account of Education be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 10**

7. **Shri Bansi Lal,**
   **Shri Om Parkash Beri, M.L.As.**

That Demand No. 10 of Rs. 3,30,02,06,000 on account of Medical and Public Health be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 11**

8. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.** :

That Demand No. 11 of Rs. 17,39,91,000 on account of Urban Development be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 13**

9. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.** :

That Demand No. 13 of Rs. 2,39,41,12,000 on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Re. 1/-.

[Mr. Speaker]

**Demand No. 14**

10. **Shri Bansi Lal, M.L.A.** :

That Demand No. 14 of Rs. 3,75,76,54,000 on account of Food & Supplies be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 15**

11. **Shri Bansi Lal,**
**Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.** :

That Demand No. 15 of Rs. 6,37,09,20,000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 16**

12. **Shri Bansi Lal, M.L.A.** :

That Demand No. 16 of Rs. 69,61,06,000 on account of Industries be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 17**

13. **Shri Bansi Lal,**
**Shri Chhattar Singh Chauhan,**
**Shri Om Parkash Beri, M.L.As.** :

That Demand No. 17 of Rs. 1,41,39,11,000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 18**

14. **Shri Om Parkash Beri, M.L.A.** :

That Demand No. 18 of Rs. 42,63,30,000 on account of Animal Husbandry be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 22**

15. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.** :

That Demand No. 22 of Rs. 33,13,38,000 on account of Cooperation be reduced by Re. 1/-.

**Demand No. 23**

16. **Shri Bansi Lal,**
**Shri Om Parkash Beri, M.L.As.** :

That Demand No. 23 of Rs. 3,36,23,26,000 on account of Transport be reduced by Re 1/-.

**Demand No. 24**

17. **Shri Bansi Lal, M.L.A.** :

That Demand No. 24 of Rs. 3,79,00,000 on account of Tourism be reduced by Re. 1/-.

**मोहम्मद असलम खां (छछरौली)** : स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैं सब से पहले अपने हल्के मतलिक कुछ बातें कहना चाहता हूं । इससे पहले हमारे बहुत साथी गवर्नर ऐड्रैस पर भी बोले लेकिन आज विपक्ष के ज्यादा साथी मौजूद नहीं हैं । वे यहां पर हथनी कुंड बैराज के ऊपर काफी बोले । वह मेरी कांस्टीच्यूएंसी में बनने जा रहा है । इन्होंने एतराज उठाया कि यह समझौता करके मख्यमुन्त्री जी ने हमारा पानी कम कर दिया है । लेकिन इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि पिछले चार या साढ़े चार साल इनकी सरकार रही और मैं हर सैशन के अन्दर हथनी कुंड बैराज को बनाने के बारे में बोलता रहा । वह बहुत ही अहमियत रखता है । यह तीन प्रदेशों के लिए बहुत जरूरी था जिसमें यू0 पी0 ,हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं । ताजे वाला हैड वर्कस 1870 का बना हुआ है । वह इतना पुराना हो चुका है कि किसी वक्त भी टूट सकता है । वर्ष 1978 में और 1988 में इनकी सरकार थी और दोनों सालों में बहुत बड़ा फ्लड आया था जिससे बहुत नुकसान हो सकता था । उससे यू0 पी0 और हरियाणा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी । तो हथनी कुंड बैराज का जो समझौता हमारे मख्य मन्त्री जी ने किया है यह बहुत मेहनत और कोशिश से किया है । यह कोई छोटा काम नहीं था । इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा । इससे केवल मेरे इलाके को ही फायदा नहीं मिलेगा बल्कि पूरे प्रदेश को मिलेगा । इसके बनने से 14 हजार क्यूसिक की बजाए हम 28000 क्यूसिक तक पानी इकट्ठा कर सकते हैं जिससे बहुत लाभ होगा । पहले हमें जो फ्लड का खतरा रहता था वह इसके बनने से खत्म हो जाएगा । जैसे मैंने पहले कहा कि 1978 में ऐसे हालात हो गए थे कि हमें बहुत खतरा हो गया था । वह तो सौभाग्य से यू0 पी0 की तरफ एक ब्रीच हो गई थी जिस वजह से पानी उधर चला गया था और हमारा बचाव हो गया था । इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं । दूसरे मैं वाटर सप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं । ज्यों ही हमारी यह सरकार आई, मेरी कांस्टीच्यूएंसी के गांव पहाड़ के साथ लगते हैं उनमें पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी । हमारी सरकार बनी और मैंने सरकार से बार-बार अनुरोध किया कि फलां गांव के लिए फलां जगह वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबवैल लगाया जाना चाहिए और फलां जगह लगाया जाना चाहिए । मुझे खुशी है कि मेरे हल्के के सभी गांवों को पीने के पानी की सुविधा मिल गई है लेकिन अब सिर्फ एक गांव ऐसा रह गया है जिसमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है । उसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उस गांव में बहुत जल्दी ही वाटर सप्लाई स्कीम पहुंचा देंगे । स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने जो पहाड़ी की तलहटी में कंडी प्रोजैक्ट बनाया है वह बहुत ही अच्छा काम किया है । उस प्रोजैक्ट का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की देखरेख में चल रहा है । हमारे कृषि मंत्री श्री हरपाल सिंह जी वहां जाते रहते हैं । उस प्रोजैक्ट की काफी अच्छी प्रोग्रैस है । एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस

[मोहम्मद असलम खां]

प्रोजैक्ट में कुछ गांव और शामिल कर लिए जाएं जोकि उस प्रोजैक्ट में आते हैं। हम उन गांवों की लिस्ट बना कर मंत्री महोदय को भेज देंगे। उन गांवों को उस प्रोजैक्ट का फायदा पहुंच सकता है। यदि उन गांवों को उस प्रोजैक्ट में शामिल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर बात होगी। स्पीकर साहब, यहां पर शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड के बारे में चर्चा की गई और कहा गया कि वह बोर्ड कालका हल्के की डिवैल्पमैंट के लिए बनाया गया है। लेकिन वह बोर्ड केवल कालका की डिवैल्पमैंट के लिए नहीं बनाया गया है उसमें मेरी कांस्टीच्यूएंसी छछरौली भी शामिल है। शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड की तरफ से डिवैल्पमैंट के लिए जितना पैसा गया है वह छछरौली ब्लॉक में ज्यादा गया है। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी का काफी मशकूर हूं कि मेरे हल्के में उस बोर्ड की तरफ से काफी पैसा दिया जा रहा है। केवल यह बात नहीं है कि शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड कालका की डिवैल्पमैंट के लिए ही बनाया गया है उसमें बिलासपुर ब्लॉक, सिंढोरा ब्लॉक और छछरौली ब्लॉक भी शामिल है। उन सभी ब्लॉक्स को उस बोर्ड का फायदा पहुंच रहा है। एक चीज की तरफ मैं सरकार की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि डाइट प्रोग्राम के अन्तर्गत यह कहा गया था कि हर जिले में एक जे0 बी0 टी0 सैंटर खोला जाएगा। जिस समय यह प्रोग्राम बनाया गया था उस समय 12 जिले थे और उसके बाद चार नए जिले और बना दिए गए। यमुनानगर जिला भी उन नए जिलों में शामिल है। यमुनानगर जिले के हम पांच एम0 एल0 एज0 ने सरकार को यह लिख कर दिया है कि वह सैंटर उस गांव में खोल दिया जाए और वह गांव मेरी कांस्टीच्यूएंसी का आखिरी गांव है जहां पर यह जे0 बी0 टी0 सैंटर खोला जाएगा। उसके लिए उस गांव की पंचायत ने जितनी जमीन चाहिए थी उसका रैजोल्यूशन पास करके दे दिया है। हमारी सरकार ने उसकी मंजूरी के लिए केस भारत सरकार को भेज रखा है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि सरकार उसको परसू करे ताकि वह सैंटर जल्दी से जल्दी खोला जा सके। स्पीकर साहब, मार्किट कमेटीज हर जगह बनी हुई हैं और उनका अपना बजट होता है। यदि कोई मार्किट कमेटी यह रैजोल्यूशन पास करके एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के पास भेजती है कि फलां जगह सड़क बनाई जाए या फलां सड़क की रिपेयर की जाए तो यहां से उस रैजोल्यूशन का कोई जवाब नहीं जाता है जिसके कारण मार्किट कमेटी न कोई नई सड़क बना पाती है और न किसी सड़क की रिपेयर कर पाती है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी मार्किट कमेटी की तरफ से ऐसा कोई रैजोल्यूशन पास हो करके आए कम से कम एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड उसका जवाब तो अवश्य दे दे कि वह सड़क बननी है या नहीं और किसी सड़क की रिपेयर करवानी है या नहीं। लेकिन मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से उसकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी मार्किट कमेटी ने वहां पर एक डेढ़ किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बनाने के बारे में रैजोल्यूशन पास करके चार साल पहले

एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड को भेजा हुआ है लेकिन उसके बारे में यहां से कोई जवाब नहीं गया है । जबकि उस मार्किट कमेटी के पास फालतू बजट पड़ा है । बिजली बोर्ड को पैसे दे रहे हैं लेकिन सड़कें बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं । सजराबाद से बिलासपुर के लिए जो सड़क है वह केवल आधा किलोमीटर का टुकड़ा बनना है । बिलासपुर एक बड़ा कस्बा है और वहां की अनाज मंडी में बहुत अनाज आता है । वह आधा किलोमीटर सड़क बननी है उसके बारे में चार साल से लिख कर भेजा हुआ है लेकिन एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड कोई तवज्जो नहीं दे रहा है । इसी तरह से छीग से कलावाला सड़क बनाने के लिए तीन साल पहले का वहां की मार्किट कमेटी ने रैजोल्यूशन पास करके यहां पर एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के पास भेजा हुआ है, उसका भी कोई जवाब नहीं गया है । मैं सरकार से अर्ज करना चाहूंगा कि उन सड़कों को पूरा करवाया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहिन करतार देवी जी बैठी हैं। इनके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में बहुत से सब सेंटर बनाये हुए हैं लेकिन वहां पर मेल या फीमेल डाक्टर कोई भी नहीं लगा हुआ । मेरी आपके माध्यम से इनसे प्रार्थना है कि वहां पर जिसको वे भेजना चाहें, भेज दें, ताकि जो अच्छी बिल्डिंगें वहां पर बनी हुई हैं, जो पूरी कम्पलीट हैं उनका फायदा उठाया जा सके और लोगों को चिकित्सा की सुविधा हो सके । अन्त में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**चौधरी बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का एक प्रोसिजर है । हाउस रूल्ज के तहत चलता है । माननीय सदस्य जनरल बजट पर स्पीच कर चुके हैं । आज डिमांडज भी हैं और उसके बाद लैजिस्लेटीव बिजनैस भी है । कायदे कानून में कन्वैंशन है कि पहले उनको टाईम मिलना चाहिए जिन मैम्बर्ज की तरफ से कट मोशंज हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन मैम्बर्ज ने कट मोशंज दी हुई हैं, क्या उनको बोलने का टाईम मिलेगा ?

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बैठिये, टाईम मिलेगा ।

**श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांडज पर बोलना चाहती हूं सरकार जो डिवैल्पमैंट के काम करती है, उसके लिए पैसा मांगा है, मैं इसके हक में बोलना चाहती हूं और कुछ सुझाव भी दूंगी । जो कमियां हैं, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमैंट के बारे में बोलना चाहती हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जो मैम्बर्ज के पैड हमें पैसे लेकर दिए जाते हैं, इन पर आधे पैडज पर नाम हैं, आधे पर नहीं हैं। हमने इस बारे में कई बार कमेटी में भी जिक्र किया है । हमें अबकी बार दो पैन पैंसिल प्रेजैंट किए गए । जो कागज इन लिफाफों का है, उस पर लिखते समय स्याही फैलती है ।

[श्रीमती चन्द्रावती]

हमारे द्वारा बार बार कहने पर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा । इसके अलावा, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की जो हिन्दी की रिपोर्ट है, वह मैं लाना भूल गई, उस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उसकी पेजिंग भी ठीक ढंग से नहीं है । उसमें 60 के बाद 168 पेज लगा हुआ है । इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इसमें सरकार का कोई खर्चा भी नहीं है क्योंकि हम ये पेज पैसे देकर खरीद रहे हैं । ये पेज मैं लेकर आई हूं, यह सैम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहती हूं । डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं शिक्षा के विषय पर बोलते हुए कहना चाहती हूं कि मेरे इलाके में स्कूल अपग्रेड किए हैं, उनके लिए सरकार का धन्यवाद । मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे इलाके में कुछ स्कूल, कॉलेज या आई0 टी0 आई0 और भी बनाने की जरूरत है । लोहारू एक छोटी जगह है । शिक्षा के ऊपर पैसा लगता है यह जायज बात है, इसलिए मैं इस डिमाण्ड के हक में हूं । शिक्षा के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है । इसके साथ मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि लोहारू में आई0 टी0 आई0 की बिल्डिंग बननी चाहिए । लोहारू एक छोटी जगह है इसलिए वहां पर स्टाफ के रहने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए । जिनको वहां पर लगाया जाता है वे वहां पर रहते नहीं हैं । जिस प्रिंसिपल को लगाया जाता है वह वहां पर रहता नहीं अभी पीछे एक प्रिंसिपल ने यह लिख दिया कि वहां पर आई0 टी0 आई0 की जरूरत ही नहीं है । वह मामला शायद अभी चल रहा है । मैं चाहती हूं कि वहां पर आई0 टी0 आई0 की बिल्डिंग बनवा दी जाए तो मेहरबानी होगी । आई0 टी0 आई0 में व्यावसायिक सब्जैक्टस को शामिल किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो स्कूल अपग्रेड किए हैं, उनके अलावा पत्थरवा, भाखड़ा, मण्डोली खुर्द बड़े-बड़े गांव हैं इनमें प्राईमरी स्कूलज हैं, इन गांवों में कम से कम एक हाई स्कूल जरूर होना चाहिए । भाखरा में हाई स्कूल होना चाहिए, पत्थरवा में मिडल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी हमारे यहां एक गुरूकुल है, जिसकी चारदीवारी के लिए मुख्य मन्त्री जी कह कर आए थे लेकिन वह पैसा अभी तक मिला नहीं है, वह गुरूकुल बाढड़ा में है इसका पैसा भी आना चाहिए । विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक ऊन का मिल है, वह मिल चलता है या नहीं चलता; इसके बारे में तो मुझे समझ में नहीं आता है । किसी दिन जाएं तो वहां पर 2-4 कर्मचारी काम करते हुए मिल जाएंगे और किसी दिन जाएं तो वह मिल बन्द मिलता है । इस बारे में मेरी सरकार से तथा मन्त्री जी तथा मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त है कि इस मिल को अच्छी तरह से चलाएं उससे लोगों को कुछ रोजगार मिल जाएगा । इस इलाके में कोई और फैक्टरी वगैरा तो है नहीं इसलिए इस मिल को अच्छी तरह से चलाएं तो मेहरबानी होगी । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पीने के पानी के बारे में कहना चाहती हूं । मैंने इस बारे पहले भी बहुत बार कहा है उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है । अब गर्मी का

मौसम आ रहा है । कुछ गांवों में पानी नहीं पहुंचता है । इस बारे में मेरा एक सवाल भी था । भिट्ठी गांव में 10 अक्तूबर को पानी गया था और वह 18 अक्तूबर तक चला उसके बाद पानी नहीं आया । 26 से 30 तारीख तक वहां पर पानी नहीं था । मैंने पानी न होने के बारे जब काफी रौला मचाया तो पानी अब शायद वहां कुछ गया है । अमरवास, सैणीवास, सालवा, ढाणी भरवरा में पीने के पानी का बुरा हाल है । अब गर्मियां आ रही हैं इसलिए आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से मेरी अर्ज है कि मण्डोली, सुरपुरा, बदवाना, मोरका आदि गांवों में पानी की सप्लाई बारे ध्यान दें । पहले तो इन गांवों में बहुत पानी आता था यहां तक कि राजस्थान के लोग भी यहां से पानी ले जाते थे । सुखिवास गांव में भी पानी का बहुत बुरा हाल है । शान्ति राठी जी ने भी इस बारे में कहा था । नहर पीछे से आती है और नहर का पानी काट लिया जाता है जिससे आगे पानी पहुंचता नहीं है और लोगों को दिक्कत होती है । नहर काटने वालों को चैक किया जाना चाहिए और उन पर जुर्माना भी होना चाहिए । इन नहरों में पानी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि भीम डैम का पानी न मिले । गाद का जिक्र भी बार-बार यहां पर आया है, मैं तो यह भी कहती हूं कि यदि हम सारे कांग्रेस वाले मिल कर वालंटरी तौर पर नहरों की गाद निकालना शुरु कर दें तो उनकी गाद निकल जाए । उपाध्यक्ष महोदय, दुख की बात है कि गाद निकालने के लिए जो पैसा था, उसमें से पैसा खा लिया गया । मैं उसका यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगी लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि 10 साल से नहरों की गाद नहीं निकाली गई है, इसीलिए पंजाब से पानी कम आता है । बेरला पम्प हाउस के बारे में भी मेरा एक सवाल था, मैंने इस बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिया था । कहीं पानी ज्यादा आता है और कहीं पानी की कमी होती है । उस पानी की कमी को दूर कर दें । अगर आप इसके प्रति थोड़े से विजिलैंट रहें तो यह कमी दूर हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, एक तो छुट्टियां इतनी हो जाती हैं कि अगर घण्टों का हिसाब लगाया जाए तो 365 दिन में 7 दिन भी नहीं बैठते हैं । अब दोनों मियां-बीबी अफसर हैं और उनमें से एक के साथ भी नाराजगी हो जाए तो दूसरा भी काम नहीं करता है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनमें से एक को दूसरी स्टेट में लगाएं तो उनको पता चलेगा कि काम कैसे होता है । उपाध्यक्ष महोदय, बात करते समय एक ये सर जी, मैडम जी, का प्रयोग करते हैं, पता नहीं यह क्या बोलते हैं । सर अंग्रेजी में है और जी हिन्दी में है, अगर इन्हें अंग्रेजी ही बोलनी है तो कम से कम पूरी बोलें ।

इसी के साथ मैं आपके माध्यम से इनकी नौलिज में सड़कों की बात भी लाना चाहती हूं कि सड़कों में सुधार हुआ है । जिन गांवों में सड़कें नहीं बनी थीं लेकिन अब वे बनी हैं । लेकिन ढिगावा गांव को जो सड़क जाती है, उसका बहुत ही बुरा हाल है । जो सड़कें कस्बों में जाती हैं उनके साथ-साथ नाली बननी चाहिए । जब हम कोई सड़क बनाने को कहते हैं तो कोई कहता है कि पंचायत बनाएगी और कोई

[श्रीमती चन्द्रावती]

कहता है कि मार्किट कमेटी बनाएगी । मैं तो यह कहती हूं कि सबको मिलकर यह काम करना चाहिए । भिवानी और लोहारू की सड़कें हैं, वह बहुत ही लम्बी हैं । जब हम दिल्ली को जाते हैं तो झज्जर से हो कर जाते हैं और बहकला गांव रास्ते में पड़ता है । वहां पर सड़क का बहुत ही बुरा हाल है । ये अफसर तो वहां जाते नहीं हैं, अगर जाते भी हैं तो इनकी अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं और ये सरकारी गाड़ियों में होते हैं जिससे इनको कोई असर नहीं पड़ता है । वहां पर पानी आने की वजह से सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है ।

**सिंचाई मंत्री** (चौधरी जगदीश नेहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है जो भी मैम्बर बोलें वह डिमांड नं0 बोल कर बोलें ताकि हमें यह पता चले कि वे किस डिमांड पर बोल रहे हैं । इसमें लैक्चर का तो कोई काम नहीं है, ये पहले बजट पर भी बोल चुके हैं, गवर्नर एड्रैस पर भी बोल चुके हैं । अब ये सिर्फ डिमांड पर ही बोलें ताकि हमें भी बात समझ आए और कन्सर्नड मन्त्री जवाब भी दे सके । (शोर एवं व्यवधान)

**प्रो0 राम विलास शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है । मैं नेहरा जी को यह कहना चाहूंगा कि माननीय चन्द्रावती जी सबसे सीनियर मैम्बर हैं । नेहरा जी आप हमें तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह क्यों भूल जाते हैं कि बहन जी हमारे में से नहीं हैं, यह आप में से ही हैं । वित्त मन्त्री जी को तो यह नोट करना चाहिए, जो मैम्बर साहिबान बोल रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने श्री असलम खां जी से डिस्कशन शुरू करवायी, इसमें अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का सवाल नहीं है । ये बार बार डिमांड का नाम लेकर हैकल कर रहे हैं ।

**Mr. Deputy Speaker** : There is no question of hackling. He is only making a suggestion.

**प्रो0 छतर सिंह चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कट मोशन दी गई है, यह हमारी तरफ से दी गई है और इन पर हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिये जबकि हमें मौका नहीं दिया गया है, हम इस बारे में आपकी रूलिंग चाहेंगे ।

**Mr. Deputy Speaker** : Discussion on Demands and discussion on cut motions will take place simultaneously. Members may speak either on demands or cut motions. It is their option.

**श्रीमती चन्द्रावती** : डिप्टी स्पीकर सर, मैंने पहले ही कहा है कि कुछ बातें तो मैं जरूर दोहराऊंगी क्योंकि प्यासे आदमी को जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वह पानी पानी ही कहेगा । मैं कहना चाहती हूं कि आज जो

जीपें चलती हैं, जुगाड़ चलते हैं, उनको पुलिस वाले या आर0 टी0 ओ0 मन मानी करके खड़े कर लेते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि या तो आप उनको रैगुलराईज कर दीजिए या फिर इनको बंद कर दीजिए। मैं आपको इस बारे में एक केस बताना चाहूंगी कि होली से एक दिन पहले नारनौल की एक जीप जा रही थी लेकिन उसको आदमपुर ढाणी के एक ए0 एस0 आई0 ने रोक लिया और उसको लेकर अपने घर चला गया। उसने ड्राईवर से कहा कि मैं यह जीप परसों लाकर तुझे वापस कर दूंगा। जीप वाला मेरे पास आया तब मैंने एस0 पी0 को फोन करके वह जीप छुड़वायी लेकिन उस बेचारे की जीप तीन दिन तक उसके पास ही रही। इस तरह से या तो इन जीपों को और इन जुगाड़ों को रैगुलराईज कीजिए या फिर इनको बन्द करवा दीजिए। ये सब पब्लिक की दिक्कत की चीजें हैं। आप इन बातों को को ट्रांसपोर्ट की डिमांड में ले सकते हैं या होम की डिमांड में ले सकते हैं, किसी भी डिमांड में इन बातों को आप ले सकते हैं। पुलिस वाले इनकी जीपों को या जुगाड़ को पैसे लेकर छोड़ते हैं। अगर मैं एस0 पी0 को टेलीफोन नहीं करती तो शायद वह पुलिस वाला उसको जीप नहीं देता। मैं बेकार के लिए टैलीफोन नहीं करती बल्कि लोगों के कामों के लिये ही टेलीफोन करती हूं। इसलिये ही मेरे टैलीफोन का बिल काफी आ जाता है। आज सरकार के पास पैसे की क्यों कमी रहती है? डिप्टी स्पीकर सर, सेल्ज टैक्स का एक वकील है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती वह अफसरों के पास जाता है और उनसे मिलता है लेकिन अफसर भी क्या करें क्योंकि उनको भी अपने परिवार का पेट पालना होता है। ट्रांसपोर्ट तो कमाई का धंधा है, इसलिये अगर सरकार सेल्ज टैक्स और इन्कम टैक्स को पूरा वसूल करे तो फिर पैसे की कमी नहीं रहेगी।

इसी तरह से जहां तक बिजली की बात है। मेरे हल्के में 1987 से लेकर 1991 तक कोई भी बिजली का नया कनैक्शन नहीं मिला। यह बात ठीक है कि सरकार ने कुछ कनैक्शन्ज दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी कमी बनी रहती है। बिजली की कमी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप नये थर्मल पावर प्लान्टस नहीं लगाएंगे क्योंकि बिजली की खपत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आबादी भी बढ़ रही है और लोगों की जरुरतें भी बढ़ रही हैं। आज बिजली से ही दूध बिलोया जाता है। आज आपका बिजली मोल लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि थर्मल पावर प्लांट लगाने की बेहद जरुरत है। मैं जब गांवों में जाती हूं तो देखती हूं कि गांवों में लोगों को बिजली ही नहीं मिलती। अगर हमें स्वयं को बिजली न मिले तो हमारी क्या हालत हो जाती है? जब गांवों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के लिये भी बिजली नहीं मिलती। एक तरफ तो उनको मास्टर नहीं पढ़ाते

[श्रीमती चन्द्रावती]

हैं और दूसरी तरफ उनको बिजली भी पढ़ने के लिये नहीं मिलती । उनको तो बिजली मिलनी ही चाहिए ।

इसी तरह से नकल रोकने का काफी इंतजाम हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी नकल चली है । मेरे गांव में भी नकल चली । लोगों ने मुझसे कहा कि लड़कियां पढ़ती हैं इसलिये थोड़ी बहुत तो नकल होनी चाहिये लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं तो नकल के खिलाफ हूं । नकल नहीं होनी चाहिये । मैं श्री देवेन्द्र सिंह और गक्खड़ जी को नकल रोकने के लिये बधाई देना चाहूंगी । उन्होंने जो नकल रोकने के लिये काम किए हैं उसके कारण इसमें काफी सुधार हुआ है । मैंने अपना एक सवाल दिया था वह अभी तक तो आया नहीं है हो सकता है कि कल आ जाए । डिप्टी स्पीकर सर, आज लोग बिहार से और हरिद्वार से नकली सर्टिफिकेट ले आते हैं जिसके कारण हमारे अपने मेहनत करके पढ़ने वाले बच्चे तो रह जाते हैं और वे ऐडमिशन ले लेते हैं । जे0बी0टी0 में दाखिला करने का दफ्तर वगैरह तो गुड़गांव में है लेकिन वे कभी तो मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं । मुलाना जी ने काफी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद भी काफी गलत गलत काम हो जाते हैं । उसके लिए चाहिए कि या तो वह ऑफिस चन्डीगढ़ में हो या किसी बीच की जगह हो । गुड़गांव में सारा सारा दिन टैलीफोन नहीं मिलता है अगर टैलीफोन मिल जाता है तो कोई उठाता नहीं है छुटो-मोटो तो जो काम होते हैं वह आपको भी पता है हमको भी पता है कि किस तरह से होते हैं यह सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं । बिजली की चोरी बहुत ज्यादा होती है । एक उद्योगपति दस हजार रुपए की बिजली की चोरी करता है तो किसान दस रुपये की कर लेता है । उसके बारे में कोई इलाज तो हो । ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूं । मेरे हल्के में इंटीरियर के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बसें कम जाती हैं। दादरी डिपो का कुछ हिस्सा भिवानी में चला जाता है, कुछ दादरी में चला जाता है । कोई जिम्मेदारी नहीं लेता । चहड़ हमारा बहुत बड़ा गांव है, 10 जमा 2 का स्कूल है, बसें कम जाती हैं । वहां बस तो जानी चाहिए । वैसे भी मेरा हल्का कुछ महेन्द्रगढ़ में है, कुछ हिसार में है, कुछ भिवानी में है, इसलिये भी मुझे लोगों को काम कहने में मुश्किल आती है मैं मुख्य मन्त्री जी से चाहती हूं कि यह एक जिले में नहीं तो दो जिलों में तो हो ही जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को काम देने के लिये कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए । अव्वल तो इंडस्ट्रीज कम हैं जो हैं, वह घाटे में चल रही हैं। जो आफीसर काम नहीं करना चाहते, जिनकी इमेज अच्छी नहीं है, वे अगर किसी जरूरी महकमे पर लगे हुए हैं तो उनको वहां से हटाना चाहिए । लोग कहते हैं कि हम पोलिटिशियन करप्ट हैं मैं तो यह कहती हूं कि अगर

हम कष्ट हैं तो ब्यूरोक्रेटस भी हमारे बराबर कष्ट हैं । इससे कम नहीं हैं सभी देश का बेड़ा बैठा हुआ है । मैं डिमांड के हक में ही कहना चाहती हूं, डिमांड पास होनी चाहिए । आपका शुक्रिया ।

**श्री अमर सिंह ढांडे** (गुहला, एस0 सी0) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड पर बोलने का टाईम दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर – 8 पर कहना चाहूंगा । सड़कों के बारे में जो भी मैम्बर बोलता है वह यही बात कहता है कि हरियाणा में सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सर्वे रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि मन्त्री जी ने सड़कें बढ़ाने की बजाए कम कर दी हैं। यह पैसा कहां खर्च होता है । सड़कों की रिपेयर के बारे में मैंने आज सवाल उठाया था और कहा था कि मेरे हल्के में सड़कों की रिपेयर के लिये जो पैसा मंजूर हुआ है वह सड़कों पर खर्च न होकर पता नहीं कहां खर्च हो गया । सड़कों का इतना बुरा हाल है कि व्हीकल लेकर चलना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है । मेरे हल्के में जहां तक पुलों की बात है । घग्घर नदी पर एक पुल बनाने की बात थी । ढंढोंता गांव है वहां घग्घर नदी पर पुल बनने की बात मैंने, जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था, तब भी कही थी । मेरे हल्के के 15–20 गांव उस पुल की वजह से कटे रहते हैं । बरसात के दिनों में 15—20 गांव ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं आ जा सकते । उन गांवों का कोई आदमी चीका मंडी में नहीं जा सकता । इस बारे में मुख्यमन्त्री जी ने शुरू में आश्वासन दिया था कि हमने पुल मंजूर कर दिया है और जल्दी ही पैसा मिलने पर काम चालू कर देंगे परन्तु अफसोस की बात है कि चार साल हो गये हैं, अब तक कोई काम नहीं हुआ । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस पुल का काम एक सार्वजनिक हित का काम है, भलाई का काम है । इस पुल को जल्दी बना दिया जाए क्योंकि इस पुल के बनने से लगभग 15—20 गांवों को फायदा होगा ।

दूसरी बात मैं शिक्षा से संबंधित कहना चाहता हूं । हमने तो यह सोचा था कि हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय, बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा ही काम करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि मेरे हल्के में जितने भी प्राईमरी, मिडल, हाई व जमा दो प्रणाली के जितने भी स्कूल्ज हैं उनमें अध्यापकों की संख्या पूरी नहीं है । कोई भी प्राईमरी स्कूल ऐसा नहीं है जहां अध्यापक पूरे हों । बच्चों को चार पांच किलोमीटर पैदल चलकर स्कूलों में जाना पड़ता है । मेरे अपने हल्के के गांव मछरेड़ी में एक स्कूल है, जहां पर कोई मास्टर नहीं है । मेरे हल्के में कई बड़े-बड़े गांव हैं जिनमें प्राईमरी स्कूल्ज हैं, उनमें एक ही मास्टर है । मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि अगर वे शिक्षा को सुधारना चाहते हैं तो

[श्री अमर सिंह ढांडे]

सब से पहले जो शिक्षा की बुनियाद प्राईमरी स्कूल्ज हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। वहां पर टीचर्ज की स्ट्रैन्थ को पूरा करना होगा ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। हमारे प्रिय नेता ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रिय सरकार जब इस प्रदेश में थी, उस वक्त बहुत से स्कूल्ज अप-ग्रेड किये गये थे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अब इस सरकार के बनने के बाद, भागल व चीका के स्कूल + 2 के लिये अप-ग्रेड हुए थे, बैसारे के सारे डि-ग्रेड कर दिये गये। मैं यह चाहूंगा कि चाहे हम अपोजिशन के मैम्बर हैं, सरकार को किसी भी हल्के के साथ इस तरह की भेदभाव की नीति नहीं बरतनी चाहिये जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो, बच्चे अच्छी शिक्षा न ले सकें। जिस तरह से दूसरे मैम्बर्ज के हल्के में स्कूल्ज अप-ग्रेड किये जाते हैं उसी तरह से अपोजीशन के मैम्बर्ज के हल्कों में भी स्कूल्ज अप ग्रेड होने चाहियें। किसी के साथ भेदभाव की नीति नहीं बरती जानी चाहिए

अब मैं मैडीकल की बात भी कहना चाहूंगा कि आज सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। कोई डाक्टर मौके पर नहीं मिलता। समय पर मरीजों को दवाईयां नहीं मिलती। मैं हैल्थ मिनिस्टर जी को कहूंगा कि गुहला हल्का में जो अस्पताल है, वहां पर दो डाक्टर्ज हैं, एक मिस्टर डोगरा और दूसरी मिसेज डोगरा। वहां पर इनको पता नहीं किसलिये बैठा रखा है ? वहां के लोगों की यह शिकायत है कि ये दोनों डाक्टर्ज अस्पताल में मिलते नहीं हैं और न ही कोई काम करते हैं जिससे लोगों को बड़ी भारी असुविधा है। इसलिये लोग बार बार मांग करते रहते हैं कि उन को वहां से बदला जाए लेकिन पता नहीं वे लोग कोई न कोई पोलिटीकल ऐप्रोच करके फिर यहीं पर आ जाते हैं। हर साल उनकी बदली रोकी जाती है। उन डाक्टर्ज ने उस एरिया का बुरा हाल कर रखा है। वे सरेआम लोगों से पैसे लेते हैं।

अब मैं कर्मचारियों से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। कर्मचारियों की रिजर्वेशन से मुताल्लिक कहना चाहूंगा। इस बारे में मेरा ख्याल भी था कि हरिजनों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। जितने भी सरकारी विभाग हैं उन में कहीं पर भी बी० सी० व हरिजन कर्मचारियों को रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही सरकार कोई कदम उठा रही है। आज हरियाणा के अन्दर नौकरियों का बुरा हाल है आज हरियाणा के सरकारी विभागों में रिजर्वेशन से संबंधित मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हरियाणा में क्लास वन की 2106 पोस्टें हैं, जिनमें से केवल 122 हरिजन ही लगे हुए हैं और इस हिसाब से यह 5.30 परसैन्ट का ही कोटा बनता

है क्लास टू में 8688 टोटल पोस्टें हैं जिनमें से 492 हरिजन आफिसर काम कर रहे हैं इसकी परसैन्टेज केवल 5.64 ही बनती है जबकि भारत सरकार में संविधान के अनुसार हमारा सरकारी नौकरियों में कोटा 20 परसैन्ट होना चाहिये । इस तरह से यह सरकार हरिजनों के साथ मजाक कर रही है और रिजर्वेशन के कोटे को नौकरियों में लागू नहीं कर रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, क्लास थ्री की पोस्टें हरियाणा के अन्दर कुल 1,83,577 हैं । इनमें हरिजन 18855 हैं । यह कोटा सिर्फ 10.3 परसैन्ट बनता है । क्लास फोर में तो आपको पता है कि हमारे स्वीपर भाई ज्यादा होते हैं इसलिये वह कोटा तो पूरा है लेकिन बाकी तीनों क्लासों में हमारा कोटा कम है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस सरकार बड़े बलन्द दावे करती है कि हम हरिजनों की भलाई के काम करते हैं और उनको अच्छी नौकरियां दे रहे हैं । तो जो बातें मैंने आपके सामने कहीं आप उनसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार हरिजनों का कितना भला करना चाहती है । पिछले सैशन में भी बात आई थी कि जो सरकार में जाट अफसर हैं, इस सरकार ने उनकी फाईलों पर "जे" शब्द लिख दिया । यह ठीक है कि जाट कांग्रेस को वोट नहीं देते लेकिन कांग्रेस आज हरिजन और बैकवर्ड भाइयों की वोट से ही सत्ता में बैठी है।

**सिंचाई मंत्री** (चौधरी जगदीश नेहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह बात दुरुस्त नहीं है । इनको यह कहना शोभा नहीं देता कि जाट कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जाट जीत कर भी बहुत आए हैं और उन्होंने कांग्रेस को वोट भी दिया है । इसलिये इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ।

**श्री अमर सिंह ढांडे** : डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली विधान सभा में कांग्रेस के एक एम0 एल0 ए0 ने बात उठाई थी कि इन्होंने खुद इसकी फाईल पर "जे" शब्द लिख दिया । यह सरकार कहती है कि हम हरिजनों का भला करना चाहते हैं। ये लोग जो ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हैं, ये हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की दया से बैठे हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारा 20 परसैन्ट का कोटा बनता है वह पूरा किया जाए । वह चाहे हरिजन का हो या बैकवर्ड का हो। सरकार इसको टाईम बाऊंड करे कि कब तक बैक लौग को पूरा कर देंगे और कब तक हमारी रिजर्वेशन को पूरा करेंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह से चौधरी देवी लाल ने हरिजनों की भलाई का काम किया था कि उन्होंने क्लास वन और टू में परमोशन में भी रिजर्वेशन दी थी उसी तरह से मैं इस सरकार से चाहता हूं कि यह भी उसको लागू करे । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हरिजनों का भला करना

[श्री अमर सिंह ढांडे]

चाहती है तो जो हमारे भाई सरकारी नौकरियों में बैठे हैं उनका रोस्टर सिस्टम ठीक किया जाए ताकि उनको समय पर परमोशन मिल सके। भारत सरकार ने संविधान के तहत जो सुविधा हरिजनों को दी हुई है उसको पूरा किया जाए। यह सरकार कोई ऐसा बिल पास करे कि जो सरकारी अधिकारी रिजर्वेशन पूरी नहीं करता उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही कर सके जिससे उसको दंड दिया जा सके। जो अधिकारी अपने विभाग में 20 परसेंट या और जितनी भी रिजर्वेशन बनती है उसको पूरी नहीं करता उसके बारे में सरकार विधान सभा में बिल ले कर आए कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

लोक सम्पर्क राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे साथी रिजर्वेशन के बारे में बोल रहे थे। जब इनकी सरकार थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्य मन्त्री थे उस समय चौधरी टेक चन्द मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन थे वहां पर 100 से ज्यादा क्लर्कों की भर्ती हुई थी उसमें रिजर्व कोटे की सीटें थी लेकिन इन लोगों ने रिजर्व कोटे के अगेन्स्ट जनरल कैटेगरी के कंडीडेट्स रख लिए। फिर आज ये रिजर्वेशन की क्या बात करते हैं? उस के अन्दर ढांडे साहब के हल्के के सीवन गांव का एक जनरल कैटेगरी का लड़का था वह लड़का मेरे एक दोस्त का दोस्त है उसको इन्होंने हरिजन कोटे में सिलैक्ट कर दिया। जब उसको ज्वायन करवाने गए तो उस समय कहा गया कि आप सर्टिफिकेट लाओ कि आप हरिजन हैं। किस मुंह से रिजर्वेशन की बात करते हैं? कमाल की बात है। इन्होंने हरिजनों के साथ जो सलूक किया है, वह मैं बताता हूं। मेरे हल्के के गांव गूणा के हरिजनों को उजाड़ कर इन्होंने बरवाला में बसा दिया। श्री किरपा राम पूनिया उस वक्त कैबिनेट में मन्त्री थे, उनको उस समय उचाना गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया।

श्री सतबीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मदन साहब अब तो मन्त्री हैं। ये चौधरी देवी लाल जी की सरकार में लोक दल पार्टी के एम0एल0ए0 थे, मिनिस्टर थे लेकिन आखिरी दिन ये चोर दरवाजे से भाग गए। कोई बात नहीं यह इनकी मर्जी है, ये भगौड़ा हो सकते हैं। लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने हरिजनों के लिए सीट रिजर्व की, उनकी परमोशन के लिये रोस्टर बनाया। उस समय हरिजनों के साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं की गई, चाहे कोई भर्ती की गई और चाहे कोई परमोशन की गई। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं चोर दरवाजे से नहीं भागा। मैंने उस समय एम0एल0ए0 और मन्त्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। यह रिकार्ड की बात है। मैं चोर दरवाजे से नहीं भागा। इनके

नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे हराने के लिये कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मैं इनकी छाती पर मूंग दल कर जीत कर आया हूं।

**श्री सतबीर सिंह कादियान :** यह मदान अब भी भागेगा। कांग्रेस का सत्यानाश हो लिया। अब भी भागना पड़ेगा।

**श्री सुरेन्द्र कुमार मदान :** मैं इस पार्टी को छोड़ कर कभी नहीं भागूंगा। आपको चुनाव जीत कर दिखाऊंगा।

**श्री अमर सिंह ढांढे :** डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजनों को नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी, उस समय मुख्य मंत्री सदन में नहीं थे, अब आ गए हैं, इसलिये मैं वह बात दोबारा कह देता हूं। अगर आप हरिजन भाइयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों की भलाई करना चाहते हैं तो विधान सभा में एक ऐसा बिल पास करें कि जो सरकारी अधिकारी रिजर्व कोटे को पूरा नहीं करता, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा बिल विधान सभा में पास करें ताकि हरिजन भाईयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों की भलाई हो सके। हर रोज अखबारों में यह खबर छपती है कि हरिजनों के साथ बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों के साथ गांवों के अन्दर और शहरों के अन्दर बहुत बदसलूकी की जाती है। क्योड़क गांव यहां पर कई बार चर्चा का विषय बना है। मैं मुख्य मन्त्री जी को एक बात कहना चाहता हूं, पता नहीं सरकारी अधिकारी इनको पूरी रिपोर्ट देते हैं या नहीं या उसमें कोई लाकूना रह जाता है। शर्मा जी ने जो बात कही वह सत्य थी। उपाध्यक्ष महोदय, क्योड़क गांव के 100 हरिजन परिवार गांव छोड़ कर चले गए थे। वहां पर बाद में हरिजनों ने पंचायत की जिसमें 1000 के करीब हरिजन इकट्ठे हुए थे, बाद में फैसला होने पर उनको वापस गांव में छोड़ कर आए थे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब भी 25 परिवार गांव छोड़ कर जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जिन अफसरों ने उन हरिजनों का मुंह काला करके और गले में जूतों की माला डालकर घुमाया था, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये। जितनी बेइज्जती उनकी हुई है, कोई भी उस गांव में अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता। बगैर किसी कसूर के, उनका काला मुंह किया गया और गले में जूतों की माला डाली गई। मदान जी भी जो मंत्री हैं, उस फैसले में शामिल थे, इन्होंने भी माना था कि उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी पता नहीं अभी तक इस्तिफा क्यों नहीं दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, जो परिवार अब भी गांव से बाहर हैं, मैं उनके नाम पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

**श्री सुरेन्द्र कुमार मदान :** उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है कि मैंने इस्तिफा क्यों नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर दो हरिजन गुटों का आपस में झगड़ा था। दोनों ही हरिजन गुटों को समझाया गया था। डी0आई0जी0 कमीशनर, एस0पी0, डी0 सी0 ने भी उनको समझाया। मैं दो दिन तक डी0सी0 साहब की कोठी के बाहर धरने पर बैठे रहे। वे एक पूर्ण नामक नम्बरदार के यहां

[श्री सुरेन्द्र कुमार मदान]

पर रुके थे, जिनकी अर्बन स्टेट में कोठी है। हरिजनों का आपस में झगड़ा हो गया और उनका आपस में फैसला करा दिया गया हो जिसमें ये भी मौजूद थे, तो फिर इस्तिफा देने वाली बात कहां से आ गई ? आज कोई परिवार ऐसा नहीं है जो उस गांव से बाहर है, बेशक आप इसका पता करवा लें। सभी लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। जातिवाद का नारा फैलाकर, झगड़ा करवा कर राजनैतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए।

**श्री अमर सिंह ढांडे :** मंत्री जी कह रहे हैं कि वे दो दिन धरने पर रहे। मैं बताना चाहता हूं कि वे 5-1-95 से 5-2-95 तक धरने पर बैठे रहे। पता नहीं इनको गलत बात कहने की क्यों आदत है ? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बसाने का काम करना चाहिये। अखबारों की कटिंग भी मेरे पास है। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष :** आप जल्दी खत्म करें।

**श्री अमर सिंह ढांडे :** उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। बसों की हालत बहुत खराब है। मेरे गुहला हल्के में 19-3-95 को एक बस दुर्घटना हुई जिसमें 8 लोग मारे गए। मरने वाले में गुहला हल्के के दो आदमी, एक औरत, एक ड्राईवर और दूसरे पांच व्यक्ति मारे गए थे। मैं चाहता हूं कि उनको सरकार उचित मुआवजा दे।

उपाध्यक्ष महोदय, गुहला क्षेत्र पूरी तरह से उपजाऊ क्षेत्र है। आज बिजली किसानों के लिये जरूरतमंद चीज हो चुकी है। मेरे हल्के में जितने भी पावर हाउस हैं सब अन्डर लोड हैं। सरकार जो 4-5 घंटे बिजली देती है, वह भी इन पावर हाउस के अन्डर लोड होने के कारण पूरा लोड नहीं उठा पाते। मैं चाहूंगा कि उनको अपग्रेड करें।

12.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हमारे हल्के में नये पावर हाउस बनाने की बात है बलबेड़ा एक बहुत बड़ा गांव है, उसके 33 के0वी0 के ऐस्टिमेट्स पहुंच चुके हैं। मैंने इस बारे में कवारतन गांव का एक क्वैश्चन भी किया था और मंत्री जी ने जवाब भी दिया था कि वहां पर 33 के0वी0 का पावर हाउस बनाएंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि गांव कवारतन व बलबेड़ा पर जल्दी ही काम शुरू करवाएं ताकि लोगों को उससे फायदा मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने डिमाण्ड के अन्दर जो पैसा रखा है, हम सरकार से चाहते हैं कि जो पैसा जिस मद के लिये रखा गया है, वह पैसा उसी मद पर खर्च किया जाना चाहिये चाहे वह पैसा हरिजनों के कल्याण के लिये हो, चाहे कोई सड़कों या पुलों आदि के बनाने के लिये हो, वह उसी काम पर खर्च होना चाहिये जिसके लिए पैसा लिया गया है। इसके साथ ही मैं गुहला हल्के की एक और जरूरी बात कहना चाहता हूं। गुहला हल्के में एक बांध बना हुआ है जो कि काफी दिन पहले बना था। पंजाब से फ्लड का पानी आता था और उस पानी से गुहला और चीका को बचाने के लिये यह बांध बनाया गया था। वह बांध

बहुत पुराना हो गया है। 20-25 गांव हरियाणा के इसके पीछे पड़ते हैं जो कि बरसात के दिनों में फ्लड के पानी से पूरी तरह से डूब जाते हैं और उनकी फसलें भी पानी में डूब जाती हैं। पानी का प्रैशर बढ़ जाने पर बांध टूट जाता है जो गांव बांध से आगे हैं उनमें बहुत तबाही होती है और नुकसान होता है। पिछले फ्लड में गुहला हल्के के 40-45 गांव बिल्कुल तबाह हो गए थे। गांवों में 8-10 फुट तक पानी खड़ा हो गया था। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस बांध का कोई समुचित प्रबन्ध करें और स्पैशल इन्जीनियर्ज की कोई टीम भेज कर वहां का सर्वे करवाएं कि उस बांध से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो बाढ़ हर साल तबाही मचाती है उससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा तथा फसलों और जानमाल की जो हानि होती है वह भी रुकेगी। उस बांध के बारे में सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से जिस तरह से यह सरकार काम कर रही है, अगर इसी तरह से आगे भी काम करती रही तो ये पलट कर जाने वाले नहीं हैं इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि ये जनता को सुविधा देने तथा राहत पहुंचाने के कामों की तरफ पूरा ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**चौधरी बंसी लाल (तौशाम)** : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मुख्य मंत्री जी ने बोलते हुए इन्टरवीन किया था। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष** : चौधरी साहब, आप डिमांड नम्बर बता कर बोलें।

**चौधरी बंसी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूं। क्या यह केवल मेरे लिये ही जरूरी है अभी तक तो आपने अपनी जो रूलिंग दी थी कि कोई किसी प्रकार बोले। जब असलम खां जी बोल रहे थे तब आपकी यह रूलिंग थी लेकिन अब आपकी दूसरी रूलिंग आ गई है। मैं इस पर भी स्टिक करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : जैसे आपकी मर्जी है वैसे बोलें। मैंने जो कहा है वह जनरल प्रैक्टिस है।

**चौधरी बंसी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल प्रैक्टिस मुझ पर ही क्यों लागू की जा रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि इस सरकार के आने के बाद कुल सरकारी नौकरियों की संख्या क्या थी और उनमें हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासिज का कितना कोटा बनता था। जो कोटा हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज का बनता था, क्या उस को पूरा किया गया या नहीं, अगर पूरा नहीं किया गया तो उसका क्या कारण है ? उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों और बैकवर्ड के नाम को मुख्य मन्त्री जी एक्सप्लायट करते हैं लेकिन उनके कोटे की जो नौकरियां हैं, वे दूसरी जगहों पर चली जाती हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज का नौकरियों में जो कोटा है, वह कितने परसैंट पूरा हुआ है, अगर पूरा

[चौधरी बंसी लाल]

नहीं हुआ है तो क्यों नहीं किया गया ? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी से एक और सवाल पूछा था कि वर्ल्ड बैंक से सरकार कितना लोन ले रही है, किस-किस डिपार्टमैंट के लिये कितना-कितना लोन लिया गया है ? मेरे कहने का मतलब है कि इरीगेशन के लिये, एजुकेशन के लिये, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये या हरियाणा सरकार की किसी भी कारपोरेशन के लिए कितना-कितना लोन लिया गया है ? उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के कान्स्टीच्यूशन के आर्टिकल 293 (3) में दिया हुआ है कि जब स्टेट गवर्नमैंट लोन लेगी तो उसकी गारन्टी भारत सरकार देगी। मैं यह इसलिये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि हरियाणा सरकार इतना ज्यादा लोन ले ले कि बाद में हरियाणा उसका ब्याज भी न चुका सके। यह एक बहुत ही अहम सवाल है, मैं इसका जवाब मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी है कि ये जवाब दें या न दें। यह लोन का मसला छोटा मसला नहीं है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अजमत खां जी रूलिंग पार्टी के एम0एल0ए0 हैं और ये माइनज के चेयरमैन भी हैं। उनका ब्यान आया था कि अगर सारी माईनज का ठेका हमें दे दिया जाए तो हम बुढ़ापा पैन्शन तो देंगे ही और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में भी पैसा दे देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब इधर-उधर से दे दिया और कहा कि हाई कोर्ट से स्टे आ चुका है। हाई कोर्ट ने तो प्रोसीजर पर स्टे दिया था तो ये उसको पूरा कर देते। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के स्टे के बाद प्राईवेट लोगों को खाने क्यों दे दी गई ? अगर ये उनको न देते तो इनका सवा करोड़ रुपए या दो करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फ्रीडम फाईटर की रिजर्वेशन हम 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि तामिलनाडू सरकार ने यह रिजर्वेशन 75 प्रतिशत कर दी और केस भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार ने इसको कांस्टीच्यूट कर दिया। उसके बाद कर्नाटक वालों ने भी 82 प्रतिशत कर दिया है और भारत सरकार को यह केस भेजा हुआ है तथा भारत सरकार उसको भी कांस्टीच्यूट करने जा रही है। तो हरियाणा में यह क्यों नहीं हो रहा है, ये दो प्रतिशत ही बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि बंसी लाल लोगों का खून पीता है, मैं तो यह कहता हूं कि चौधरी भजन लाल सारे हरियाणा के लोगों का खून पीता है। दूसरे इन्होंने कर्मचारियों की बात कही मैंने कर्मचारियों के साथ क्या किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, 50 हजार के करीब कर्मचारी मेरे घर के पास मीटिंग करके गए और मैंने एक भी कर्मचारी को सस्पैंड नहीं किया। इन्होंने तो लाठियां चलाई हैं। कर्मचारियों को रेलों और बसों में से पकड़-पकड़ कर उतारा है और अगर कोई कर्मचारी नहीं मिला तो उसके घर से उसके बीवी-बच्चों को ही पकड़ लाए थे। मेरा फतिया तो पिछली बार कर्मचारियों ने पढ़ दिया था, अब की बार इनका फातिया कर्मचारी पढ़ देंगे। जब यह बात हुई थी तो कांग्रेस के एक माननीय सदस्य पण्डित

चिरंजी लाल हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भजन लाल कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर गया है और मरा हुआ सांप बंसी लाल के गले में डाल गया है। कांग्रेस की हार तो भजन लाल के कारण हुई लेकिन वह मरा हुआ सांप बंसी लाल के गले मढ़ दिया। यह सब तो भजन लाल ने किया है, मैं तो ऐसे काम नहीं करता हूं।

एक और जवाब में मुख्यमंत्री ने कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया का हिसार के बारे में हवाला दिया। इन्होंने यह कह दिया कि हम आपके पास कागज भेज देंगे लेकिन वह कागज आज तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया ने जुलाई 1991 में यह प्वायंट आउट किया था और 1993 में भी किया था कि इसमें 1 करोड़ 43 लाख 46 हजार का घाटा हिसार डिस्टिलरी की वजह से हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये कहते हैं कि उसकी बात बिल्कुल सही है तो ये उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया कोई पौलीटीकल आदमी नहीं है जिसका ये कह देंगे कि यह पार्शियल रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें बेबुनियाद हैं और हकीकत में तो यह टैक्स की चोरी है। इसी तरह से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन तो है ही कहां? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जिला कांग्रेस का प्रधान है, पुलिस कप्तान जनरल सैक्रेटरी है, तहसीलदार खजांची है और बाकी जितने मुलाजिम हैं .....(विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप इनसे कहें कि ये मुझे बीच में न टोकें, वरना फिर आपको मेरा टाईम बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ और भी जो अफसर हैं, वे इनके कार्यकर्त्ता हैं। सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। सरकार अगर कहीं पर हो तो मैं आपको बताऊं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो लोग कहते हैं मैं तो कभी-कभी ही कहता हूं। पंडित चिरंजी लाल ने जो कहा है मैं उसको कोट करता हूं। उन्होंने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी है। मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी उन्होंने यह भी लिखा है कि तीन जनवरी को मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने उनके लड़के कुलदीप को एक सरकारी मुलाजिम के दफ्तर में बुलाकर उसको धमकी दी और उससे कहा कि अपने पिता को समझा कि प्रधानमंत्री के आवास पर उन्होंने जो मेरे सम्बन्ध में कहा है, वह ठीक नहीं है। मेरा नाम भजन लाल है। मैं रगड़कर रख दूंगा तेरे बाप जैसे सौ सांसद मेरी जेब में हैं। इस बात की न तो पंडित चिरंजी लाल ने कंट्राडिक्शन की है और न ही मुख्यमंत्री जी ने कंट्राडिक्शन की है। मेरे पास यह नौ मार्च का अखबार है। आज का नहीं है, आज तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं आयी। उपाध्यक्ष महोदय, पंडित चिरंजी लाल ने यह भी कहा कि हम तो कहते ही रहे हैं कि महाजन सेतृत्व के सफाये के लिये हविपा विधायक ओ0पी0 जिन्दल पर इन्होंने जो अत्याचार किए वह सबके सामने हैं। उनको टाडा के तहत जेल तक पहुंचाने की साजिश मुख्यमंत्री ने की थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इनके सांसद कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैंने एक बात बीजों के बारे में कही थी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बीज के केस का जवाब गोलमोल कर दिया। करनाल में जिस कम्पनी

[चौधरी बंसी लाल]

ने नकली बीज बेचा था उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उस कम्पनी के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और दो आदमियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उन दो आदमियों को गिरफ्तार करने का क्या नतीजा निकला, क्या इन्क्वायरी हुई ? मुख्यमंत्री जी ने बीज की अरली वैरायटी और लेट वैरायटी बतायी थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कैथल गया था तो मैंने वहां पर इस बारे में किसानों से बात की थी तो उन्होंने बताया कि यह जो पी०आर० 103 वैरायटी है इसमें अरली और लेट वैरायटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बल्कि इसमें तो एक ही वैरायटी होती है। जिस ने यह बीज बेचा है, उसके पास तो सीड बेचने का लाईसेंस ही नहीं है। उसके पास तो फर्टिलाइजर बेचने का लाईसेंस है। जिसने इसका बिल काटकर दिया है, मैं नहीं समझता कि उस आदमी को बीज बेचने का अधिकार था। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि केवल 19 एकड़ में ही बीज खराब था लेकिन वहां तो 600 क्विंटल से भी ज्यादा बीज बिका है। क्या 600 क्विंटल बीज 19 एकड़ में ही बोया जाएगा ? उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों में घपला बहुत बड़ा है लेकिन सरकार इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है। कानून कायदे के तहत तो कोई आदमी खुला बीज नहीं बेच सकता, लेकिन इसमें खुला बीज बेचा गया है और 12 रुपये या 20 रुपये देकर उनसे कट्टा वापस ले लिया गया। 31 किलोग्राम बीज बेचा गया जबकि 31 किलोग्राम का फर्टिलाइजर का कोई कट्टा नहीं होता है, कोई पैकेज नहीं होता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर इनकी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि इस सरकार के आगे पीछे कोई नहीं है। इसी तरह से मुख्य-मंत्री जी ने कह दिया कि पंजाब में गन्ने को ले जाने में कोई रुकावट नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही जब कैथल में लोगों से यह कहा कि मैंने विधान सभा में मुख्य मंत्री जी से इस बारे में कहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई पाबन्दी नहीं है। वहां पर सैकड़ों किसानों ने हाथ खड़े करके आवाज लगायी कि गन्ना प्रदेश से बाहर जाने के लिये रोक रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अब किसान खुद ही समझ लेंगे कि क्या हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री जी इस बारे में खुद जवाब दे देंगे।

इसके अलावा, आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने मौलेसिस का रेट प्रति क्विंटल 180 के बजाए 200 रुपये कर दिया और 50 परसैन्ट कोटा रिजर्व कर दिया। क्यों 200 रुपये का झगड़ा रख दिया, 100 का 100 परसैंट खुला रख दो। उससे किसान के गन्ने की कीमत बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो यमुना नदी के जल वितरण का मामला है उसका अभी तक मुख्यमंत्री जी तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाए कि राजस्थान के साथ जो बांध बने हैं, उन बांधों का पानी लिए बगैर, उसके बदले में पानी लिए बगैर आपने दस्तखत क्यों कर दिए ? मुख्यमंत्री जी अभी तक इसको अच्छी तरह से क्लेरीफाई नहीं कर पाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान को हम जो बिजली देते हैं उस पर एक

डेढ़ रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमको हाइडल पावर प्रोजेक्ट से कितनी बिजली मिलती है मेरे हिसाब से करीब 1/3 मिलती है। क्या वह भी डेढ़ या अढ़ाई रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलती है ? किसान के ऊपर रेट ऐसा लगा दिया कि किसान चाहे दो एकड़ धरती का मालिक हो, उसे कम से कम इतना तो देना पड़ेगा, 300 या 350 रुपये कुछ रखे हैं। मैं यह नहीं समझता कि किसान को बिजली देने से हरियाणा सरकार को नुकसान होता है। सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है। किसान जो देश के लिये कमाई करता है जिससे सेल टैक्स मिलता है, उससे आगे काम बढ़ता है, उससे आमदनी होती है, वह सरकार को याद ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की मोटरें जल जाती हैं। कल भी मुझे कैथल में लोगों ने कहा कि कई-कई दिन बिजली नहीं आती। दो दिन से पहले कभी आती ही नहीं, एक दिन आती है तो दूसरे दिन नहीं आती। कई जगह हफ्ते-हफ्ते बिजली चली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगा होम तो एक ही होम है, मुख्यमंत्री जी का होम है, बाकी तो हरियाणा में कहीं होम रहा ही नहीं। जितनी आज ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन हरियाणा में खराब है, मेरे ख्याल में उतनी किसी अड़ोस-पड़ोस के प्रदेश में नहीं है। कत्ल होते हैं, रेप होते हैं और पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाते हैं। फिर जो केस ठीक हों, सही केस हों वे दर्ज नहीं होते। उपाध्यक्ष महोदय, हों भी कैसे, जब पुलिस वालों को रिश्वत लेकर भर्ती किया जाता है तो क्या होगा, वे तो कमाई पूरी करेंगे। इसलिये होम डिपार्टमैंट का जहां तक सवाल है, होम डिपार्टमैंट की बहुत खसता हालत है, चाहे जिसको अपर क्लास के लिये भेज दिया, चाहे जिसकी तरक्की कर दी, चाहे जिसको साल में छह जगह तबदील कर दिया, चाहे जिसकी ए०सी०आर० खराब करवा दी, चाहे जिसको सजा करवा दी। छोटे कर्मचारियों को जब तक एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वे अपने हकों के लिये लड़ नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू की बात आ गई। प्रदेश के टूर करते वक्त मुझे बहुत सी जगह लोग मिलते हैं, वे कहते हैं कि हमारे इंतकाल दर्ज नहीं होते। रजिस्ट्रियों पर इतने परसैंट मांगते हैं, वह परसैंटेज न दें तो रजिस्ट्री नहीं होती। अगर ऊपर किसी के पास शिकायत करें तो कोई सुनवाई नहीं करता। क्या कहें इसका ?

उपाध्यक्ष महोदय, एजूकेशन में इन्हीं के मैम्बर का एक प्रस्ताव भी आज के लिए रखा हुआ था। दो साल से ज्यादा हो गए, कौपिंग के बारे में चल रहा था कि कौपिंग न हो। कौपिंग रोकने के लिए सुशीला कुमारी की हत्या की गई और जिस द्वारा हत्या की गई, वह कमरी कमी मुख्यमन्त्री जी की सिक्योरिटी में था। (विघ्न) जनाब देते समय बता देना। एजूकेशन की हालत तो यह है कि कहीं मास्टर नहीं हैं। एजूकेशन बोर्ड ने ऐसा कर दिया कि 5-5, 7-7 साल पहले लोग फेल हो गए थे, वे भी पास कर दिए। इसी एजूकेशन के सिलसिले में स्कैण्डल

[चौधरी बंसी लाल]

आउट करने के लिए यूनिवर्सिटी के श्री रणबीर सुहाग का भी कत्ल हो गया, उसने पुलिस कप्तान को लिखकर दिया कि मुझे सिक्योरिटी दो, उसको सिक्योरिटी नहीं मिली । (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : कितनी बार दोहराओगे ?

चौधरी बंसी लाल : जितनी बार आप सही जवाब नहीं देंगे, मैं दोहराऊंगा, मेरा काम यही है । उपाध्यक्ष महोदय, आज महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के बहुत से सीनियर प्रोफेसर हथियारों का लाइसैंस मांग रहे हैं । कई प्रोफेसर्ज जो 60, 70 हजार रुपये के सैलरिड परसन हैं इसलिए वे रिवाल्वर या बंदूक खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन इसके बावजूद भी वे लाइसैंस मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है । यह इनकी ऐजूकेशन की हालत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 10 पर बोलना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैडीकल कालेज में कोई स्थान पूरे नहीं हैं । केवल गिनती के ही स्थान पूरे होंगे । मेरे विचार से गवर्नमैंट आफ हरियाणा को मैडीकल काऊंसिल आफ इंडिया ने यह लिखा है कि अगर आप, जो कंडीशंज हैं, उनको पूरा नहीं कर सकोगे तो इस मैडीकल कालेज को डी-रिकगनाइज कर दिया जाएगा । उसी दिन से मैंने यह कहा था लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था । मैं तो यह कहता हूं कि इसके लिये कानून रिलैक्स कीजिए, जो मर्जी चाहे कर लीजिएगा, लेकिन रोहतक मैडीकल कालिज की हालत सुधारें, क्योंकि यह मामला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है । हरियाणा प्रदेश के सैन्टर में वह एक मैडीकल कालेज है, दूसरा भी चाहे बना लो, अच्छी बात है । लेकिन इस के साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि मैडीकल कालेज के प्रोफेसर, चाहे वे कितनी भी तनख्वाह क्यों न मांगे, वहां अच्छे से अच्छे प्रोफेसर भर्ती करिएगा, चाहे बाहर से ही एन्गेज क्यों न करने पड़े लेकिन मैडीकल कालेज रोहतक की हालत सुधरे । एक वह भी जमाना था कि जब एक स्टूडैन्ट रोहतक मैडीकल कालेज से एम0बी0बी0एस0 या एम0डी0 करके निकलता था, अगर वह किसी भी पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने चला गया तो जाते ही वह सिलेक्ट हो जाता था लेकिन आज हालत यह है कि वे रोहतक मैडीकल कालेज का नाम सुनते ही स्टूडैन्ट रिजैक्ट हो जाता है । मुख्यमन्त्री जी आप इसको सुधारो, इसकी वर्किंग को आप सुधारें । वहां के इक्विपमैंट का सुधार करिए । कई सालों से इक्विपमैंट खराब पड़े हैं । आपके पास, कोई अच्छे-अच्छे प्रोफेसर्ज नहीं हैं आपके पास, कोई अच्छे-अच्छे डाक्टर्ज नहीं हैं । जैसे पीछे डाक्टर भड़िया रिटायर हुए । वे बड़े अच्छे सर्जन थे । बम्बई से, कलकत्ता से खास करके किडनी आपरेशन के लिए लोग उनके पास आते थे, उनको ऐक्सटैन्शन देनी चाहिए थी । इसी तरह से डाक्टर श्रीवास्तव थे, वे भी रिटायर हुए, उनको भी ऐक्सटैन्शन देनी चाहिए थी । अच्छे

अच्छे डाक्टर्ज को रखना चाहिए था । ऐज की रिलैक्सेशन दो, कोई भी किसी तरह की रिलैक्सेशन दो, लेकिन मैडीकल कालेज में डाक्टर्ज अच्छे होने चाहिए । लेकिन आज हस्पतालों की हालत यह है कि अच्छी दवाई नहीं मिलतीं, अच्छे डाक्टर्ज नहीं मिलते । यहां तक कि डंगरों के डाक्टर्ज भी नहीं मिल रहे हैं । इन बातों पर मुख्य मन्त्री ध्यान देवें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इरीगेशन में भी मुख्य मन्त्री महोदय क्लेम करते हैं, सिंचाई व इरीगेशन मन्त्री क्लेम करते हैं कि इतने दिनों तक या इस मौनसून से पहले नहरों की गाद निकलवा देंगे, नहरों की डी-सिल्टिंग करवा देंगे । आज तक डी-सिल्टिंग कहीं हुई, हमने देखी नहीं है । हमने नहरों के किनारों पर खड़े होकर देखा भी है कि जो छोटी-छोटी नहरें हैं, उनके दोनों तरफ छोटे-छोटे पौधे व सरकण्डे खड़े हैं । अगर उसमें कहीं गाय भैंस भी चलती जाए तो वह नजर नहीं आएगी । इतनी बुरी हालत है, वहां की । इसी तरह से इरीगेशन में जो एन0बी0के0 लिंक्स हैं, उसकी 2700 क्यूसिक्स पानी चलने की कैपेसिटी है और उसमें पानी केवल चल रहा है 1700 क्यूसिक्स , बाकी एस0बाई0एल0 में चलाना पड़ता है । उस एन0बी0के0 के लिंक को भी ठीक करवाना चाहिए ताकि उसमें पानी ज्यादा जा सके और पंजाब से भी पूरा पानी आ सके । पंजाब वाले बहुत बार यह कहते हैं कि हरियाणा को पानी हम इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास ज्यादा पानी लेने की कैपेसिटी नहीं है । क्या यह कोई अच्छी बात है ? इरीगेशन के ऊपर हमारी सरकार जितना खर्च करे, हम खुशी से उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे । इरीगेशन से जितना पानी जाएगा उतना ही किसानों के खेतों को ज्यादा पानी मिलेगा और नैशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा । नैशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इससे नेशन का फायदा होगा, नेशन का फायदा होगा तो उससे किसान, मजदूर और प्रदेश का भी फायदा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं । मुख्य मन्त्री महोदय ने उस दिन जवाब नहीं दिया था । मैंने एक बात कही थी कि टूरिज्म वालों के जो टूरिस्ट स्थान हैं, उनका स्टैण्डर्ड बहुत खराब है । बहुत से टूरिस्ट बाहर से आते हैं । पंजाब से जाने वाले, आगरा जाने वाले और जयपुर वगैरह जाने वाले भी हरियाणा से होकर गुजरते हैं । मैंने इस बारे में एक दिन एक बात कही थी कि चाहे आप 10 रुपए कमरे का किराया और बढ़ा दो, मगर उनकी सफाई रखो, कपड़े साफ रखो । मैं क्या बताऊं, वहां पर जो तकिए इन लोगों ने रख रखे हैं, उनको जब आप लगाओगे तो उनमें से छोटे छोटे दाने वहां पर बिखरते जाएंगे । यह हालत इनके तकियों की है । मैं यह कहना चाहता हूं कि बाहर से जब टूरिस्ट आता है और ये उससे 480 रुपए किराए के लेते हैं तो कम से कम वह आराम से तो ठहर सके । उस रोज आपने फरमाया, डिप्टी स्पीकर साहब, कि अम्बाला में पीने का पानी नहर का है । वहां पर एक बार मैं थोड़ा पानी दे गया था । मैंने अम्बाला के लोगों से मुलाकात

[चौधरी बंसी लाल]

की और खास तौर से पत्रकार भाइयों से बात की तो वे कहने लगे कि आप अम्बाला की बात भी कहते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने असैम्बली में कह दिया कि अम्बाला, कैथल, रिवाड़ी, हीसल वगैरह जगहों का पानी खराब है। यानी बड़े-बड़े शहरों का कई जिलों में पानी खराब है और वह पीने के काबिल नहीं है लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगती। जब तक इन सब का प्रबन्ध नहीं हो जाता, उस वक्त तक सार नहीं पड़ेगी। मैं खास तौर से मुख्य मन्त्री जी से दो बातों का जवाब चाहूंगा। एक तो बैकवर्ड और हरिजनों का कोटा कितना पूरा किया और दूसरे वर्ल्ड बैंक से किस-किस महकमे के लिए कितना कितना लोन लिया, उसका सालाना ब्याज क्या होगा, आगे कितना लोन ले रहे हैं जिसके लिए आपने एग्रीमैंट किया होगा और उसका टोटल ब्याज कितना होगा, उसे स्टेट दे सकेगी या नहीं ?

**चौधरी भजन लाल :** उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। बंसी लाल जी कल सदन में नहीं थे, कहीं सैर करने गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहा और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि अगर माननीय सदस्य कोई बात हाउस में उठाए, उसका जवाब सरकार को तसल्लीबख्श देना चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी ने सब से पहले तो हरिजन और बैकवर्ड के कोटे की बात की। शुक्र है परमात्मा का कि इन्होंने हरिजनों के बारे में कुछ हमदर्दी दिखाई। वरना तो उनके सब से ज्यादा खिलाफ थे तो ये थे।

---

## व्यैक्तिक स्पष्टीकरण

### चौधरी बंसी लाल द्वारा

**चौधरी बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदय, आन-ए-प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैं हरिजनों या बैकवर्ड क्लासिज के खिलाफ कभी नहीं रहा। (शोर)

**चौधरी भजन लाल :** तोशाम और भिवानी में हरिजन, चमार, एक भी आपको वोट नहीं डालता। (शोर)

**श्री सतबीर सिंह कादियान :** उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल तो हरिजनों को चीचड़ कहते हैं। (शोर)

**चौधरी बंसी लाल :** आन-ए-प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन अगेन। मैंने यह कहा था कि चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि अगर

भैंस खरीद लें तो चौधड़ तो साथ ही आ जाएगे । अगर ये जाटों को साथ ले लें तो चौधड़ तो साथ आ लेंगे । (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बाबू जगजीवन राम को छोटा कहा था । (शोर)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है । ये बाबू जगजीवन राम को कहने लगे कि ये दो कौड़ी का आदमी नहीं है । बाबू जी ने भिवानी की मीटिंग में खुद कहा था कि आदमी कौड़ी का नहीं होता । अगर ये रुपए का कह देते यानी 15 हजार रुपए या एक लाख रुपए का कह देते तो समझ में आता क्योंकि कौड़ी की तो कोई कीमत ही नहीं होती । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम जैसे भले आदमी के बारे में मुख्य मन्त्री जी ऐसी बात कह रहे हैं। मैंने उनकी शान के खिलाफ भी कभी नहीं कहा ।

चौधरी भजन लाल : जब ये मुख्य मन्त्री थे तो मैं इनकी कैबिनिट में मन्त्री था । इन्होंने रिवाड़ी में बाबू जगजीवन राम की स्टेज पर जूते फिंकवाए थे । (शोर) और भद्दी से भद्दी बात इन्होंने कही । यह रिकार्ड की बात है । यह बात मैं नहीं कहता ।

चौधरी बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन ।

चौधरी भजन लाल : किस बात का पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ?

चौधरी बंसी लाल : आप जरा सुनने की शक्ति रखिए । आपने हाउस का दो दिन का सैशन खत्म दिया । वह इसलिए खत्म दिया क्योंकि आपमें हमारी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भाग रहे हो । आप मेरी बात को ध्यान से सुनें । उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम मेरे मंत्रित्व काल में भी तशरीफ नहीं लाए । दूसरी बात यह कि बाबू जगजीवन राम के स्टेज पर एक आदमी ने रिवाड़ी में जूता फैंका था ।

चौधरी भजन लाल : चलो वह रिवाड़ी की बात होगी ।

चौधरी बंसी लाल : जब रिवाड़ी में जूता फैंका तो हमने उस आदमी को गिरफ्तार किया और उसको सजा कराई । उस आदमी के बारे में मैंने खुद सरकार से रिकार्ड ले कर बाबू जी को बताया कि यह डिफैंस के महकमे से मैंटली रिटार्डिड, डिसचार्जड किया गया है, यह इसका सर्टिफिकेट है । आप यह चैक कर लें और बाबू जी ने मान लिया कि हां है ।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुभाष बतरा) : स्पीकर साहब, मुझे इस बात का इल्म है कि बाबू जगजीवन राम रोहतक में आए थे उसके बाद उनका जलसा भिवानी में था । उन्होंने रोहतक में यह बात कही थी जिसको मैंने अपने कानों से सुना था । बाबू जी ने उस समय यह कहा था कि बंसी लाल ने मुझे दो कौड़ी का कहा है, अब मैं भिवानी में दो करोड़ आदमियों को देखने जा रहा हूं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कान से सुना था या अपनी आंख से देखा यह इनकी जड़ी हुई कहानी है । इनके पल्ले और कुछ नहीं है, यह यही कहेंगे ।

श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा) : स्पीकर साहब, मैं उस सभा में मौजूद था । जो बातें बतरा साहब ने कही है, मैं उसकी ताईद करता हूं । यह सच्ची बात है । ये सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है ।

---

## वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरिजन भाईयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों के रिजर्व कोटे के बारे में कहा । जब मैं छोड़ कर गया था उस समय सभी पोस्टों पर लगभग पूरा कोटा करके गया था यानि 20 परसैंट कोटा हरिजन भाईयों का पूरा करके गया था और 10 परसैंट कोटा बैकवर्ड क्लासिज भाईयों का पूरा करके गया था और यह बैकवर्ड क्लासिज का रिजर्व कोटा मैंने ही दो परसैंट से बढ़ा कर 10 परसैंट किया था । रोस्टर सिस्टम मैंने ही बनाया था । रोस्टर सिस्टम होना चाहिए ताकि तीन के बाद हरिजन लगे और बैकवर्ड क्लास का भाई भी लगे । इन्होंने उस रोस्टर सिस्टम को खत्म कर दिया । मैंने जो रोस्टर सिस्टम बनाया था, इन्होंने उसको तोड़ दिया । मैं रिजर्व कोटे को लगभग पूरा करके गया था, जब मैंने दोबारा आ करके देखा तो हरिजनों का 20 परसैंट से घट कर 12 परसैंट पर आ गया । अब हमने उसको 17 परसैंट के लगभग वापिस पहुंचा दिया है । जो मैंने बैकवर्ड क्लासिज का कोटा 10 परसैंट पूरा किया था, उसको इन्होंने घटा कर 6 परसैंट ला दिया, उसको हम 9 परसैंट के करीब वापिस ले आए हैं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने साढ़े तीन साल के अर्से में टोटल कितनी भर्तियां की ? जितनी भर्तियां की, उनमें कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड क्लासिज के भाई भर्ती किए ? आपने जो 30 एच0सी0एस0 भर्ती किए, उनमें हरिजन कितने और बैकवर्ड क्लासिज के कितने भर्ती किए ?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास टोटल आंकड़े नहीं हैं। वह अलग-अलग महकमे से लेने पड़ते हैं। आपको टोटल आंकड़े चाहिएं तो आप को लिख कर भेज देंगे।

**चौधरी बंसी लाल :** आप उन 30 एच0सी0एस0 का बता दें।

**चौधरी भजन लाल :** उसमें रिजर्वेशन नहीं होती। उनके रिकार्ड के आधार पर नोमिनेशन होती है। उसमें रिजर्वेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात यह कही कि वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लिया। इस बारे में हमारे पास पूरे आंकड़े हैं और वह आपको वित्त मंत्री बताएंगे। महकमे वाइज अलग-अलग स्कीम्ज के लिए कितना-कितना पैसा लिया अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। किस-किस महकमे ने कितना-कितना पैसा किस किस प्रयोजना के लिए लिया है, यह वित्त मन्त्री जी बता देंगे।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माईनिंग के बारे में कह दिया। एच0एम0एल0 के चेयरमैन ने भी कहा कि इसका कन्ट्रोल एच0एम0एल0 को देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन मैंने इसके बारे में आपको कहा था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक खानों का ताल्लुक है, फरीदाबाद में अनखपुर, बड़खल पाली प्राईवेट पार्टियों को सिलिका सैंड की माईनिंग दी गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करके अक्तूबर, 1986 में समय से पूर्व लीज समाप्त करके हरियाणा मिनरल्ज लिमिटिड को चौधरी बंसी लाल जी ने दे दी। (विघ्न) यह बात बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बाद में इस आदेशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4–12–86 को, माईनिंग की लीज के आदेश को अवैध घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10–12–86 को राज्य सरकार ने जब अपील की सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया कि नहीं, यह गलत है और फिर चौधरी बंसी लाल जी ने ही 18–12–86 को, जिनके पास पहले लीज पर थी, उनको वापस दी। इन्होंने अपने हाथ से उनको वापस की, यह रिकार्ड की बात है।

**चौधरी बंसी लाल :** मैंने तो हरियाणा मिनरल्ज लिमिटिड को दी थी। हाई कोर्ट ने भी इस प्वायंट पर स्टे दिया था कि प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नई अमैंडमैंट हुई थी पार्लियामैंट में, उसका हरियाणा के आफिसर्ज को पता नहीं था। अब यह कानूनी कार्यवाही पूरी करके छुट्टी करो।

**चौधरी भजन लाल :** ये वापस आपने 12वें महीने सन् 1986 में दी थी और मई तक आप चीफ मिनिस्टर रहे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जनवरी, 1994 को मिनरल्ज एक्ट 1957 में संशोधन करके भी उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र देने के लिए छूट दे दी कि दे सकते हैं। दूसरे अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कह

[चौधरी भजन लाल]

दिया और भारत सरकार ने भी कह दिया, भारत सरकार ने स्टे दे दी कि नहीं इनके पास रहेगी । अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व जिला फरीदाबाद में 1989 में महत्वपूर्ण खानें आनन्दपुर, पाली, बड़खल आदि नीलामी द्वारा दी जाती थीं । 1989 में हरियाणा मिनरल्ज लिमिटिड को 5 साल के लिए पट्टे पर दी गई । इन्हीं क्षेत्रों में सिलिका सैंड मेजर मिनरल्ज 1983-84 के लिए प्राईवेट पार्टियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई । फिर जो इनसे इंकम हुई, वह मैं बताना चाहता हूं । वर्ष 1986-87 में 5 करोड़ 12 लाख रुपए आए, वर्ष 1991-92 में 9 करोड़ 91 लाख रुपए, 1993-94 में 18 करोड़ 27 लाख रुपए और 1994-95 में 22 करोड़ रुपए होने जा रही है । कहां इनके वक्त में 5 करोड़ थी और कहां अब 22 करोड़ होने जा रही है, यानि 4 गुना ज्यादा इनकम आज इससे होने जा रही है ।

**चौधरी बंसी लाल** : जब के भाव और अब के भावों की तुलना करके देखो तो पता चलेगा ।

**चौधरी भजन लाल** : दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कह दी कि उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए । उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं । उनकी कुर्बानियों की वजह से देश आजाद हुआ । उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं और आजादी में सुख का सांस ले रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए । इन्होंने कहा कि फलां जगह पर 81 प्रतिशत और फलां जगह पर 69 प्रतिशत रिजर्वेशन है । स्पीकर साहब, ये वकील तो हैं लेकिन अखबार जरा कम पढ़ते हैं । ये कहते हैं कि अखबार दोपहर के बाद 8 आने रद्दी में बिकता है । सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि रिजर्वेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती । (विघ्न)

**चौधरी बंसी लाल** : अध्यक्ष महोदय, क्या तामिलनाडू में रिजर्वेशन 69 प्रतिशत नहीं है और क्या इसके लिए हिन्दुस्तान के विधान में तरमीम नहीं की गई ? (विघ्न)

**चौधरी भजन लाल** : उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? (विघ्न)

**चौधरी बंसी लाल** : अध्यक्ष महोदय, विधान के उस प्रोविजन को अल्ट्रावायरस कान्स्टीच्यूट कर दिया ।

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर किसी को मानना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत रिजर्वेशन हरिजन भाईयों के लिए, 10 प्रतिशत बैकवर्ड भाईयों के लिए, 17 प्रतिशत एक्स सर्विसमैन और दूसरे लोगों को तथा 3 प्रतिशत हैण्डीकैप्ड की रिजर्वेशन है । इस प्रकार यह 50 प्रतिशत रिजर्वेशन हो गई । इनमें से किसकी रिजर्वेशन कम की जा सकती है । किसी के कोटे को हम

कम नहीं कर सकते, इसलिए हम ने यह फैसला किया है कि जो कोटा पूरा नहीं होगा, उसमें सबसे पहले जो स्वाधीनता सेनानी हैं, जिन्होंने जंगे-आजादी में भाग लिया, उनके आश्रितों को उनके बेटे-बेटियों, पोते पोतियों, दोहते-दोहतियों को दिया जाए । (विघ्न) दूसरे इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बारे में कह दिया । खुदा का शुक्र है कि इनको भी कर्मचारियों की याद आई । चौधरी बंसी लाल जी ने कर्मचारियों की क्या हालत की थी । अध्यक्ष महोदय, एक लाख कर्मचारी दिल्ली में गए थे । उनके नुमाइंदे मुझे भी मिले थे, तब मैं केन्द्र में मन्त्री था , उन्होंने कहा था कि ये कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । मैंने भी इनसे कहा कि कम से कम इनकी बात तो सुन लें । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मैं इनकी कोई बात नहीं सुनता । इनका इलाज मैं जानता हूं । ये बड़े बदमाश हैं, डण्डों से इनको लम्बा बना दूंगा, इनकी सीधा कर दूंगा । मेरे हाथ में जूता है । (विघ्न)

---

## वैयक्तिक स्पष्टीकरण--

### चौधरी बंसी लाल द्वारा

**चौधरी बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी की यह आदत है कि वे गलत बात को 100 बार कह कर सच्ची बनाना चाहते हैं लेकिन वह सच्ची बनती नहीं है सरकारी कर्मचारियों के साथ इन्होंने जो किया है वे ही अगली बार इनका फातिया पढ़ कर बता देंगे कि ये कहां पर खड़े हैं ।

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, जब ये बोल रहे थे तो मैंने इनको बीच में नहीं रोका लेकिन ये बार-बार बोल कर मेरी स्पीड तोड़ देते हैं ।

**चौधरी बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि बाद में पूछ लेना और जब मैं पूछने के लिए खड़ा हुआ तो हाउस ऐडजर्न कर के भाग गए, इसलिए मुझे बीच-बीच में पूछना पड़ रहा है, वरना बीच में बोल कर मैं राजी नहीं हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी बंसी लाल जी हाउस का टाईम बढ़ाने के बाद भी अगर 10-12 मैम्बर्ज खड़े हो जाएं तो किस-किस को टाईम देंगे और फिर हाउस को अन-लिमिडिट समय के लिए तो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ऐडजर्न करना पड़ा था ।

**चौधरी बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, शायद सदन 2 दिन इसी लिए घटाया गया है ताकि सभी अच्छी तरह से बोल लें ।

---

## वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

**चौधरी भजन लाल :** क्या कोई मैम्बर बोलने के लिए खड़ा था, क्या किसी मैम्बर को बोलने में कोई रुचि थी । अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के सभी लोग बोल चुके थे, कोई बाकी नहीं था । इधर के भी सभी बोल लिये थे । अध्यक्ष महोदय, ये लोग तो रैलियों में लगे हुए थे । कोई 22 और कोई 23 प्रतिशत हैं, दोनों को मिला कर 45 प्रतिशत हो गए, बाकी बचे 55 प्रतिशत अकेली कांग्रेस पार्टी के । (विघ्न) मैंने तो 22 और 23 मिलाकर 45 प्रतिशत बताया था । 45 परसैंट में दोनों पार्टियों के, 55 परसैंट कांग्रेस के हो गये । दोनों को मिलाओ तो 100 ही होता है । (विघ्न) अब कर्मचारियों की हालत इन्होंने दिल्ली में जा कर क्या करी, यह भी सब जानते हैं । यहां पर ये हरियाणा की पुलिस ले गए और ये जमुना का पानी भर कर ले गए और इन्होंने उन कर्मचारियों के ऊपर पानी छुड़वाया था, उन्हें पानी में डूबो-डूबो कर बाहर निकाला । उन कर्मचारियों ने यह प्रण किया कि जब तक जिन्दा हैं बंसी लाल को नहीं आने देंगे । यह कसम उन्होंने जमुना का पानी हाथ में लेकर खाई और साढ़े तीन लाख कर्मचारियों ने अपने अपने रिश्तेदारों के वोट दूसरे बक्से में डाल दिए और इनका फातिया पढ़ा गया ।

**चौधरी बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस बात को मान लिया है और अब की बार तो इनका फातिया पढ़ा जाना है ।

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, हमने कर्मचारियों के लिए जो कुछ किया है, वह किसी ने भी नहीं किया है । कर्मचारियों का हमारे ऊपर विश्वास है, वे हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं । कर्मचारी तो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं । हम इनकी तरह जालिम नहीं हैं । हमने कर्मचारियों की हर बात का ध्यान रखा है । अध्यक्ष महोदय, मुझे मैम्बर्ज ने बताया कि बंसी लाल लौबी में कह रहे थे कि पं० चिरंजी लाल ने जो भजन लाल के खिलाफ बयान दिया है उस से वह कोई न कोई फायदा उठाना चाहता है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने तो हाउस में माना है कि इन्होंने कर्मचारियों को धमकी भी दी है । इस बारे में इन्होंने तीन बार माना है और यह रिकार्ड की बात है । आपने राजबीर के मामले में कहा कि आपने उसको धमकी दी । बंसी लाल जी धमकी देना तो कानूनी जुर्म है । (विघ्न) मैं तो उनसे अपनी बात कहता हूं । मैंने चिरंजी लाल के लड़के को नहीं धमकाया है । चिरंजी लाल जी चुने हुए नुमायंदे हैं, एम० पी० हैं । (विघ्न) वे हमारे साथी हैं ।

**चौधरी बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, आज तक मुख्य मन्त्री जी की कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है । पंडित चिरंजीलाल ने प्रैस कान्फ्रैंस में यह कहा है कि 3 जनवरी

को मुख्य मन्त्री ने स्वयं करनाल कचेहरी से एक सरकारी अधिकारी के टेलीफोन पर उनके पुत्र कुलदीप शर्मा, एडवोकेट को बुलाकर यह कहा और धमकी दी कि अपने पिता को समझा दें कि इन्होंने प्रधान मंत्री आवास पर मेरे सम्बन्ध में जो अपशब्द कहें हैं, वह ठीक बात नहीं है । मेरा नाम भजन लाल है और मैं रगड़ कर रख दूंगा । तेरे बाप जैसे 100 एम0 पी0 मैं अपनी जेब में रखता हूं । इस बारे में, आज तक मुख्यमन्त्री की कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है ।

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह लगता है कि यह ब्यान इनका ही छपवाया हुआ है । चिरंजी लाल तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते । अगर मैं इनका जवाब दूं तो मुझे अखबार में जवाब देने की क्या जरूरत है ? अगर कोई गलत बात कहेगा तो उसके लिए वह अनुशासनहीनता करेगा और अनुशासनहीनता के लिए कमेटी बनी हुई है इसलिए वह कमेटी ही इस बारे में ऐक्शन लेगी । हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है । हमने किसी को भी नहीं धमकाया और न ही हमारी धमकाने की कोई आदत है ।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हिसार डिस्टीलरी के बारे में भी कह दिया तथा कम्पट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल की रिपोर्ट का भी हवाला दिया । अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि पहले एक नियम था कि जब शीरा किसी को अलौट करते हैं तो उसमें कितनी परसैंट स्प्रिट बनेगी, इसका एक नार्म बना हुआ है । जैसे भट्ठे में बीस टन कोयले में एक लाख ईंटें बनेंगी । इसी तरह से जो कोयला बिजली के प्रोजेक्टस में जाता है, पावर स्टेशन में जाता है तो उसमें से कितनी परसैन्ट कोल जलनी चाहिए कितनी बिजली बननी चाहिये इसका एक नार्म है । यह नार्म बहुत पहले का यानि चालीस साल का मुकर्रर किया हुआ है कि इसमें से इतने परसैन्ट स्प्रिट बननी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लगभग सारी फैक्ट्रियों का मोडर्नाईजेशन किया गया । इसलिए शीरे में जो चीनी जाती है वह चीनी उसमें जानी कम हो गयी और चीनी की मिकदार बढ़ गयी । पहले जहां यह मिकदार 55 परसैंट थी, वहीं अब यह 40–42 परसैंट हो गयी । 1990–91 में जब इनका राज था जो सामने बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हिसार डिस्टीलरी की बाकायदा चैकिंग करवायी थी और इन्होंने एम0 शंकर सहित तीन आदमियों की एक कमेटी भी बनायी थी । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उसके मुताबिक अब जो नार्म्ज हैं, वह कम होने चाहिएं । अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने उसको बदलकर 30.5 परसैन्ट किया है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश एवं हमारी पानीपत की कोआपरेटिव शूगर मिल ने भी यह कम किया है । 1991–92 में हमारी पानीपत की कोआपरेटिव फैक्ट्री में 31.04 परसैन्ट शीरा बनी जबकि हिसार डिस्टीलरी में 31.77 परसैन्ट बनी । इसी तरह से 1992–93 में पानीपत की कोआपरेटिव फैक्ट्री में 30.26 परसैंट शीरा बनी जबकि हिसार डिस्टीलरी में 32.24 परसैन्ट । इसी प्रकार से 1993–94 में पानीपत की कोआपरेटिव फैक्ट्री में 26.14

[चौधरी भजन लाल]

और हिसार डिस्टलरी में 29.50 परसैंट शीरा बनी । अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है । इन्होंने आडीटर जनरल की रिपोर्ट उठायी और कहा कि 36.64 परसैन्ट बना दी और इसमें इतनी स्पिरिट बनती और इतनी शीरा बनती एवं इतनी शराब बनती । अध्यक्ष महोदय, यह तो एक क्वालिटी की बात है । जो कमेटी बनी हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी है और बताया है कि यह परसैंट क्या होनी चाहिए । अगर उस परसैन्ट से ज्यादा बने या कोई आदमी गड़बड़ करने की बात करे तब तो यह कह सकते हैं लेकिन इनको तो हिसार डिस्टलरी का बहुत फोबिया हो गया है । चाहे आपका राज रहा हो या हमारे सामने बैठने वालों का राज रहा हो, तो इन्होंने भी एक एक चीज को चैक करके देख लिया ।

**चौधरी बंसी लाल** : अध्यक्ष महोदय, हिसार डिस्टीलरी से हमें कोई ऐलर्जी नहीं है । मैं तो एक बात मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सी0ए0जी0 तो कोई पोलिटिकल आदमी नहीं है, उनकी रिपोर्ट में हिसार डिस्टीलरी का ही क्यों पैरा आया है, बाकी दोनों डिस्टलरी का पैरा क्यों नहीं आया ?

**चौधरी भजन लाल** : क्योंकि एक ही डिस्टीलरी का आडिट हुआ है, दूसरी डिस्टीलरीज का आडिट नहीं हुआ है । जब आडिट होगा तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी । अध्यक्ष महोदय, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट क्या कहती है, वह मैं आपको बताता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : बंसी लाल जी, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट तो आती रहती है, पहले भी आती रही है ।

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, आडीटर जनरल की रिपोर्ट किसको कहते हैं, यह उसको कहते हैं जैसे इन्होंने बिजली के सामान की परचेज की थी और उसका आडिट हुआ था । मैं आपको बताता हूं कि देश का आडीटर जनरल क्या कहता है ? 1972 में इन्होंने बिजली के तारों में एक करोड़ पचास लाख रुपये का घपला किया था, ट्रांसफार्मर्ज में इन्होंने दो करोड़ पचास लाख रुपये का घपला किया था, मीटर्ज में 85 लाख रुपये का घपला किया था, केबल्ज में तीस लाख रुपये का घपला किया था, फिर 15 लाख रुपये का घपला किया और उसके बाद फिर पोल्ज में 20 लाख रुपये का घपला किया है । पोल्ज के बारे में तो चौटाला साहब ने भी कहा है कि पंजाब के रिजैक्टिड हुए पुराने पोल्ज इन्होंने लिए । इसके अतिरिक्त दूसरे आईटम पर पचास लाख रुपये का घपला किया है, यानी कुल मिलाकर इन्होंने 6 करोड़ रुपये का घपला किया है । अध्यक्ष महोदय, आडीटर जनरल की रिपोर्ट इसको कहते हैं क्योंकि आडीटर जनरल की रिपोर्ट यह कहती है । रिपोर्ट उसको नहीं कहते हैं : 'आडीटर जनरल ने कहा कि बंसी लाल ने परचेज में इतना कमीशन खाया है ।'

## वैयक्तिक स्पष्टीकरण --

**चौधरी बंसी लाल द्वारा**

**चौधरी बंसी लाल** : ऑन ए प्वाइंट ऑफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन सर, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने चार कैबिनेट के मंत्रियों की कमेटी बनाई थी उसमें सरदार स्वर्ण सिंह, बी० आर० कुमारमंगलम, लॉ मिनिस्टर श्री गोखले और फखरुद्दीन अली अहमद थे । उसमें उन्होंने मुझे पूरी तरह से एग्जोनरेट किया था । (विघ्न)

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं । यह रिकार्ड की बात है । बेमतलब की गलत बात कहकर अपने आपको क्लीन पुट करने की कोशिश करते हैं । इसी बात को लेकर तीन साल तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी लोगों ने । (व्यवधान)

---

## वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शीरे के बारे में कह दिया । 50 परसैंट हम लेते हैं । यू० पी० में 65 परसैन्ट लेते हैं । फ्री करने के बारे में भी सोचेंगे । आदमी को सिर-पैर की बात कहनी चाहिए । इन्होंने कह दिया कि डी० सी०, एस० पी० आज एक जिले का प्रधान है कांग्रेस का, एक जनरल सैक्रेटरी बना हुआ है । चौधरी बंसी लाल जी, मैंने भी आपके साथ काम किया है । खुदा के वास्ते कुछ तो सच बोलो, नहीं तो यह छत गिर जाएगी और बहुत लोग दब जाएंगे । पहले लोग झूठ बोलते हुए डरते थे, आज तो आंख भी नहीं दुखती । (विघ्न)

**चौधरी बंसी लाल** : दो तारीख को जींद में क्या होने जा रहा है, वह भी बता दें ?

**चौधरी भजन लाल** : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह प्रथा डी० सी० को सारा काम सिपाही से लेकर एस० पी० तक, सारे काम पटवारी से लेकर डी० सी० तक यह प्रथा आपकी डाली हुई है, हमने उसको खत्म किया है, कम किया है । चाहे पार्टी का फंक्शन हो, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, एम० एल० ए० करेंगे, मंत्री करेंगे लेकिन डी० सी० और एस० पी० नहीं करेंगे । (विघ्न)

**चौधरी बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं । यह तो इनकी अपनी पार्टी का जिम्मेदार आदमी कह रहा है । पंडित चिरंजी लाल शर्मा कहते हैं कि हरियाणा में सरकारी अधिकारी ही कांग्रेस पार्टी की जगह लिए हुए हैं । डी० सी० प्रैजिडैण्ट हैं, पुलिस अधीक्षक वाइस प्रैजिडैण्ट है, तहसीलदार कोषाध्यक्ष और बी० डी० ओ० संगठन कार्यकर्ता का स्थान लिए हुए हैं । ये इनकी पार्टी के लोग कहते हैं ।

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने कहा कि मुकद्दमा दर्ज हो गया, तीन आदमी गिरफ्तार हो गए । पूरी कार्यवाही करने में लगे हैं । किसानों और बी० के० यू० वालों से मिलकर उनको पूरा मुआवजा दिलाएंगे । खाद के बारे में कह दिया कि कट्टे का वजन कम है । हो सकता है कोई न कोई गड़बड़ करता हो । हम नहीं कहते कि सारे ईमानदार लोग हैं । लेकिन जहां कहीं भी बात सरकार के ध्यान में आती है, सरकार फौरन उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही करती है । यह भी कह दिया कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत ठीक नहीं है, फिर कह दिया कि डी० सी० और एस० पी० की रिपोर्ट खराब कर देते हैं । आप जैसा आदमी भी यूं कहे, वैसे आजकल आपको हरिजनों से हमदर्दी हो गई है, उस वक्त जिनकी आपने रिपोर्ट लाल स्याही से खराब ही नहीं करी बल्कि सारी फाइल को पूरा हनुमान बना रखा था । उनकी सबकी फाइलें मंगाकर मैंने रिपोर्ट ठीक करके उनको प्रमोशन दी है । (विघ्न)

---

## वैयक्तिक स्पष्टीकरण

### चौधरी बंसी लाल द्वारा

**चौधरी बंसी लाल :** ऑन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन स्पीकर सर, अगर किसी का कसूर होगा तो मैंने उनकी ए० सी० आर० में उनके खिलाफ लिखा होगा । अच्छा काम करने वाले अफसरों को मैंने पदमश्री दिलाए, चार-चार इंक्रीमैंट दिलाई अच्छी से अच्छी ऐप्रीसिएशन की । गलत काम किया होगा तो ए० सी० आर० में भी लिखा होगा । हम किसी की गल्त रिपोर्ट नहीं लिखेंगे । आप ने तो बदले की भावना से रिपोर्टस लिखी हैं (शोर) मैंने तो आफिसर का काम देखा है, चाहे वह किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो । (शोर)

**चौधरी भजन लाल :** आपने इसलिये रिपोर्टस खराब लिखीं कि वह आदमी ऊपर न आ जाए, उसकी प्रोमोशन न हो जाए । आपने तो सौगंध खा रखी थी कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आपने इसी भेदभाव की वजह से उन लोगों के साथ ज्यादती की है । (शोर)

---

**चौधरी भजन लाल:** इसी तरह से यमुना वाटर के बारे में, मैंने काफी तफसील के साथ बताया है क्योंकि वह प्रदेश के हित में था । आपने हाईडल पावर के बारे में भी बताया है कि 1/3 बिजली बनती होगी । आप भी मुख्य मंत्री रहे हो, क्या 1/3 बनती है ? मैं कहता हूं कि बहुत थोड़ी बनती है और वह भी 70 पैसे यूनिट
13.00 बजे | आज घर में पड़ती है ।

**चौधरी बंसी लाल :** कितने मेगावाट बनती है, यह तो बता दो । (शोर)

**चौधरी भजन लाल :** यह तो भाखड़ा के पानी पर डिपैंड करता है । अगर पानी ज्यादा होगा तो बिजली ज्यादा बनेगी । वेरीऐशन होता रहता है । कभी नीचे 45 मेगावाट तक आ जाती है । केवल 20 परसैंट से ज्यादा है । (शोर)

**चौधरी बंसी लाल :** भाखड़ा की बिजली मिलाकर आप कल जीरो–आवर में हाउस में यह बता देना कि एक साल में कितने परसैंट मेगावाट आती है ?

**चौधरी भजन लाल :** 20 परसैंट से ज्यादा कभी कभी आती है । दूसरा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कह दिया कि होम मिनिस्ट्री का बुरा हाल है । बुरी हालत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । साथ में इन्होंने सुशीला हत्याकांड की बात भी यहां पर कर दी, हमें ज्यों ही पता चला तो हमने सी० बी० आई० से जांच के आदेश दे दिये लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं । उनकी जमानत हो गई है । मैं कहता हूं कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसकी जमानत नहीं होनी चाहिये, उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिये । (शोर) अगर बंसी लाल जी, वह जिंदा मिल गई तो फिर आपका क्या होगा ? फिर क्या इस्तीफा दे दोगे आप ? (शोर) इसी तरह से रणबीर सिंह सुहाग की बात भी इन्होंने कर दी । ज्यों ही हमें पता चला, हमने यह मामला सी० बी० आई० के हवाले कर दिया । जांच के आदेश कर दिये, जिसका दोष होगा, उसे अवश्य सजा मिलेगी ।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि मुख्य मंत्री जानते हैं कि सुशीला कहां है, इसलिये वे बता दें ।

**चौधरी भजन लाल :** उसकी कोई हाडी थोड़ा मिली है । हम इस बात के लिये पीछे हैं, सी० बी० आई० भी पीछे लगी हुई है । जब पता चल जायेगा तो हम आपको बता देंगे । इसी तरह से नहरों के बारे में भी बता देता हूं कि नहरों की सफाई के लिये पैसा हम ने दिया ताकि टेल तक पानी जा सके और किसानों को उससे फायदा हो सके ।

इसी तरह से टूरिज्म की बात है । इस समय हमारा टूरिज्म सारे हिंदुस्तान में बेहतरीन है, नम्बर वन पर है । जो सुझाव इनकी ओर से आए हैं, हम उनको चैक कर लेंगे, अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा लेकिन मेहरबानी

[चौधरी भजन लाल]

करके बंसीलाल जी आप ठीक बोला करें, इनका ख्याल किया करें, बहुत उम्र हो गई है आपकी । इस उम्र में तो आदमी को सही बोलना चाहिये क्योंकि आगे जाकर भगवान को भी जवाब देना है । वह भी आपसे हिसाब किताब मांगेगा ।

**श्री अध्यक्ष :** गन्ने का भाव जो साढ़े तीन सौ, चार सौ बताया है, उस बारे में भी बता दें ।

**चौधरी भजन लाल :** ऐसा नहीं कहा होगा स्पीकर साहब । मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्या कहा गन्ने के बारे में और ये कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इनको गन्ने का तो पता ही नहीं है । जिस इलाके के ये लोग रहने वाले हैं, उस इलाके में तो लोग यह कहा करते हैं कि गुड़ की भेली जो है, वह पेड़ को लगती है । (हंसी) इनको क्या पता है कि गन्ना किस को कहते हैं ? (शोर) एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी ने दो अप्रैल की रैली के बारे में कहा कि वह पोस्टपोन क्यों कर दी ? मैं प्रैस के भाइयों को भी बताना चाहता हूं और सदन को भी बताना चाहता हूं कि तीन अप्रैल को प्रधान मंत्री जी ने मेवात में माइनोरिटीज के बजट के बारे में अपना प्रोग्राम रख दिया इसलिए हमें दो अप्रैल की रैली पोस्टपोन करनी पड़ी । बाकी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्वायंट उठाए थे, उनका जवाब मैंने दे दिया है, धन्यवाद ।

**श्री ओम प्रकाश बेरी (बेरी) :** अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 3, 5, 9, 10, 17, 18, 22 तथा 23 के बारे में बोलूंगा क्योंकि इन पर मैंने कट मोशंज दिए हुए हैं । सब से पहले जैसे मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्ज को दो परसैंट रिजर्वेशन दी हुई है । वह भी एक्स सर्विसमैन के कोटे में से काट कर दी हुई है । इस बारे में मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा । आपने इसमें लिखा है कि अगर 17 परसैंट एक्स सर्विसमैन के डिपैंडेण्ट मिल गए तो फ्रीडम फाइटर्ज को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी । यह रिजर्वेशन भी केवल क्लास थ्री में है । जिस तरह से पंजाब और हिमाचल में यह रिजर्वेशन क्लास वन तक है उसी तरह से हरियाणा में भी होनी चाहिए । इसमें अगर किसी अमैंडमैंट की जरूरत हो तो उस बारे में सरकार को हिंदुस्तान की सरकार को लिखना चाहिए ताकि वह कांस्टीच्यूशन में अमैंडमैंट करें । अब मैं डिमांड नं० 3 के बारे में कहना चाहता हूं । आज चौधरी भजन लाल क्लेम करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अन्दर सब से अच्छी कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में है । अब मैं इस बारे में क्या कहूं क्योंकि इनको असत्य बोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है । पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पर कानून व्यवस्था खराब है तो वह हरियाणा में है । यह सरकार 1991 में बनी थी । उस वक्त मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी शेखी से कहा था कि अगर हमारे राज्य में रात को गहने पहन कर औरत निकल जाए तो उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है । आज

आप रात की बात छोड़ दें, कोई औरत दिन में भी चले, तो भी उसकी सुरक्षा की गारन्टी नहीं है । इसका जीता जागता उदाहरण सुशीला कुमारी का अपहरण कांड है । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । क्योंकि इस केस में अपराधी मुख्य मन्त्री जी से संबंधित थे, इस कारण से हरियाणा की पुलिस ने इस केस में दिलचस्पी नहीं ली । उसके बाद सी0 बी0 आई0 ने दूध का दूध और पानी का पानी निकाल कर रख दिया ।

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । एक ही बात को रोज रोज उठाने का क्या मतलब है । अगर ये ऐसा करेंगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा ।

**श्री ओम प्रकाश बेरी** : ठीक है सारी बातें आ चुकी । स्पीकर साहब, सुशीला का कसूर यह था कि उसने नकल नहीं करने दी । (शोर)

**चौधरी भजन लाल** : उस केस के बारे में जांच करने के लिए हमने खुद सी0 बी0 आई0 को लिखा था ।

**श्री अध्यक्ष** : बेरी साहब, इसके बारे में बार बार जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है । पहले भी इसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है । उसकी इंवैस्टीगेशन चल रही है ।

**श्री ओम प्रकाश बेरी** : स्पीकर साहब, अकेले सुशीला कांड की ही बात नहीं है । सेखों हत्या कांड हुआ । उसकी जांच सी0 बी0 आई0 ने की । उस केस में हरियाणा पुलिस नाकामयाब रही । इसी तरह से रणवीर सिंह सुहाग की हत्या की गई । (शोर)

**श्री अध्यक्ष** : इसके बारे में आप कुछ न कहें । ये सारे मामले सबजुडिश हैं ।

**श्री ओम प्रकाश बेरी** : स्पीकर साहब, मैं अब तक ला एण्ड आर्डर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं । क्या आप मुझे बोलने के लिए टाईम नहीं देना चाहते ला एण्ड आर्डर के बारे में डिमांड है उसके बारे में मैंने कट मोशन दी हुई है । आप मुझे मेरी बात कहने दें । स्पीकर साहब जितनी भी हत्याओं के बड़े बड़े कांड हुए हैं, उनके बारे में हर दफा अपोजिशन पार्टीज सी0 बी0 आई0 से इंवैस्टीगेशन की मांग करती हैं । इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा की पुलिस पर आम आदमी का यकीन नहीं रहा है और हरियाणा की पुलिस कतई तौर पर लोगों को हरास करने के लिए है । लोगों की हैल्प करने के लिए कतई तौर पर नहीं है । पूरे हरियाणा प्रदेश में जंगल का राज कायम है और प्रदेश में कानून का राज नहीं है । पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं वे छोटे अधिकारियों पर दबाव डाल कर नाजायज काम करवाते हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार पुलिस की यूनियन

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

क्यों नहीं बनाती । पुलिस की यूनियन बने ताकि वे अपनी बात सही ढंग से सरकार तक पहुंचा सके और किसी दबाव में काम न करें । ला एण्ड आर्डर में सुधार होना बहुत जरूरी है । यदि उनकी यूनियन होगी तो वे अपनी ग्रिवैंसिज सरकार के सामने रख सकेंगे ।

स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी ने टैक्सेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए । मुख्य मंत्री जी आप मेरी बात को ध्यान से सुने । यह कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है । इसके मुताबिक मैं एक बात खास तौर से कहना चाहूंगा । जिस तरह से आपने कहा है कि नार्म्ज बदल गए हैं । इस रिपोर्ट में एक बात यह लिखी हुई है :—

"The case was referred to Government in 1991. The reply has not been received....."

श्री अध्यक्ष : यह रिपोर्ट तो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी और पी० ए० सी० के सामने जाती है ।यह रिपोर्ट हाउस में डिस्कस नहीं हो सकती ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मैं यह डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इन्होंने कहा है कि नार्म्ज बदल गए हैं, अगर नार्म्ज बदल गए हैं, उस बात को सही माना है। यह केस 1991 में रैफर किया गया था, इसका अक्तूबर 1994 तक कोई जवाब नहीं दिया । इसका जवाब दिया जा सकता था ताकि यह चीज क्लीयर हो जाती ।

इसी प्रकार से मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा । वित्त मंत्री जी ने 1995-96 के जो बजट अनुमान पेश किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 110 प्राइमरी स्कूल, 102 मिडल स्कूल और 40 हाई स्कूल अपग्रेड करने का काम किया है । सिर्फ स्कूलों को अपग्रेड करने से शिक्षा के स्तर में सुधार होने वाला नहीं है । स्पीकर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं और सरकार अच्छी तरह से जानती है कि जो 10 जमा 2 प्रणाली के स्कूल हैं उनमें अध्यापकों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं । अंग्रेजी, हिसाब और साईंस सब्जैक्टों के पद अब तक नहीं भरे जा सके हैं । स्पीकर साहब, अजमत खां जी का सवाल नम्बर 1144 जो 14-3-95 को फिक्स था उसके जवाब में एजूकेशन के बारे में बड़ी गलेरिंग फिगर्ज दी गई हैं। मेवात के एरिया में हैडमास्टर्ज के 49 पद खाली पड़े हैं। अब आप ही बताएं कि शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार होगा । जो सरकारी स्कूल हैं उनका हाल इस कद्र है कि ये स्कूल गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चों को रोकने के लिये बाड़े बने हुए हैं। मेरा ख्याल है यह गलत बात नहीं है । आजकल जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये पब्लिक स्कूलों में दाखिल करवाते हैं। जो मिनिस्टर और एम०एल०एज० हैं वे भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने यह मान लिया है कि जहां तक सरकारी स्कूलों की

शिक्षा के स्तर का ताल्लुक है वह कतई तौर पर अच्छा नहीं है। अगर शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं करेंगे तो इस प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। शिक्षा के स्तर में सुधार करना बहुत आवश्यक है। अकेले स्कूलों को अपग्रेड करने से बात नहीं बनेगी। मूल रूप से शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिये। जो प्राइवेट स्कूल दुकानों के रूप में चल रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिये ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो।

अब मैं डिमांड नं0 10 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे मेरा कहना यह है जो रूरल एरियाज में डिस्पेंसरीज और पी0एच0सीज0 हैं उनमें कोई भी डाक्टर जाना पसंद नहीं करते। पोस्टिंग तो कर दी जाती है लेकिन वे वहां पर 15 दिन बाद एक दिन जाकर हाजिरी लगा देते हैं। उनका आम आदमियों को कोई फायदा नहीं है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो नए नए डाक्टर्ज लगाएं उनके लिये यह कंडीशन रख दें कि पहले पांच साल उन्हें रूरल एरियाज में सर्विस करनी पड़ेगी। यदि सरकार ऐसा कर देती है तो फिर आम आदमी जो गांव में रह रहा है, उसको फायदा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 17 के बारे में कहना चाहता हूं। दक्षिण हरियाणा में स्प्रिंकलर सैटस काफी मात्रा में लगाये जाते हैं। उन पर वित्त मंत्री जी ने सेल्ज टैक्स में छूट दी इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो नकली खाद, पेस्टीसाइड और बीज बेचा जा रहा है यह सब अधिकारियों द्वारा डीलर के साथ मिलकर बेचा जा रहा है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिये और जिस तरह से पंजाब में ए0डी0 ओज0 को सैम्पल लेने की पावर्ज हैं हमारे यहां पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिये ताकि इस पर रोक लग सके और किसानों को उसका फायदा हो सके। अब तक यहां पर केवल क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपैक्टर को ही पावर है जो जिले में एक होता है। अतः मैं चाहूंगा कि ए0डी0ओज0 को सैम्पल लेने की पावर्ज दी जाएं। जो इनसैक्टीसाइड्ज हैं उसका हर बैच का सैम्पल लिया जाना चाहिये। इस पद्धति को अपनाया जाता है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

अब मैं डिमांड नं0 18 पर बोलना चाहता हूं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के लागू होने के बाद जो वी0एल0डी0एज0 हैं उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं रहा। अब इस अधिनियम के जरिए क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी गई है। यह इण्डियन वैटरनरी एक्ट 10 साल से बना हुआ है। इसका जो सैक्शन 15 है उसमें क्वालिफिकेशन है। यदि इसमें अमैंडमैंट कर दी जायें और भारत सरकार को हरियाणा सरकार लिख दे तो ऐसा सम्भव हो सकता है।

---

## वॉक आउट

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, आप बैठिए।

**श्री ओम प्रकाश बेरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक सुझाव दे रहा हूं। कृपया मुझे बोलने दें।

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठिए।

**श्री ओम प्रकाश बेरी :** यदि आप मुझे बोलने देना नहीं चाहते तो मैं विरोध स्वरूप वाक आउट करता हूं।

(इस समय माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश बेरी सदन से वाक आउट कर गए।)

---

## वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

**श्री राम भजन अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 5 पर बोलना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने जो फार्म नं0 15 पर व्यापारियों को छूट दी इसके लिये मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार बैरियर्ज हटा कर व्यापारियों को राहत दी है, उसी प्रकार ऑक्ट्राय भी अबोलिश कर देना चाहिये। 17 स्टेटों में ऑक्ट्राय नहीं है। इस काम के लिये जो अधिकारी, मुनशी, चपड़ासी आदि लगे हुए हैं, उनका खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम होती है। आक्ट्राय जितना वसूल करते हैं उस को वसूल करने पर उतना ही खर्च हो जाता है, इसलिये उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चुंगी जैसी बीमारी को इस प्रदेश से समाप्त करें। जिस प्रकार बैरियर्ज हटाने से सरकार को लाभ हुआ है, वैसे ही चुंगी हट जाने से सरकार को लाभ होगा। (विघ्न)

**स्थानीय शासन राज्य मंत्री (चौधरी धर्मबीर गाबा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास चुंगी से 19 करोड़ 70 लाख रुपये की प्राप्ति होती है। माननीय सदस्य चुंगी हटाने की बात तो कर रहे हैं इसके साथ ही यह कोई आल्टरनेटिव तो बताएं जिससे कि हम यह राशि प्राप्त कर सकें। लोग यह चाहते हैं कि शहरों के अन्दर उनको हर फैसिलिटी प्राप्त हो। लोगों को यह फैसिलिटीज तभी दिलवाई जा सकती हैं जब हमारे पास सफिशियेंट पैसा हो। इसके लिये ये कोई सोर्स बताएं कि पैसा कहां से इकट्ठा किया जा सकता है। इन्होंने गलत बात कही है कि जितनी चुंगी वसूल होती है उतना तो उसको कलैक्ट करने पर ही लग जाता है। स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है हमारा एक्सपैंडीचर चुंगी वसूल करने पर 60 प्रतिशत खर्च होता है और 40 प्रतिशत हमें बचता है।

**श्री राम भजन अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने खुद माना है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा पैसा तो इनको चुंगी वसूल करने में ही खर्च हो जाता है। जो पैसा बचता है उस बारे में सरकार पूरी तरह से विचार करे कि कैसे इस पैसे को जुटाया जा सकता है। सरकार के लिये इतना पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे पहले बैरियर्ज पर टैक्स के लिये रुकना पड़ता था चुंगी के लिये गाड़ियां, ट्रैक्टर और ट्रकों आदि को

रोकते हैं उससे समय भी वैस्ट होता है और उसके लिये सरकार को भी खर्च करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि मिलावट की टैस्टिंग के लिये डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लैबोरेटरीज होनी चाहियें ताकि वहां पर व्यापारी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर माल बेचने से पहले उसको टैस्ट करवा लें और क्वालिटी के बारे में सुनिश्चित कर लें। मिलावट के केस में कानून हो कर सजा का भी प्रावधान है इसलिये डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लैबोरेटरीज का होना बहुत ही जरूरी है। व्यापारी तो मैन्यूफैक्चरर से माल खरीदते हैं उनको यह पता नहीं होता कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। इसके साथ ही एक और प्रावधान भी होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि छोटे व्यापारियों को सुविधाएं दे रहे हैं। मिलावट को रोकने के लिये कानून बना हुआ है जिसके अन्दर इन्सपैक्टर्ज नमूने लेने के लिये जाते हैं। आजकल इसमें काफी करप्शन हो रही है। इन्सपैक्टर दुकानों पर जा कर उनके साथ सौदेबाजी करते हैं कि या तो इतने रुपये दो नहीं तो सैम्पल भरेंगे। मजबूर हो कर दुकानदारों को उनकी बात माननी पड़ती है। इसी तरह से आक्ट्राय में भी करप्शन है। ट्रकों के ट्रक निकल जाते हैं। 200/- रुपये दे कर वह बिना चुंगी के अपना माल निकाल ले जाते हैं। लेकिन जो छोटा दुकानदार है या छोटा जमींदार है जो कि किलों घी लाता है या कोई और छोटी चीज लाता है उसको टैक्स देना पड़ता है और बड़े लोग उसकी चोरी कर लेते हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि 50 प्रतिशत तो इस पर सरकार को वैसे ही खर्च करना पड़ता बाकी का जो पैसा है वह किन्हीं दूसरे साधनों से जुटाया जा सकता है इसके लिये सोचा जा सकता है किसी और मद में इस को बढ़ा कर पूरा किया जा सकता है। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार स्ट्रीट लाईट की बिजली का खर्च लोगों पर 2 पैसे प्रति यूनिट लगा कर बिल भरा जाता है उसी प्रकार चुंगी के बारे में भी कर सकते हैं या फिर इस बारे में कोई और जरिया भी ढूंढा जा सकता है और यह पैसा व्यापारियों से तथा दूसरे लोगों से इकट्ठा किया जा सकता है।

चौधरी धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, यह जो आक्ट्राय के बारे में इन्होंने दोबारा बात उठाई है। मैं आदरणीय सदस्य के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि आज हम ने जो म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक्शन करवाए हैं, यह कांग्रेस पार्टी ने ही करवाए हैं। उसके बावजूद हमने यह फैसला किया है कि इनका प्राईवेटाईजेशन किया जाए। जो भी म्युनिसिपल कमेटी हमें अपना रैजोल्यूशन भेजेगी कि हम कंट्रैक्ट बेसिज पर देना चाहते हैं तो हम आक्ट्राय को कंट्रैक्ट बेसिज पर देंगे। इससे एक फायदा यह जरूर होगा कि जो हमारी इनकम है वह तीन गुणा होगी। इस प्रकार हम यह करने जा रहे हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आक्ट्राय को कंट्रैक्ट बेसिज पर सरकार देगी उससे आमदनी जरूर बढ़ेगी क्योंकि जो सरकार के अधिकारी हैं वे चोरियां नहीं रोक पाते हैं लेकिन कंट्रैक्टर इसे अपने स्वार्थ के लिये रोक देगा।

[श्री राम भजन अग्रवाल]

अध्यक्ष महोदय, मेरा वाटर रेट के बारे में सरकार को एक सुझाव है। सरकार ने इस साल में रेट तीन दफा बढ़ा दिए हैं लेकिन पानी नहीं है। एक रेट तो ऐसा है कि एक टूटी पर 24 रुपए लगेंगे और एक से अधिक पर 40 रुपए के करीब लगेंगे। वैसे तो टूटियों में पानी आता ही नहीं है, अगर आता है तो एक में भी उतना ही आता है और तीन में भी उतना ही आता है। एक से अधिक टूटियों में इन्होंने ज्यादा टैक्स का प्रावधान रखा है, यह कोई न्याय संगत बात नहीं है। अगर प्रैशर ज्यादा होता है तो पानी आ जाता है। आज तो स्टेट में नल ही बहुत ज्यादा लग गए हैं। 200 कनैक्शनों के लिये 3 इंच लाईन बिछाई गई थी और आज 1000 के करीब कनैक्शन दे दिए गए हैं जिस कारण से पानी का प्रैशर बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिये मैं बहन जी से कहूंगा कि इस टैक्स वाली बात पर ये पुनः विचार करें। आज एक आदमी मकान का महीने का किराया तो 50 रुपये देता है और पानी का बिल 100 रुपए महीना आ जाएगा। इसीलिये आप सस्ते पानी का प्रावधान करें। आदमी शराब, तथा दूसरी चीजें तो छोड़ सकता है लेकिन पानी नहीं छोड़ सकता है। इसलिये आप पानी को मंहगा न करें। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री छत्तर सिंह चौहान (मुंढालखुर्द) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नं0 6 पर बोलूंगा जो वित्त मंत्री जी के विभाग से सम्बन्धित है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनको दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी जब आप जवाब दें तो उसमें यह बता देना कि हरियाणा प्रदेश पर हरियाणा के बोर्ड और कारपोरेशंज का 1986-87 में, 1991-92 में और 1994-95 में कितना कर्जा था। (विघ्न) दूसरी बात यह है कि ये कोई भी डिपार्टमैंट ले लें, इनका 80 प्रतिशत आफ-दि-बजट साल के आखिर में खर्च होता है। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि सारे साल का जितना बजट है उसको क्वार्टर में बांटा जाए। यह बात जो साल के आखिर में पैसा खर्च करने वाली बात है, यह हमें एस्टीमेट कमेटी में डिपार्टमैंट वालों ने बताई थी। क्या जरूरत है कि 31 मार्च को ट्रेजरी और बैंक 12 बजे तक खुलें। 80 प्रतिशत बिल आखिरी तीन दिनों में ही बन जाते हैं। यह पब्लिक की मनी है इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। कमेटी मीटिंग में डिपार्टमैंट ने बताया कि बजट तो अलाट हो जाता है लेकिन हमें फाईनैंशियल सैंक्शन नहीं मिलती है। इसलिये वित्त मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें। इसके अलावा मैं तीसरी बात वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। इन्होंने खुद एक महाजन परिवार में जन्म लिया है इसलिये महाजन तो उसे कहते हैं जो किफायतदार हो। इनको तो गवर्नमैंट की कुछ इकोनोमी को ठीक करना चाहिये। यह ठीक है कि ये मन्त्रियों को कम नहीं कर सकते। स्पीकर सर, मैं कुछ सुझाव इनको देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से हर डिपार्टमैंट में चाहे कोई जीप हो या कोई गाड़ी हो, उनमें डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी और सब डिविजन लैवल पर पैट्रोल या डीजल बिना बात के खर्च किया जाता है।

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष :** वित्त मंत्री जी आप जवाब देने के लिये कितना समय लेंगे ?

**वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गप्ता) :** सर, आप मुझे जितना भी समय देंगे मैं उतने समय में ही बोल लूंगा ।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है ।

---

## वर्ष 1995-96 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

**प्रो0 उत्तर सिंह चौहान :** स्पीकर सर, इनको एक बिल बनाना चाहिये कि जिस किसी ऑफिसर को भी गाड़ी चाहिये, वह अपनी रिक्वीजिशन भेजे क्योंकि आज देखा जाता है कि मूली खरीदने के लिये भी अफसरों की गाड़ी जा रही है, बच्चे स्कूल भेजने के लिये भी गाड़ी जा रही है, रिश्तेदार को छोड़ने के लिये भी गाड़ी जा रही है इसलिये हम तो यह सोचते हैं कि यह सब पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिये। वित्त मन्त्री जी, आपने तो एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म ले रखा है जिसमें economy must be in your blood.

स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नं0 आठ पर जो कि सड़कों से संबंध रखती है और जिसके अमर सिंह जी मंत्री हैं के बारे में बोलना चाहूंगा । सर, आपने भी इस हाउस को दस दिन से देखा है कि इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के मैम्बर्ज की तरफ से सिर्फ दो ही बातों पर जोर दिया जा रहा है । एक तो यह कि नहर टूटी पड़ी है और दूसरे सड़कें टूटी पड़ी हैं । (विघ्न)सर, मैं इनको सुझाव दे रहा हूं । एक बात तो आप भी मानेंगे कि आज सारे प्रदेश के लोग इस बात से चिंतित हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं और उनकी चिंता ठीक भी है । इसलिये मैं कहूंगा कि इनको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिये ताकि सड़कों की मरम्मत हो सकें । एक बार मैं और लाला रामभजन अग्रवाल चौधरी अमर सिंह जी से मिलने गए तो इन्होंने हमसे कहा था कि मैं सड़कों को नया कोट पहना दूंगा । सर, लेकिन अब इन्होंने तो नया कोट पहन लिया किन्तु सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हुई है । (विघ्न)

स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नं0 9 जो कि ऐजूकेशन के संबंध रखती है, पर बोलना चाहूंगा । आज सरकार नकल रोकने के लिये मानसिक रूप से प्रयास कर रही है जिसमें इनको सफलता भी मिली है जिसके लिये मैं इनको बधाई भी देना चाहूंगा । लेकिन नकल क्यों होती है इसकी गहराई में ये नहीं गए ? नकल इसलिये होती है क्योंकि स्कूलों में अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं इनका जो स्टाफ है जैसे डी0पी0आई0 या दूसरा ट्रेनिंग

[प्रो0 छत्तर सिंह चौहान]

स्टाफ है वह कभी भी स्कूलों में इंसपैक्ट करने नहीं जाता। मंत्री जी भी कभी चैक करने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको समय ही नहीं है। स्पीकर सर, आप तो एक महान शिक्षाविद रहे हैं, आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश और प्रदेश में आज दो तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक तो पब्लिक स्कूल की प्रणाली है जिसमें मांगे राम जैसों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी प्रणाली है गवर्नमैंट स्कूल। एक गवर्नमैंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा पब्लिक स्कूल वाले पढ़े हुए बच्चे को कम्पीट नहीं कर सकता। इसलिये सरकार को इस प्रकार की दोहरी प्रणालियों को समाप्त करना चाहिये और अपने शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई की ठीक व्यवस्था करनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** चौहान साहब, जब तक प्राईवेट प्रोपर्टी रहेगी, तब तक ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

**प्रो0 छत्तर सिंह चौहान :** स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नं0 22 पर जो कि को-आप्रेटिव डिपार्टमैंट से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा। आज हरियाणा के लोग इस डिपार्टमैंट को डिपार्टमैंट आफ करप्शन भी कहते हैं क्योंकि इस डिपार्टमैंट में आज करप्शन है। (विघ्न)

**प्रो0 राम विलास शर्मा :** स्पीकर सर, पीरचन्द, अमर सिंह जी और धर्मपाल, ये सभी पहले एक साथ थे, इनकी आपस में बनी मोहब्बत थी। इसलिये वह इन को इंट्रप्ट कर रहे हैं। (विघ्न)

**सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि वे या तो सदन में यह बात साबित करें कि करप्शन कहां है अन्यथा यहां इस तरह की बात न करें। (विघ्न)

**प्रो0 छत्तर सिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदय, मैं पहले करप्शन वाली बात बता देता हूं। कैथल के ए0आर0 आफिस में जगदीश नारायण नाम का एक क्लर्क 13-2-1976 से 9-8-1989 तक रहा। इन तेरह सालों में वह एक सीट पर ही रहा, उसके रहते आठ असिसटैंट रजिस्ट्रार आए। इस आदमी ने सबसे पहले 9 लाख 79 हजार का गबन किया, उसके पश्चात् वह हर साल इसी तरह करता रहा। यह ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है जिसके पेज 52 से 54 तक सारा विवरण दिया है। इसने टोटल 19 लाख 58 हजार 405 रुपये सत्तर पैसे का गबन किया और इसके खिलाफ कार्यवाही यह की कि इसको वहीं रखा। न ए0आर0 के खिलाफ कार्यवाही की, न किसी और के खिलाफ कार्यवाही की। (विघ्न)

**श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस विधान सभा में बैठते बैठते तीन वर्ष के लगभग हो गए। क्या इनका इतना भी कर्त्तव्य नहीं बनता कि इनकी नौलेज में भ्रष्ट व्यक्ति आ गया तो चिट्ठी ही लिख देते।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान :** बहिन जी, ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है।

**श्री अध्यक्ष :** चौहान साहब, आपको पहले भी बताया है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है, वह हाउस में डिसकस नहीं होती।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान :** ठीक है जी मैं वह डिसकस नहीं करता, दूसरी बातो पर आ जाता हूं। मैं डिमांड नंबर 15 पर बोलना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से टूटी सड़कों को लेकर सारे हरियाणा की जनता और विधान सभा के सदस्य चिंतित हैं, इसी प्रकार सारी नहरें मिट्टी से भरी पड़ी हैं। दक्षिणी हरियाणा का पानी नेहरा साहब हिसार और सिरसा ले गए। एस०वाई०एल० बनाने का नाम नहीं ले रहे। अध्यक्ष महोदय, ये एस०वाई०एल० नहीं बना सकते क्योंकि इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। यमुना जल समझौता इसलिये करना पड़ा क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी थी। ये हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहरों की सफाई के लिये सारी जनता चिंतित है। कल चौधरी सूरज मल भी इसी बारे बोल रहे थे। चौधरी सूरज मल ने किसान के घर में जन्म लिया है। वैसे किसान के यहां तो नेहरा साहब ने भी जन्म लिया है लेकिन उन्हें मन्त्री पद ने सारा कुछ भुला दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हरियाणा की सारी नहरें सिल्ट से भरी पड़ी हैं उनकी सफाई की वारफुटिंग पर जरूरत है।

स्पीकर साहब, मुख्यमन्त्री महोदय ने चौधरी बंसीलाल जी के बारे में यह कह दिया कि वे हरिजनों के बहुत खिलाफ थे, उन्होंने जगजीवन राम जी का भी नाम ले दिया कि चौधरी बंसी लाल जी ने इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा। स्पीकर साहब, शायद चौधरी भजन लाल जी की यादाश्त कमजोर है। वे तो खुद बड़े लीडर्ज के बारे में कहते रहे हैं, नाम दूसरों का लेते हैं। उनको याद होगा 2 अक्तूबर, 1979 को मुख्यमन्त्री भिवानी में किसी हस्पताल का उद्‌घाटन करने के लिये गए थे और उस वक्त इन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस का चुनाव निशान तो खूनी पंजा है और श्रीमती इन्दिरा गांधी जो उस वक्त देश की प्रधानमन्त्री थी, के बारे में भी यह कहा कि यह देश की सब से ज्यादा भ्रष्ट औरत है, और उसके तीन दिनों के बाद ही ये कांग्रेस में आ गये। वह आदमी चौधरी बंसी लाल जी जैसे कर्मठ व्यक्ति के बारे गलत कहे तो यह कितनी शर्म की बात है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि कोई आदमी किसी के दामन पर दाग लगाने से पहले अपना दामन तो देख ले। धन्यवाद।

**श्री सतबीर सिंह कादियान (नौलथा) :** स्पीकर सर मैं एक दो सुझाव ही देना चाहता हूं। इस विधान सभा की अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं उनकी मीटिंग भी होती रहती हैं और उनकी रिपोर्टस भी समय समय पर आती रहती हैं। कमेटी उन रिपोर्टस की स्क्रूटनी करती है। कमेटीज के जो स्कोप एंड फंक्शंज हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं। कमेटीज की रिकमैंडेशंज/औब्जर्वेशंज को इम्पलीमैंट करने के लिये आफिसर्ज की ड्यूटी लगायी जाती है और उनको यह कहा जाता है कि आप इनके बारे में 5-6 महीनों में एक्शन लेकर हमें सूचित करें। एक्शन इनीशीयेट करें। परन्तु कमेटीज उनकी

[श्री सतबीर सिंह कादियान]

रिपोर्टस के लिये इन्तजार करती रहती हैं ताकि रिपोर्टस को फाइनल किया जा सके। लेकिन सरकार के वे बेलगाम ऑफिसर अपनी रिपोर्ट सही टाईम पर नहीं देते जोकि इस प्रदेश के हित में नहीं है। अगर उनकी रिपोर्ट समय पर न आये तो फिर इन विधान सभा की कमेटियों का औचित्य ही क्या रह गया। इस सब बातों को हम सभी मैम्बर्ज रियालाइज करते हैं चाहे कोई रूलिंग पार्टी से सम्बन्धित हो, चाहे कोई किसी दूसरी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि मुख्य मंत्री महोदय या चीफ सैक्रेटरी के लैवल पर इस मामले को टेक अप किया जाना चाहिये और सभी बड़े ऑफिसर्ज को इस तरह की हिदायतें जारी होनी चाहियें ताकि वे समय पर कमेटियों के पास अपनी रिपोर्टस भेजें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जहां दूसरे प्रदेशों में हमने देखा है कि अपोजीशन के लीडर के लिये, कमेटियों के चेयरमैन के लिये बैठने के लिये अलग से कमरा होता है, उसी तरह से यहां पर भी सरकार को विधानसभा के अन्दर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि मैम्बर्ज, चेयरमैन आपस में बैठकर आपसी विचार विमर्श कर सकें और साथ में उनके काम काज के लिये स्टाफ का प्रोवीजन भी होना चाहिये, टेलीफोन की व्यवस्था भी होनी चाहिये ताकि वे अपने सरकारी काम काज को ऐफीशिऐन्टली निपटा सकें, इस ओर सरकार ध्यान दे।

इससे आगे मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों 26 जनवरी को जो बाक्या करनाल रैस्ट हाउस में हुआ उस बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि यह तय है कि उस रस्ट हाउस में चीफ मिनिस्टर व राज्यपाल महोदय की गाड़ी ही प्रवेश कर सकती है, दूसरी किसी की नहीं लेकिन हमारे मुख्य सचिव महोदय उस दिन वहां पर गये, उनकी गाड़ी को एक एस0पी0 रैंक के आदमी ने दरवाजे पर रोका तो उन्होंने आगे से उस अधिकारी को स्टूपिड फैलो कहा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। वे कोई चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी से ऊपर नहीं हैं। हम मैम्बर्ज से भी उनका रुतबा ऊंचा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में इतना गरूर नहीं होना चाहिये। वे इतने बेलगाम क्यों हो रहे हैं। उनका यह कहना उनके लिये ठीक बात नहीं थी। एक सीनियर आई0पी0एस0 अधिकारी को उन्होंने इस तरह ट्रीट किया, यह उनके लिये शोभा नहीं देता था। इससे यह लगता है जैसे पंडित जिरंजी लाल शर्मा ने कहा था और शायद इसी बात से एक्सपोज हो कर कहा था कि डी0सी0 इनके प्रधान हैं।

श्री अध्यक्ष : इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी बात कहें।

श्री सतबीर सिंह कादियान : ठीक है जी, दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जितने छोटे छोटे अफसर हैं उनके पास भी गाड़ियां हैं और वे सारी पैट्रोल की हैं। मेरा सुझाव है कि डीजल की कारें खरीदी जाएं। मेरे पास भी डीजल की कार है। उसमें कोई अन्तर नहीं है। अन्तर है तो पैट्रोल और डीजल की कीमत में। पैट्रोल बहुत

मंहगा है और डीजल सस्ता है। इसके अलावा अफसरों को गाड़ी खरीदने के लिये लोन भी दिया जाता है। अगर उन्होंने कहीं दूर पर जाना है तो वे अपनी गाड़ी ले कर जाएं और उसका उनको टी0ए0 डी0ए0 दिया जाए। अब उनको ड्राइवर भी देना पड़ता है। आप देखते हैं कि शाम को सारी कारें सरकार की सब्जी मंडी में या शौपिंग सैंटर्ज में मिलेंगी।

**श्री अध्यक्ष :** ये तो आपके टाइम में भी जाती होंगी।

**श्री सतबीर सिंह काद्यिान :** सर, मैं तो हमेशा एम0एल0ए0 ही रहा हूं, मझे ऐसा मौका नहीं मिला। वैसे मैं ऐसे करता भी नहीं हूं। मैं इफको का चेयरमैन था तो बस में आया करता था, कार में नहीं आया करता था। जब कार में कभी आता था तो उसका खर्चा इफको वालों को देना पड़ता था। तो ऐसे कदम उठा कर उन अफसरों के खर्च कम किए जा सकते हैं। लेकिन किस मन्त्री जी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये पास बुक बनाने की बात यहां हुई थी और उस बारे में कानून भी पास हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूं कि पास बुकस बनाने के लिये सरकार कब ध्यान देगी। मैं चाहता हूं कि इसको टाइम बाउंड बना कर तीन महीने में किसानों को पास बुकें मिलनी चाहियें। अब मैं कोआपरेशन के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे शूगर मिल एक जिले में दो दो हैं। जैसे रोहतक में है तो उसका चेयरमैन डी0सी0 होता है। डी0सी0 के पास पहले इतने काम होते हैं कि वह इसके काम को अच्छी तरह से देख नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी जो बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज हैं उनमें से किसी को इसका चेयरमैन लगाया जाए। इसका चेयरमैन कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिये। जितनी भी सहकारी संस्थाएं होती हैं उनमें शेयर होते हैं। चाहे वह मिल्क बैंकस हों, चाहे कोआपरेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैंक हो, कोआपरेटिव बैंक हो या कोआपरेटिव सोसाइटीज हों। इनके लिये कानून की मान्यता यह है कि हर साल इनकी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जानी चाहिये। परन्तु बहिन जी आपके नेतृत्व में इनकी मीटिंग कभी भी नहीं हुई। यदि इनकी मीटिंग नहीं होगी तो उन शेयर होल्डर्ज का क्या होगा जिनके शेयर हरियाणा सरकार के पास पड़े हैं। जब आप मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे तो इसका क्या औचित्य रह गया इस सहकारिता क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप एक बिल ले कर आएं जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं को कानूनी अधिकार होंगे। इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जहां देश में हरित क्रांति आई है वहां दूध की क्रान्ति भी आनी चाहिये। इसलिये पशु पालन विभाग के तहत ज्यादा से ज्यादा पशु हस्पताल खोले जाने चाहियें ताकि पशु धन के लिये उचित व्यवस्था हो सके। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्टस होने चाहिएं। अब मिल्क फार्म के आफिशियल्ज ही दवाइयां प्रैसक्राइब कर सकते हैं जबकि इनके अपने बी0एल0डी0ए0 हैं। उनको दवाइयां प्रैसक्राइब करने का अख्तियार नहीं है।

**पशु पालन राज्य मन्त्री (राव धर्म पाल)** : स्पीकर साहब, जहां तक दूध का सवाल है। हरियाणा प्रदेश में फी आदमी 602 ग्राम दूध हर रोज मिलता है। वह बनावटी दूध नहीं है, असली दूध है। हरियाणा प्रांत में 3715 लाख टन दूध हर रोज उपलब्ध होता है और मेरे मंत्री बनने के बाद दो लाख टन की पैदावार बढ़ी है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा दूध पंजाब में होता है और दूसरे नम्बर पर हरियाणा प्रदेश में होता है।

**श्री सतबीर सिंह कादियान** : मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। पशु पालन विभाग को प्रोत्साहन देना चाहिये। जो वी0एल0डी0ए0 हैं उनको प्रैस्क्रिप्शन के अधिकार दिए जाएं।

इसके अलावा अब मैं परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। जिन प्राइवेट आप्रेटर्ज को सरकार ने जिन जिन सड़कों के रूट परमिट दिए हैं उन सड़कों पर उनकी बसें चल नहीं सकती। इसके अलावा आपने उन पर जो 10 किलोमीटर तक रूट परमिट देने की शर्त लगाई है उसको हटा लेना चाहिये। जैसे आपने पानीपत से गोहाना, पानीपत से सफीदों के रूट परमिट दिए हुए हैं वे सवारियों को ला करके नैशनल हाई वे पर उतार देते हैं उन सवारियों को रोडवेज की बसें बैठाती नहीं हैं। वहां पर न कोई बस अड्डा है और न कोई अड्डा इंचार्ज है। फिर लोग थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर किराए पर करके जाते हैं तो सरकार उन पर अंकुश लगाती है और उनके चालान किए जाते हैं। सरकार इस व्यवस्था में सुधार करे और ज्यादा से ज्यादा बस अड्डे बनवाए।

**प्रो0 राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़)** : स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमाड नं0 15 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि इरीगेशन से संबंधित है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बजट और गवर्नर ऐड्रेस दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण डाकुमैंट्स हैं। गवर्नर ऐड्रेस में तो सरकार ने एस0वाई0एल0 नहर के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है लेकिन बजट में एक सैंटेंस में यह कहा गया है कि एस0वाई0एल0 नहर बनाने के लिये पंजाब से अनुरोध कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि हमारी इस बारे में पूरी कोशिश चल रही है। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिये एस0वाई0एल0 नहर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई दूसरा नहीं है। किसी सरकार के लिये चार साल का समय कोई कम समय नहीं है। यह सरकार आज तक यह नहीं बता सकी कि एस0वाई0एल0 नहर पर कितना काम किया है। इन्होंने उस नहर पर कुछ काम किया हो तो ये बताएं। इन्होंने वहां पर कुछ किया ही नहीं है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जो पहले इनकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने गांव गांव में यह कहा है कि एस0वाई0एल0 नहर का कोई भी काम नहीं किया गया है। दो दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने हमारे बारे में यह कहा था कि आप इस एस0वाई0एल0 नहर के मुद्दे को उलझा रहे हैं। एक ही छत के नीचे हमारा और

पंजाब का अधिवेशन चल रहा है, वे भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। हम इनकी बात सुन कर चुप हो गए। लेकिन स्पीकर साहब, उस नहर को कम्पलीट करवाने की इनकी नीयत नहीं है। इन्होंने उसके बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया। यह इनकी बड़ी भारी विफलता है। इसके अलावा मैं डिमांड नम्बर, 1 पर बोलना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** डिमांड नम्बर 1 विधान सभा की है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं हो सकती।

**प्रो० राम विलास शर्मा:** स्पीकर साहब, मैं तो सुझाव देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** डिमांड नम्बर 1 पर डिस्कशन नहीं की जा सकती। आप और बात कर लें।

**प्रो० राम बिलास शर्मा :** स्पीकर साहब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा मन्त्री मुलाना साहब ने नकल को रोकने का प्रयास किया उनको इस बारे में कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली इस बारे में वे खुद जाने। स्पीकर साहब शिक्षा एक ऐसा अदारा है जो पीढ़ियों का निर्माण करता है। प्रौढ़ शिक्षा के जो उम्मीदवार हैं उनको आप जहां पर वैकेंसीज हैं उनको उन वैकेंसीज पर एडजैस्ट करने के लिये विचार करें। जो संस्कृत के अध्यापक हैं आप उनको भी प्रोत्साहन दें, उनको भी लगाएं और उनको पूरे वेतनमान दें। सरकार ने जिस प्रकार कालेज अध्यापकों को यानि अनुदान प्राप्त कालेजिज के अध्यापकों को जो वेतनमान दिए हैं, उसी प्रकार से स्कूल जो अनुदान प्राप्त हैं, उनके कर्मचारियों को पूरा वेतनमान दें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं भवन तथा सड़कों की डिमांड के बारे में बोलना चाहता हूं। चौधरी अमर सिंह जी वहां पर प्रिवेंसिज कमेटी में जाते हैं। इनके सामने कई बार सवाल उठाया है और ये मानते भी हैं कि जो नैशनल हाई वे जयपुर से दिल्ली का है, उस पर ट्रैफिक का लोड है। इसको चौड़ा करके फौर लेन बनाया जाना चाहिए।

अब मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। पीने के पानी के जो वाटर वर्कस बने हुए हैं, उनमें बिजली के कनैक्शन्ज नहीं है, कनैक्शन्ज दिए जाने चाहिएं। आगे आने वाली गर्मी की कल्पना करें तो क्या हालत उन लोगों की होगी, जरा सोचिए। मैंने एक सवाल के दौरान भी कहा था कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी तीन जगहों से टूटी हुई है। इस पर 45 गांव पड़ते हैं। वहां पर 8—10 गांवों में डेढ़ साल से पानी नहीं जा रहा। मेरी प्रार्थना है कि प्राथमिकता के आधार पर उनको पानी दें।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहते हुए बहन जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारे हस्पताल हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है।

[प्रो० राम बिलास शर्मा]

हमारा हरियाणा छोटा सा है। बहुत कलतार देवी जी से मेरा अनुरोध है कि एक सप्ताह में सारे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाया जा सकता है और अच्छी प्रकार से चैक किया जा सकता है। हैल्थ के बारे में चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं जो हमारा मैडिकल कालेज है, उसकी भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तीन मंजिला एक इमारत जिस पर 1 करोड़ रुपये लागत आई थी। उद्घाटन से पहले ही उसमें क्रैक आ गया। वहां वार्डज में बहुत अधिक अंधेरा रहता है। इतना अधिक अंधेरा रहता है कि कोई टी० बी० का मरीज हो तो वह अंधेरे का खौफ देखकर वैसे ही मर जाए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और सब-डिवीजन लैवल पर जितने भी हास्पिटल हैं, उन सब में एमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो वहां पर इतना तो प्रबन्ध हो कि उस को औपचारिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इन हस्पतालों की न तो लैटरिन्ज ठीक मिलेंगी, न चद्दरें ठीक मिलेंगी और न ही बैड ठीक मिलेंगे। इसलिये इन सब बातों पर मन्त्री महोदय पूरी तरह से ध्यान दें। इसके साथ साथ एक बात कह कर मैं बैठता हूं कि मेरे हल्के में पीने के पानी की 9 योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कृपया इनको प्राथमिकता के आधार पर जन स्वास्थ्य मन्त्री पूरा करवाएं। धन्यवाद।

14.00 बजे

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, कल आपकी इजाजत से मैंने इन द्वारा उठाई गई सारी बातों का जवाब दे दिया था। आपने मेरे को उस समय बोलने का समय दिया जब विरोधी पक्ष और ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं रहा था। जो जवाब मैंने दिया था उससे सारे विपक्ष के भाई भी प्रसन्न हो कर गए थे।

---

## बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट तक और बढ़ा लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

---

# वर्ष 1995-96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

**वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता)** : स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी कल नहीं थे, कोई जरूरी काम होगा इसलिये कल हाउस में नहीं आए, कोई रैली वगैरा करने गए होंगे । चौधरी बंसी लाल जी जब भी बोलते हैं वे मुख्य मन्त्री जी से जवाब मांगते हैं और उनकी बातों का जवाब माननीय मुख्य मन्त्री जी 2-3 बार दे भी चुके हैं और शायद इनकी सेहत का राज भी यही है कि जब तक चौधरी भजन लाल जी से दो-चार कड़कदार बातें न सुन लें इनको चैन नहीं पड़ता। शायद इससे इनका खून बढ़ता है (हंसी) उनकी बातों से शायद इनकी तबीयत फड़क उठती है । अध्यक्ष महोदय, इनकी बातों का जवाब तो वैसे मुख्य मन्त्री जी ने भी दे दिया है लेकिन मैं इनको फिर से एक बात बता देना चाहता हूं ये नोट कर लें । पिछले 4 साल के दौरान इस सरकार ने जो लोन लिया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है । 1991-92 में 23.25 करोड़ रुपये का लोन लिया, 1992-93 में 44.95 करोड़ रुपये, 1993-94 में 55.79 करोड़ रुपये 1994-95 में 54.31 करोड़ रुपये का लोन लिया है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इनको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोन यूं ही नहीं लेते बल्कि लोन के साथ हमें कुछ राशि अनुदान के रूप में भी मिलती है । हम लोन वेस्ट करने के लिये नहीं लेते हैं । जब कोई स्कीम बना कर कोई वायबल प्रोजैक्ट वर्ल्ड बैंक को भेजते हैं और वे उस प्रोजैक्ट को जस्टिफाईड समझते हैं तभी लोन देने के लिये वे सहमत होते हैं । जब उन को यह पूरा यकीन होता है कि स्कीम वायबल है और लोगों के हित में है केवल तनख्वाह या दूसरे एक्सपैंडिचर के लिये नहीं है बल्कि सालों साल उससे लोगों का भला होगा, जनता का हित होगा तभी प्रोजैक्ट वे सैंक्शन करते हैं लोन के साथ सबसिडी भी होती है । इस लोन में 70 प्रतिशत हमें वापिस करना है और बाकी 30 प्रतिशत की ग्रांट मिलती है । अध्यक्ष महोदय 1991-92 के लिये 23.75 करोड़ का जो लोन था उसमें 10.18 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मिली है । इसकी अलग अलग स्कीम्ज हैं । कैटेगरीवाईज लोन मिलता है । जिन स्कीमों पर लोन मिला है वह भी मैं इनको बता देता हूं । पहली हरियाणा इरिगेशन सैकण्ड प्रोजैक्ट है, दूसरी नैशनल एग्रीकल्चर एक्सटैंशन प्रोजैक्ट है, तीसरी इन्टैग्रेटिड वाटर शैड कण्डी ऐरिया प्रोजैक्ट है, चौथी कोमन लैण्ड इन अरावली हिल्ज, पांचवीं नेशनल वाटर मैनेजमैंट प्रोजैक्ट, छठी हरियाणा टैक्नीकल एजुकेशन प्रोजैक्ट, सातवीं ई0 ई0 सी0 तथा 8वीं हरियाणा ह्यूमन इम्प्रूवमैंट प्रोजैक्ट, इन आठ प्रोजैक्टस के तहत हमने लोन लिया है जिसके फिगर्ज मैंने पहले बता दिये हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं कि जो वाटर शैड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसको कौन सा डिपार्टमेंट करेगा ? (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : यह स्कीम इरिगेशन, एग्रीकल्चर और फोरेस्ट यानि इसमें 2—3 डिपार्टमेंट इन्वाल्वड हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या शिवालिक बोर्ड भी इसमें शामिल है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवालिक बोर्ड वर्ल्ड बैंक के अधीन नहीं है । (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको फिर एक मिनट के लिये इन्ट्रप्ट कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, घग्गर टांगरी भारकण्डा पर बांध बनाने के लिये जो प्रोग्राम था, उसके बारे एक्सपर्ट इंजीनियर्ज ने यह कह दिया था कि इसमें सिल्ट इतनी ज्यादा आएगी कि अगले साल दो साल में वह बराबर हो जाएगी इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा और यह वायेबल नहीं है । इस प्रोजैक्ट से अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों के एरियाज को बैनिफिट हो सकता है । मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले तो यह प्रोजैक्ट वायेबल नहीं था, क्या कण्डी ऐरिया वाटर शैड प्रोग्राम के तहत यह वायेबल हो जाएगा ? मैं मुख्य मन्त्री जी से भी कहना चाहूंगा कि वाटर शैड प्रोग्राम पूरी होने पर क्या ऐसी टैक्नोलोजी सर्वे करवाई जा सकती है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है हरियाणा इतने महंगे लोन ले रहा है । (विघ्न)

**Ch. Birender Singh** : Speaker, Sir do you think that my question is irrelevant as the Minister is not replying to my question. This is a vital information and the Minister should come out with this information as to how much loan has been taken from the World Bank ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के अपने रिसोर्सिज हैं, और हरियाणा का लोन एक दिन भी लेट नहीं हुआ है, हमने पूरा इन्ट्रस्ट दिया है । अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारी बाकियों से बहुत ही बेहतर पोजीशन है । हम किसी प्रकार का ऐसा लोन नहीं लेते हैं जिसे हरियाणा सरकार नहीं दे सके । यह तो वायेबल प्रैक्टीस है और वर्ल्ड बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देता है । अध्यक्ष महोदय इस बारे में इन्हें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मन्त्री जी ने बताया कि हमने फलां फलां साल में इतना इतना लोन लिया । मैंने जो सवाल पूछा है वह यह

है कि वर्ल्ड बैंक से हमने किस काम के लिये कितना कर्जा लिया है और कितना लेने जा रहे हैं। इन्होंने तो दो तीन साल का बता दिया। जो एग्रीमैन्ट आगे का और पीछे का कर रखा है उसका टोटल मिला कर कितना होता है। उसका सालाना ब्याज कितना बनेगा और इन्होंने जिन स्कीमों का नाम लिया है कि हम वर्ल्ड बैंक से इन स्कीमों के लिये पैसा ले रहे हैं। ये बातें जानने का अधिकार सदन को भी है कि वे क्या क्या स्कीम्ज हैं, इनकी डिटेल सदन के मैम्बरों को भी मिलनी चाहिए ये सदन के पटल पर रख दें।

**श्री मांगे राम गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, यह ऑफिशियल रिकार्ड है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये इस तरह से मांग सकते हैं यह हम इनको दे भी सकते हैं हम इनको सदन की पटल पर भी रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात चौधरी बंसी लाल जी ने कही वैसे तो मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया था और मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। जब बंसी लाल जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त हरियाणा के किसी भी टीचर का तबादला नहीं किया जाता था और कहते थे कि कोई भी मास्टर अपने गांव के 20 किलोमीटर नजदीक नहीं रह सकता। तो मास्टर जब स्कूल अपनी साईकल पर जाते थे तो वे अपनी साईकल पर थपकी लगाते थे कि चल बेटा बंसी 20 मील की रफ्तार से। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जितनी सुविधा जितने पे स्केल के रिवीजन जितने ए0 जी0 एस0 के केस थे और जितने बोनस के केस थे, वे जितने इस सरकार ने दिए हैं, मैं समझता हूं उतने तो पिछली सरकार ने दिए ही नहीं हैं। कोई भी ज्यादती आज कर्मचारियों के साथ नहीं है। इसी तरह से चौहान साहब ने अधिकारियों की बात कह दी। (विघ्न) मैं तो इनके बारे में नहीं कहना चाहता था लेकिन मुख्य मन्त्री ने जैसा कल कहा था कि बिटोड़े में से गोस्से ही निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा। जब बिटोड़े में गोस्से रखते हैं तो गिनती नहीं होती और जब उसमें रखते हैं तब भी गिनती नहीं होती लेकिन खजाने में तो एक एक रुपया गिनकर रखा जाता है और गिनकर ही निकाला जाता है। (विघ्न) खजाने में गिनती का पूरे हिसाब से पैसा होता है यही कारण है जैसे मैंने कल भी अपने जवाब में बताया था कि कोई भी टैक्स हरियाणा सरकार ने नहीं लगाया है। आज आप हरियाणा के किसी भी वर्ग, से पूछो चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो कर्मचारी हो यानी सब को ही सरकार ने कोई न कोई रिलीफ दी है और सब इस बात को मानते भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है।

**प्रो0 शेर सिंह चौहान** : जो महिला के प्लाट पर कब्जा हुआ है या जो पंजाबी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में भी बता दो।

श्री मांगे राम गुप्ता : पंजाबी महिला से आपका क्या लेना देना है ? (विघ्न) जींद में से होकर निकल जाना सारा पता लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज यह कहना कि हरियाणा सरकार की इकोनोमी नहीं है, खर्चे पर कंट्रोल नहीं है, और सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, ठीक नहीं है क्योंकि आज तक भी हरियाणा की इकोनोमी का इससे अच्छा कंट्रोल नहीं हुआ है । हमने 6 करोड़ रुपये के बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया है और सभी वर्गों को सुविधा देने के बाद सिर्फ 15 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । इसके अलावा इन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा कि वे गाड़ियों का मिसयूज करते हैं । सर, बाकायदा कायदे कानून इस बारे में बने हुए हैं जिस अधिकारी को कायदे कानून से गाड़ी मिलती है, दो सौ रुपये महीने के हिसाब से उसकी तनख्वाह में से काटे जाते हैं और अगर कोई अधिकारी एक महीने में चार सौ कि0 मी0 से ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करता है तो उससे दो रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं और वह तनख्वाह में से कट जाते हैं। (विघ्न) मैं आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव हैं जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यह सरकार सदन को पूरे विश्वास के साथ कहती है कि हम कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे। (विघ्न) हमने किसानों को जो भी सुविधाएं दी हैं, उसके लिए तो आपने सरकार का धन्यवाद किया नहीं है । अब आप इस तरह की बात करते हो। पास बुक भी हमने बना रखी हैं। अध्यक्ष महोदय बहुत सी बातों पर यहां पर चर्चा हुई और उन सभी बातों का मुख्यमन्त्री जी द्वारा और जो मेरे विभाग से संबंधित थी का मेरे द्वारा उत्तर दिया गया और हर प्रकार की तसल्ली करने की कोशिश की गयी है । इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप डिमांडवाइज इन डिमांड पर मत करा लीजिए और इनको पास करा दीजिए ।

---

## बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

---

## वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

**Mr. Speaker** : Hon'ble members now voting on demands on the Budget for the year 1995-96 will take place.

First, I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demands to the vote of the House.

**Demand No. 1**

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,94,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 1—Vidhan Sabha.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 2**

**Mr. Speaker** : Now I put the cut motion on Demand No. 2 given by Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan M.L.As. to the vote of the House-

Question is—

That Demand No. 2 of Rs.61,94,94,000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 61,94,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 2—General Administration.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 3**

**Mr. Speaker** : Now I put the cut motion on Demand No. 3 given by Sarvshri Bansi Lal and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 3 of Rs. 1,92,39,12,000 on account of Home be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,87,44,12,000 for revenue expenditure and Rs. 4,95,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 3—Home.*

*The motion was carried.*

[Mr. Speaker]

**Demand No. 4**

**Mr. Speaker :** Question is

That a sum not exceeding Rs.26,24,83,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 4—Revenue*.

*The motion was carried.*

**Demand No. 5**

**Mr. Speaker :** Now I put the cut motion on Demand No. 5, given by Sarvshri Ram Bhajan and Om Parkash Beri M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 5 of Rs. 16,81,11,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker :** Question is—

That a sum not exceeding Rs.16,81,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 5—Excise & Taxation*.

*The motion was carried.*

**Demand No. 6**

**Mr. Speaker :** Now I put cut motion on Demand No. 6, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 6 of Rs.1,57,85,85,000 on account of Finance be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker :** Question is—

That a sum not exceeding Rs.1,57,85,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 6—Finance*.

*The motion was carried.*

**Demand No. 7**

**Mr. Speaker :** Question is—

That a sum not exceeding Rs. 16,68,78,70,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 7—Other Administrative Service*.

*The motion was carried.*

## Demand No. 8

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 8, given by Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 8 of Rs. 1,90,81,92,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 97,85,59,000 for revenue expenditure and Rs. 92,96,33,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 8—Buildings & Roads*.

*The motion was carried.*

## Demand No. 9

**Mr. Speaker** : Now, I put cut motion on Demand No. 9 given by Sarvshri Chhattar Singh Chauhan and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 9 of Rs. 5,45,56,03,000 on account of Education be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,45,56,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 9—Education*.

*The motion was carried.*

## Demand No. 10

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 10, given by Sarvshri Bansi Lal and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 10 of Rs. 3,30,02,06,000 on account of Medical and Public Health be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,53,96,31,000 for revenue expenditure and Rs. 76,05,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No.* 10—*Medical & Public Health.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 11**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 11, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 11 of Rs. 17,39,91,000 on account of Urban Development be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 17,39,91,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 11—Urban Development.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 12**

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 35,47,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No.* 12—*Labour & Employment.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 13**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 13 given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

That Demand No. 13 of Rs. 2,39,41,12,000 on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,36,83,85,000 for revenue expenditure and Rs. 2,57,27,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 14**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 14 given by Shri Bansi Lal, M.L.A. to the vote of the House.

That Demand No. 14 of Rs. 3,75,76,54,000 on account of Food & Supplies be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 8,76,38,000 for revenue expenditure and Rs. 3,67,00,16,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 14—Food & Supplies.*

*The moton was carried.*

**Demand No. 15**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 15 given by Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

That Demand No. 15 of Rs. 6,37,09,20,000 on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,55,82,20,000 for revenue expenditure and Rs. 1,81,27,00,000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 15—Irrigation.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 16**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 16 given by Shri Bansi Lal, M.L.A., to the vote of the House.

That Demand No. 16 of Rs. 69,61 06,000 on account of Industries be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 33,31,49,000 for revenue expenditure and Rs. 36,29,57,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 16—Industries.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 17**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 17 given by Sarvshri Bansi Lal, Chhattar Singh Chauhan and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

That Demand No. 17 of Rs. 1,41,39,11,000 on account of Agriculture be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,41,39,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 17—Agriculture.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 18**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 18, given by Shri Om Parkash Beri, M.L.A., to the vote of the House.

That Demand No. 18 of Rs. 42,61,30,000 on account of Animal Husbandry be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 42,61,19,000 for revenue expenditure and Rs. 11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 18—Animal Husbandry.*

*The motion was carried.*

**Demand Nos. 19 to 21**

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,68,50,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 19—Fisheries.*

That a sum not exceeding Rs. 56,39,52,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 20—Forest.*

That a sum not exceeding Rs. 69,35,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 21—Community Development.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 22**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 22 given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A., to the vote of the House.

That Demand No. 22 of Rs. 33,13,38,000 on account of Cooperation be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 18,63,29,000 for revenue expenditure and Rs. 14,50,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 22—Co-operation.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 23**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 23 given by Shri Om Parkash Beri and Shri Bansi Lal, M.L.As, to the vote of the House.

That Demand No. 23 of Rs. 3,35,23,26,000 on account of Transport be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,93,89,56,000 for revenue expenditure and Rs. 42,33,70,000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No. 23—Transport.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 24**

**Mr. Speaker** : Now I put cut motion on Demand No. 24 given by Shri Bansi Lal, M.L.A. to the vote of the House.

That Demand No. 24 of Rs. 3,79,00,000 on account of Toursim be reduced by Rs. 1/-.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker :** Question is—

That a sum not exceeding Rs. 27,00,000 for revenue expenditure and Rs. 3,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year, 1995-96 in respect of charges under *Demand No.* 24—*Tourism.*

*The motion was carried.*

**Demand No. 25**

**Mr. Speaker :** Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,63,53,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under *Demand No.* 25—*Loans & Advances by State Government.*

*The motion was carried.*

---

## बिल्ज़—

(i) पंडित भगवत दयाल शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, रोहतक (अध्यापक सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1995

**Mr. Speaker :** Now, the Technical Education Minister will introduce the Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, 1995 and move the motion for its consideration.

**Technical Education Minister** (Rao Inderjit Singh) : Sir, I beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Question is—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clause 2**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Technical Education Minister will move that the Bill be passed.

**Technical Education Minister** (Rao Inderjit Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

## (2) हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 1995

**Mr. Speaker :** Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

**Irrigation Minister** (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker** : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clause 2**

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 3**

**Mr. Speaker** : Question is—

That clause 3 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker** : Question is—

That clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

**Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

---

## बैठक का समय बढ़ाना

**Mr. Speaker :** Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 10 minutes?

**Voices :** Yes.

**Mr. Speaker :** The time of the sitting is extended by 10 minutes.

---

## बिल्ज (पुनरारम्भ)

### (3) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1995

**Mr. Speaker :** Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

**Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) :** Sir, I introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1995.

I also move—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clauses 2 to 7**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is—

That clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

**Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gamba) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill be passed.

**प्रो० राम विलास शर्मा:** स्पीकर साहब, वैसे तो हरियाणा में एक नगर निगम बनी है उसके चेयरमैन के चुनाव का मामला भी हाई कोर्ट तक गया और इलैक्शन के तीन महीने बाद तक चेयरमैन का चुनाव नहीं करा सके। इसलिये यह बिल बिना चर्चा के जल्द बाजी में पास न करवाएं। जो पंचायती राज विधेयक है, उसके अन्दर नगरपालिका के प्रैजीडैंट की टैन्योर एक साल रखी थी, अब इस बिल में 5 साल की रखी है। चेयरमैन के लिये और वाईस चेयरमैन के लिए, इस बारे में मेरा कहना है कि बाकी जगह ऐसा है कि वाईस चेयरमैन का चुनाव एक साल के लिए होता है अत: मेरा सुझाव है कि हमारे यहां पर भी वाईस चेयरमैन का चुनाव एक साल के लिए होना चाहिए।

**चौधरी धर्मबीर गाबा :** पांच साल का इसलिए किया है ताकि हर साल चुनाव के चक्कर में न पड़ कर, काम समूचली चलता रहे और दूसरे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पंचायती राज एक्ट में भी यही प्रोवीजन है, इसलिये हम यह अमैंडमैंट लाये हैं।

**श्री अध्यक्ष :** म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान के लिए बैकवर्ड क्लास की औरतों का कोटा बाद में तय किया, अगर पहले करते तो ठीक रहता, यह आपकी गलती रही है।

Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

## (4) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995

**Mr. Speaker :** Now the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

**Minister of State for Local Government** (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clauses 2 to 7**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

**Minister of State for Local Government** (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

**(5) पंजाब भू-दान यज्ञ (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1995**

**Mr. Speaker :** Now, the Irrigation Minister will introduce the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

**Irrigaton Minister** (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab Bhulan Yagna (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker** : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clause 2**

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The moton was carried.*

**Mr. Speaker** : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

**Irrigation Minister** (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

---

## बैठक का समय बढ़ाना

**Mr. Speaker** : Is it the sense of the House that the time of the House be extended by 5 minutes.

**Voices** : Yes.

**Mr. Speaker** : Time is extended by 5 minutes.

## बिल्ज—

## (पुनरारम्भ)

### (6) हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1995

**Mr. Speaker** : Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

**Irrigation Minister** (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker** : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clause 2**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

**Irrigation Minister** (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill. be Passed

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill be passed.

**प्रो० राम विलास शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो उद्देश्य बताए गए हैं, उसकी लैंग्वेज पर मुझे ऐतराज है। इसमें लिखा है "बेईमान व्यापारी" यह "कर की चोरी" या "अनियमितता" लिखें। दूसरे इसमें इन्होंने 10 की जगह 15 प्रतिशत किया है इससे टैक्स इवेजन नहीं रुकेगा, इसमें यूनिफोरमिटी लाएं। जैसे डी नेचरड सिपरिट है; उसका टैक्स चंडीगढ़ में 50 पैसे है और कालका में 6 रुपये प्रति लिटर है। एडजेसैंट स्टेट्स के साथ टैक्स में यूनिफोरमिटी लाएं और व्यापारियों के लिये जो "बेईमान" शब्द लिखा है, उसको बदला जाना चाहिए।

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 24th March, 1995.)

*2.14 hrs.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

26841/H.V.S.—H.G.P., Chd.